

प्रकाशक -

प्रो० वेदव्यास

साहित्य भवन

हस्पताल रोड, लाहौर

मुद्रक—

श्रीकृष्ण दीक्षित

चाम्बे मशीन प्रेस

गोहनलाल रोड, लाहौर

भारतवर्ष का इतिहास (दूसरा भाग)

(अंग्रेज़ी-युग तथा वर्तमान युग)

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ
१ प्रारम्भिक यूरोपियन व्यापारी	५
२ अंग्रेज़ों और फ्रांसिसियों की प्रतिस्पर्धा	१३
३ बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की वृद्धि	२७
४ वारेन हेस्टिंग्स	५७
५ लार्ड कानवालिस	६७
६ लार्ड वैलजली	७७
७ सर जार्ज बारलो और लार्ड मिटो	८८
८ मार्किस आफ हेस्टिंग्स	९६
९ लार्ड विलियम बेंटिक	१०८
१० ऑवलैड और ऐलनबरो	११४
११ लार्ड हार्डिंग	१२२
१२ लार्ड डलहौज़ी	१२७
१३ लार्ड कैनिंग	१३८
१४ लार्ड कैनिंग से लार्ड नार्थमूक तक	१४६
१५ लार्ड लिटन और लार्ड रिपन	१५५
१६ लार्ड डफ्रिन, लार्ड लेंसडाउन और लार्ड एलिंग	१६५
१७ लार्ड फर्ज़न और लार्ड मिण्टो	१७२
१८ लार्ड चैम्सफोर्ड लार्ड हार्डिंग और लार्ड इरविन	१८७
१९ लार्ड विलिंगटन और लार्ड लिन्लिथगो	२०२
२० भारत की शासन व्यवस्था	२०८

भारतवर्ष का इतिहास

दूसरा भाग

(अंग्रेज़ी युग तथा वर्तमान युग)

प्रथम अध्याय

प्रारम्भिक यूरोपियन व्यापारी

भारत को अनेक बार जीता गया । आर्यों ने उसे मूल निवासियों से लिया । मुसल्मानों ने आर्यों को पराजित किया; अपनी दारी पर वे भी मराठों से परास्त किए गए, और सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में एक नई जाति ने प्रवेश किया जो भविष्य में भारत की भाग्य-विधात्री बननेवाली थी ।

नवीन जाति
का आगमन

अन्तरीप-मार्ग—यद्यपि सोलहवीं शताब्दी से पहले यूरोपियन भारत के विषय में बहुत ही कम जानते थे, पर इस देश का माल भूमध्यसागर (Mediterranean) की प्रधान प्रधान मंडियों में बहुत पहले पहुँच चुका था । ईसा के जन्म से पहले ही से काली मिर्च और गरम मसाले निकटवर्ती पूर्वोप नगरों दैवीलोन, तीनेवाह और सिडौन को जाते

प्राचीन काल में
यूरोप और भारत
का परस्पर
व्यापार

थे, जहां से वे और वाज़ारों में भेज दिए जाते थे ।

रोम-साम्राज्य के पतन के बाद वेनिस नगर के रहने वालों ने एक प्रजा-तन्त्र राज्य स्थापित कर लिया और भारत-यूरोपियन व्यापार पर पूर्ण अधिकार कर लिया । पूर्वीय देशों की वस्तुएँ भारत से वेनिस और जनेवा को, जो उस समय प्रधान सामुद्रिक शहर थे, बराबर जाती रहती थीं । वहां से वे यूरोप के अन्य बड़े बड़े नगरों में भेज दी जाती थीं, जहां उनकी ऊँचे दामों पर खूब बिक्री होती थी । प्रधान सामुद्रिक मार्ग लाल सागर और भूमध्यसागर से होकर जाता था । लाल सागर के रास्ते के मालिक अरब निवासी थे और भूमध्यसागर के इटली के निवासी । मिश्र पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यह मार्ग संकट-पूर्ण हो गया । अब यूरोपियन लोग भारत को जाने वाले किसी ऐसे मार्ग को खोज लिये के इच्छुक थे, जिसके द्वारा वे भी इस लाभकारी व्यापार में भाग ले सकें । अन्त में पुर्तगीज़ों को अफ्रीका के नीचे से होकर जानेवाले मार्ग का पता लग गया । सन् १४८८ में वास्को डी गामा ने आशा-अन्तरीप (Cape of Good Hope)

वास्को डी
गामा

का चक्र काटा और मालाबार तट पर कदम रखवा ।

भारत में पुर्तगीज़—आरम्भ में तो पुर्तगीज़ों को अरब लोगों के हाथों बड़े बड़े उठाने पड़े, परन्तु बाद में फ्रेसिस्को ऐल्मीडा नामक प्रथम पुर्तगीज़ वायसराय ने उन्हें हराकर दामन और दियू से भगा दिया ।

ऐल्मीडा

इससे सामुद्रिक मार्ग पर उनका एकछत्रराज्य हो गया और यूरोप भारत के व्यापार के वही पूरे मालिक होगए। उन्होंने इस अधिकार को सारी सोलहवीं शताब्दी में घनाए रक्खा और अपने राज्य का भी बहुत कुछ विस्तार किया।

अल्बुकुर्क

ऐल्मीडा के बाद अल्बुकुर्क वायसराय बनाया गया और उसने गोआ पर अधिकार किया जो शीघ्र ही एक अच्छा बड़ा शहर बन गया। अल्बुकुर्क पूर्व में पुर्तगाल साम्राज्य का स्थापक कहा जा सकता है, क्योंकि उसने आर्मुज और समुद्र के अन्य बहुत से स्थानों पर भी अधिकार किया था। सन् १५१५ में उसकी पदच्युती और मृत्यु के बाद भी पुर्तगाल के पूर्विय साम्राज्य की सीमा में विस्तार होता रहा और सोलहवीं शताब्दी की तबत पुर्तगाल राज्य की सीमा समुद्र तट पर १२०० मील तक व्याप्त हो गई।

परन्तु सत्रहवीं सदी के प्रारम्भ होते ही पुर्तगालियों का सौभाग्य-सूर्य अस्त होना आरम्भ हो चला। उन्होंने भारतीय व्यापार से एक सदी तक खूब लाभ उठाया। पर भारत की सम्पत्ति की कथा सुनकर डचों, अंग्रेजों और फ्रांसिसियों के मुंह में पानी भर आया।

पुर्तगालियों का पतन

भारत के निवासियों ने इन नए यूरोपियनों के आगमन का स्वागत किया क्योंकि अब पुर्तगालियों से हिन्दू और मुसलमान दोनों ही घृणा करने लगे थे। वे शान्ति-पूर्वक व्यापार करना तो जानते ही नहीं थे, साथ ही वे सामुद्रिक लूटमार से भी धन प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त वे यहां के निवासियों को जबरदस्ती ईसाई बनाते थे

दलपूर्वक धर्म परिवर्तन

जिससे सब ओर असन्तोष फैल गया था ।

सन् १५८० में पुर्तगाल और स्पेन का राज्य एक हो गया। स्पेन के अमेरिका वाले विस्तृत उपनिवेशों के मुकाबले

स्पेन और पुर्तगाल का सम्मिलन
पुर्तगाल का पूर्वी साम्राज्य चुद्र-सा
अतः उसे तुच्छ दृष्टि से देखा जाने लगा

उस समय स्पेन, अंग्रेजों और डचों से घेरा
कर रहा था, अतः एक राज्य होजाने के कारण पुर्तगाल को

इस युद्ध में भाग लेना पड़ा । इस लड़ाई से उसे बड़ी आर्थिक हानि
उठानी पड़ी; इसलिए वह अपने प्रत्येक दूर-देशस्य अधिकार

वनाए न रख सका और अपने से अधिक
पुर्तगीजों से अधिक बलवान सैन्य शक्तिवालों के आगे मुक
निपुण नाविक जातियां के लिए बाधित हो गया । धीरे धीरे पुर्तगीज

के पास से सारे प्रदेश निकल गए, हाँ, गोआ, दामन, और दि
बाक्री रह गए, जो अब तक उन्हीं के पास हैं ।

डच—पुर्तगीजों को सत्रहवीं सदी में विशेषकर शुरू क
आधी शताब्दी में डचों ने, जो उस समय सामुद्रिक-शक्ति
बहुत बढ़े चढ़े थे, इस क्षेत्र से निकाल बाहर कर दिया । डचों
नीदरलैंड में सन् १६०२ में सम्मिलित ईस्ट इण्डिया कम्पनी
कायम की और जावा के बेटेविया नगर को अपना पूर्वीय केन्द्र
स्थल बनाया । वे गरम मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना
चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत पर अधिकार करने के स्थान पर
मलाया द्वीपसमूह पर कब्जा किया और वहां से अन्य व्यापारियों

मसालों के द्वीपों
पर प्रभुत्व

के व्यापार को नष्ट कर इन गरम मसाले वाले द्वीपों पर अपना एकाधिकार कायम कर लिया। भारत में उनका प्रधान केन्द्रस्थल बंगाल का चिनसुरा नगर था। परन्तु यहाँ अंग्रेजों की शक्ति की बढ़ती के साथ साथ वे अशक्त होते गए। फ्रांस और स्पेन के साथ लगातार युद्ध करने से हालैण्ड की हालत बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए इंगलैण्ड ने उसके सामुद्रिक प्रभुत्व को नष्ट कर दिया। भारत में डचों का जो प्रधान केन्द्रस्थल था, उस पर फ्रेंच लोगो ने कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी ही भारत में प्रधान प्रतिस्पर्धी रह गए। पर मलाया द्वीपों पर डच लोगो का पहले की तरह ही अधिकार बना रहा।

पतन

फ्रांसीसी—पूर्व के व्यापार में भाग लेने के लिये फ्रांस ने शुरू में जो प्रयत्न किए वे बेकार साबित हुए। सन् १६६४ में एक फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी कायम की गई और फ्रांस से एक सेना भेजी गई जो कोचीन में उतरी। इसकी मदद से सूरत में एक फ्रैंक्टरी कायम की गई। एक दूसरी फ्रैंक्टरी मसुलीपट्टम में खोली गई। पांडीचेरी का स्थान बीजापुर के बाद साह से खरोद लिया गया और वह शीघ्र ही एक प्रसिद्ध शहर बन गया। अन्य फ्रेंच स्थान बंगाल में बन्दरनगर और मलाबार तट पर माही थे। ड्यूमा (Dumas) ने जो सन् १७३५ से १७४१ तक फ्रेंच राज्य का गवर्नर रहा, भारतीय नरेशों से मेल करके फ्रेंच प्रभाव बढ़ाना चाहा। फ्रांसीसियों का इसके बाद का इतिहास अगले परिच्छेद में दिया जाएगा।

अंग्रेज़-ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रारम्भिक इतिहास—
 भारत में जिन अंगरेज़ों ने सबसे पहले पैर रक्खा था, उनमें एक
 टामस स्टीफेन्स भी था, जो सन् १५७६ में
 स्टिफेन्स के
 पत्र
 गोआ में उतरा था। उसने अपने पिता को
 अनेक पत्र लिखे, जिनमें उसने देश के उप-
 जाऊपन और पुर्तगीज़ों के व्यापार का विस्तार से वर्णन किया।
 उसके इन पत्रों को पढ़कर अंगरेज़ों में पूर्व के साथ व्यापार करने
 के लिए बड़ा चाव पैदा हो गया। अंगरेज़ों ने सन् १५८८ में
 स्पैनिश आर्मेडा पर विजय प्राप्त कर ही ली
 ईस्ट इण्डिया
 कम्पनी का
 स्थापना
 थी, अतः वे और भी अधिक उत्साहित हो
 गए। सन् १५६६ में अंगरेज़ व्यापारियों की
 एक कम्पनी ने भारत और आसपास के द्वीपों
 से व्यापार करने की अनुमति के लिए महारानी एलिज़ाबेथ से
 प्रार्थना की। सन् १६०० में अनुमति मिल गई और कम्पनी
 बन गई।

पहले दो बार गरम मसालों के द्वीपों की ओर यात्रा की गई।
 अंगरेज़ों ने वहाँ कुछ व्यापार भी किया, पर डच वहाँ बहुत शक्ति-
 शाली बने हुए थे। इस द्वीप समूह से निकाले जाकर अंग्रेज़ों ने
 भारत में एकत्र होने का निश्चय किया, जहाँ उनकी किस्मत जागने
 वाली थी। कम्पनी की तीसरी सामुद्रिक यात्रा में एक जहाज़
 सूरत पहुँचा। हाकिन्स इसी जहाज़ से उतरा था ' वह जहांगीर के
 दरबार में गया और वहाँ से सूरत में रहने की अनुमति मांग
 लाया। इस तरह अंगरेज़ों को खड़े होने भर को जगह मिल गई।

पुर्तगीजों में अब किसी तरह की ताकत नहीं रही थी अतः उन्होंने अंगरेजों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। अंगरेजों ने पुर्तगीजों को सूरत के निकट स्वाली (Swally) के पास हरा भी दिया था। इस विजय से अंगरेजों को सूरत में कोठी बनाने का फरमान मिल गया। सन १६२२ में अंगरेजों और फारसियों की सम्मिलित सेनाओं के हाथों में आमुज के आ जाने से पुर्तगाल के पतन में रही सही कसर भी पूरी हो गई। अब अंगरेजों को उस से किसी तरह का भय न था। सन १६१५ में सर टामस रो एक राजदूत की हैसियत से भारत में आया और अपने देशवासियों के लिये कुछ व्यापारिक सुविधाएँ और रिश्वायते प्राप्त करने में सफल हुआ। शाहजहाँ ने बोटन नामक एक अंगरेज सज्जन की सेवा से प्रसन्न होकर उससे कोई इनाम मांगने को कहा, इस पर उसने अपने स्वदेश बन्धुओं के लिये बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने और कोठियाँ बनाने की अनुमति मांगी। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हुगली शहर में एक कोठी कायम हो गई। सन १६६१ में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई के द्वीप को अपनी पत्नी कैथेराइन आफ़ ब्रेगेंजा के दहेज के रूप में प्राप्त किया और उसे दस पौंड प्रति वर्ष के नाममात्र के किराये पर कम्पनी को सौंप दिया। इससे पहले कम्पनी ने मद्रास का स्थान भी चन्द्रगिरि के राजा से खरीद लिया था और उस में सेंट जार्ज नाम की एक किलेबन्दी

पुर्तगीजों के साथ संघर्ष

सर टामस रो

बोटन का जाति प्रेम

बम्बई का द्वीप

फोर्ट सेंट जार्ज

वाली कोठी बनाने की अनुमति भी प्राप्त करती थी। सन १६६० में अङ्गरेजों ने हुगली नदी के पूर्वीय दलदली वाले किनारे पर,

जहाँ आजकल कलकत्ता शहर बसा है, एक फोर्ट विलियम कोठी बनवाई, जो फोर्ट विलियम के नाम से

मशहूर है। विलियम हैमिल्टन ने, जो अंगरेज डाक्टर था, बाद-शाह फ़रख़सियार की चिकित्सा करने के पुरस्कार में अपने देश-वासियों के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त करली थीं।

सम्मिलित ईस्ट इण्डिया कम्पनी— ईस्ट इण्डिया

कम्पनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिलने से

प्रति द्वंद्विनी

कम्पनियों का

सम्मिलन

इङ्गलैण्ड में विरोध उत्पन्न हुआ और कुछ

अन्य लोगों ने भी भारत से व्यापार करना

आरम्भ किया। सन १६६८ में एक दूसरी

कम्पनी बनाई गई। दोनों कम्पनियाँ दस

वर्षों की हानिकर प्रतिस्पर्धा के बाद सन् १७०८ में मिला ली गई।

इस प्रकार संयुक्त कम्पनी भारत में अपने कार्यों और अपने अधिकारों की रक्षा करने में पूर्ण स्वतन्त्र हो गई।

प्रश्न

१. सोलहवीं शताब्दी में भारत में पुर्तगीज़ राज्य स्थापित होने का संक्षिप्त विवरण लिखो। पुर्तगीज़ों के पतन का कारण भी बताओ।

२. सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक ईस्ट इंडिया कम्पनी की चढ़ती का संक्षिप्त विवरण लिखो।

३. निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखो—

वास्को डी गामा, अल्वकुर्क, गोआ, चंद्रनगर, सर टामस रो, बम्बई।

दूसरा अध्याय

अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धा करनाटक के युद्ध

दक्षिण में ब्रिटिश शक्ति का उत्थान

इन्ही दिनों फ्रान्स से डूप्ले (Dupleix) आया । यह बड़ा चतुर और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था । इस समय तक गोलकों के हाथ से सारी शक्ति जा चुकी थी । दक्षिण में सूबेदार आसफ़जाह, ने जो

दक्षिण निज़ामुल्मुल्क के नाम से भी प्रसिद्ध था, मुग़लों को अधीनता का जुआ अपने कंधों से उतार कर फेंक दिया था ।

करनाटक में भी एक शक्तिशाली राज्य कायम हो चुका था । बाजीराव प्रथम की अधीनता में मराठा शक्ति जोर पकड़ रही थी और दक्षिण पर पूरा अधिकार कायम करने के लिए निज़ाम और मराठों में आए दिन झगड़े होते रहते थे । ऐसी दशा

देख कर डूप्ले ने फ्रेंच साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखा । उसने सोचा कि देशी शासकों के काम में दखल देने से उसे लाभ पहुँचेगा ।

डूप्ले को अब-
सर मिला

क्योंकि इस के द्वारा उसको फ्रांसीसियों का गौरव बढ़ाने के अनेक अवसर मिलेंगे। वह हिन्दुस्तानी सिपाहियों को भी सैनिक शिक्षा दे रहा था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि यदि उन्हें उत्तम शिक्षा दी जाय और उनका योग्य यूरोपियन सेनापतियों द्वारा संचालन किया जाय, तो वह सेना भी यूरोपियन सेना से कम उपयोगी न रहेगी।

पुर्तगाल और डच इस समय तक पिछड़ चुके थे। ब्रिटेन का घोर प्रतिद्वन्दी अब फ्रांस ही था। दोनों ही भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करना चाहते थे, किन्तु इतना बड़ा देश होते हुए भी भारत दोनों को स्थान नहीं दे सकता था। या तो इङ्ग्लैंड को अपनी नीति छोड़नी पड़ती, या फ्रांस को; अथवा इन दोनों प्रतिस्पर्धियों को आपस के उस संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ता, जो अनिवार्य प्रतीत होता था। हम आगे चल कर देखेंगे कि अन्त में युद्ध ही आवश्यक होगया।

करनाटक की पहली लड़ाई (१७४४-४८) —

भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो पहली लड़ाई हुई, वह सन १७४० में आस्ट्रिया को गद्दी के निमित्त यूरोप के युद्ध की (जिस में फ्रैंच और अंग्रेज दोनों एक दूसरे के विरोधी थे) प्रतिध्वनि मात्र थी। भारत में दोनों देशों के लोगों में शान्ति बनाए रखने की कोशिश भी की गई थी, पर डूप्ले नहीं चाहत था कि वह यह मौक़ा हाथ से जाने दे। उसने अर्काट के नवाब

घटनाएँ

अनवरुद्दीन के साथ सुलह कर ली और इस डर से कि कहीं अंग्रेजों उसकी राजधानी पाण्डीचेरी पर धावा न कर दें, उसने नवाब के द्वारा अंग्रेजों के पास उस पर हमला न करने का संदेशा कइला भेजा । इसी बीच मे ला वूडौने की अधीनता मे एक सामुद्रिक सेना ने मद्रास पर धावा करके एक मामूली-सी लड़ाई के बाद उस पर कब्जा कर लिया । पर उक्त फ्रेंच कप्तान ने खासी रकम लेकर शहर वापिस कर देने का वायदा किया, परन्तु लावूडौने के बाद डूप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया । अनवरुद्दीन उस समय दक्षिण भर का हाकिम था, इम लिये उसे आशा थी कि इस विजय का कुछ हिस्सा उसे भी मिलेगा । डूप्ले ने उसे कुछ देने दिलाने से साफ इन्कार कर दिया । इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने मद्रास पर कब्जा करने के लिये दस हजार सेना भेजी । उसका सामना एक छोटी किन्तु सुशिक्षित फ्रेंच सेना ने किया और उसे दुरी तरह हरा दिया । डूप्ले ने इस विजय को और भी आगे बढ़ाने के लिये सेंट डेविड के द्विपे पर धावा करने का इरादा किया, इसी समय अंग्रेज मेजर लारेंस ने आकर उन्हे पीछे हटा दिया और फिर पाण्डीचेरी पर धावा कर दिया । परन्तु अंतमे अंग्रेजों को बड़ी क्षति के बाद घेरा उठा लेना पड़ा । उधर ऐ ला रोपेल की सन्धि से यूरोप का युद्ध भी समाप्त हो गया था । इस सन्धि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए देशों को वापस कर देना आवश्यक था

कगनीतियों

की सफलता

इससे मद्रास अंग्रेजों को वापिस मिल गया । इस युद्ध से भारतवासियों की निगाह में फ्रेंच सेना का गौरव और डूप्ले का मान बढ़ गया ।

करनाटक की दूसरी लड़ाई (१७४९-१७६४)—

इसके कुछ दिनों बाद ही एक ऐसा मौक़ा आया जो डूप्ले की योजना के अनुकूल था । हैदराबाद का वृद्ध ^{कारण} निज़ाम मर गया था और उसकी गद्दी पर अधिकार करने के लिये उसके बेटे नासिरजंग और पोते मुज़फ्फरजंग में झगड़ा उठ खड़ा हुआ था । इसी तरह का एक झगड़ा कर्नाटक में भी उठा । बात यह थी कि वहाँ के शासक अनवरुद्दीन का, जिसे सृत निज़ाम ने नवाब बनाया था, किसी पिछले नवाब के जमाई चन्दासाहब ने विरोध शुरू कर दिया था । मुज़फ्फरजंग ने चन्दासाहब से मेल कर लिया और डूप्ले से सहायता की प्रार्थना की । वह तो यह चाहता ही था । इन सब की सम्मिलित सेना ने अनवरुद्दीन पर सन् १७४६ में धावा बोल दिया और उसे मार डाला । अनवरुद्दीन का पुत्र मुहम्मदअली भाग कर त्रिचिनापली जा पहुँचा । अब चन्दासाहब को केवल मुहम्मदअली को ही हराना था, इसके बाद वह करनाटक का शासक हो जाता ।

अंग्रेजों ने इस बात से डर कर कि फ्रेंच लोग अपना प्रभाव बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, मुहम्मदअली और नासिरजंग का पक्ष

लड़ाई के बाद उस पर अधिकार करने में सफल हुआ। क्लाइव

अर्काट

की बात ठीक निकली। जिस समय चन्दासा-

हव को इस बात की खबर हुई, उसने अपनी

सेना का एक बड़ा-सा भाग अर्काट के पुनर्विजय के लिये भेजा,

जिसके विरुद्ध क्लाइव ५३ दिनों तक साहस के साथ अपनी रक्षा

करता रहा। इसके बाद उसे मद्रास की नई सेना से सहायता प्राप्त

हो गई। जब चन्दा साहव की सेना ने घेरा उठा लिया तो क्लाइव

ने उस पर हमला कर उसे अर्नी और कवेरीपाक में हराया। इसके

बाद क्लाइव ने मेजर लारेंस के साथ, मुहम्मदअली को छुटकारा

दिलाने के लिये, त्रिचनापली की ओर कूच किया। चन्दासाहव

को घेरा उठाने के लिये विवश करके मुहम्मदअली को करना-

टक का नवाब घोषित कर दिया गया। चन्दासाहव मैदान से

भाग कर तंजौर के राजा के हाथ में पड़ गया और

मारा गया।

पर डूप्ले इतनी जल्दी चुप होकर बैठने वाला नहीं था, उस

ने अपनी क्षतिपूर्ति करने का प्रयत्न जारी रखवा। उधर अंग्रेज

शांति चाहते थे क्योंकि इस लड़ाई का उनके

डूप्ले के साथ

व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा था। पर डूप्ले

समझौते की

कुछ नहीं सुनता था और इस बात पर अडा

बात चीत का

हुआ था कि जब तक उसे कर्नाटक का नवाब

रद होना

स्वीकार न किया जायगा, वह किसी तरह का

समझौता न करेगा। अंग्रेज इसके लिये तैयार नहीं थे, इसलिये जब

वे अन्य सारे उपायों से हार गए तो उन्होंने इस मामले में सीधे फ्रांस के बादशाह से लिखापढ़ी करनी शुरू की। बादशाह और उसके दरबारी अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण डूप्ले को उस महत्वाकांक्षा को जान ही न सके थे, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह था कि फ्रैंच व्यापार नष्ट होता दिखाई देना। इसके अतिरिक्त दरबार में डूप्ले के दुश्मन भी काफी थे, जिन्होंने उसके विरुद्ध बादशाह के कान खूब भरे।

डूप्ले को
वापस बुला
लिया गया

डूप्ले को वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू नामक एक और अफसर को भेजा गया और सन् १७५५ में पाडीचेरी की सन्धि के अनुसार युद्ध समाप्त कर दिया गया। इस संधि

के अनुसार विजित प्रदेश वापस कर दिये गए, मुहम्मदअली को कर्नाटक का नवाब मान लिया गया, और इस प्रकार अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से युद्ध किया था, वह सब उन्हें प्राप्त हो गया, तथा फ्रांसीसियों के हाथ में जो कुछ पहले था वह भी निकल गया।

कर्नाटक की तीसरी लड़ाई (१७५८-१७६१)—

सन् १७५६ में यूरोप में सात वर्ष का युद्ध छिड़ गया और भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में पुनः विरोध

कारण

बढ़ने लगा। फ्रैंच सरकार ने लाली को इस

उद्देश्य से भारत का गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ बना कर भेजा कि वह फ्रांसीसियों का पहला राज्य वापस ले लेने की कोशिश करे। वह पांडीचेरी में सन् १७५७ में उतरा। यह पलासी की उस लड़ाई के साल भर बाद का क़िस्सा है जिस से अंग्रेजों के हाथ में

एक बड़ा सुवा और बहुत बड़े साधन आगये थे ।

लाली को शुरू शुरू में कुछ सफलता हुई । उसने फोर्ट सेंट डेविस पर अधिकार कर लिया और फिर मद्रास पर धावा करने का इरादा किया । पर उसके पहले वह निर्वाह

घटनाएं

के लिये किसी जगह कब्जा करना चाहता था ।

उसने तंजौर पर धावा किया । उसमें उसे सफलता न हुई । अब उसने उत्तरी सरकार से बुसी को बुला भेजा । यह बड़ी भारी भूल थी, क्योंकि उसके पीठ फेरते ही, क्लाइव द्वारा बंगाल से भेजे हुए कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया । निज़ाम ने भी फरांसीसियों का साथ छोड़ कर अंग्रेजों के साथ मेल कर लिया था और इस प्रकार फरांसीसियों का हैदराबाद रियासत में सारा प्रभाव नष्ट हो गया ।

लाली और बुसी ने मिल कर मद्रास पर धावा किया और दो महीने के घेरे के बाद शहर पर अधिकार कर लिया, पर अंग्रेज सामुद्रिक सेना के आते ही उन्हें घेरा उठा कर भागना पड़ा । अब लाली के पास निर्वाह के लिये भी कुछ नहीं रहा था । सिपाहियों को वेतन नहीं मिला था और वे विद्रोह करने पर उतारू हो रहे थे । सन् १७६०

बाडिवाश

में सरआयरकूट ने बाडिवाश में फरांसीसियों को बुरी तरह हराया और बुसी को कैद कर लिया । अब स्पष्ट होगया था कि भारत में फरांसीसियों का साम्राज्य कायम करने का अवसर सदा के लिये चला गया । दूसरे साल

फ्रैंच शक्ति के पतन की अन्तिम घटना के नाम से प्रसिद्ध है। लाली फ्रांस को वापस लौट गया, जहां उस पर अभियोग चलाया गया और उसे प्रायदण्ड दिया गया।

पेरिस की सन १७६३ की सन्धि के अनुसार शान्ति स्थापित हो गई और सात वर्ष के युद्ध का अन्त हुआ। पांडोचेरी और अन्य कई स्थान फ्रांसीसियों को वापस दे दिये गए।

परिणाम पर इसके बाद फ्रांसीसियों में अंग्रेजों का मुकाबला करने की ताकत कभी नहीं आई। अंग्रेजों ने गत सात वर्ष के युद्ध में यूरोप और अमेरिका में जो कुछ प्राप्त किया था उसके मुकाबले में उन्हें अपनी भारत की सफलता चुद्र-सी मालूम होती थी।

फ्रांसीसियों की असफलता के कारण—अंग्रेजों की सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, उसके अनेक कारण थे। डूप्ले, लाली या दुसी में घुराइयां निकालना व्यर्थ होगा, क्योंकि वह फहना कठिन है कि वे अयोग्य व्यक्ति थे। यदि हम स्ताइव, लारेंस या कूट को अधिक योग्य सेनापति मान भी ले, तो भी यह अन्तर इतना थोड़ा था कि केवल इसी आधार पर हम किसी की सफलता का कारण स्थिर नहीं कर सकते। वास्तविक कारण इससे गहरा था।

अंग्रेज कम्पनी को अपनी प्रतिद्वंद्विनी फ्रैंच कम्पनी को अपेक्षा अधिक सुविधाएँ प्राप्त थीं। फ्रैंच कम्पनी के अंग्रेज कम्पनी हिस्सेदार अपनी कम्पनी के मामलों में बहुत कम की श्रेष्ठता दिलचस्पी लेते थे। उसके पास धन का अभाव था

रहता था। फ्रैंच सरकार को निजी युद्धों से ही फुरसत नहीं थी, वह इस कम्पनी की उन्नति के लिये अवकाश और धन कहां से लाती। वस, डूप्ले की महत्वपूर्ण योजनाओं के असफल होने का बड़ा कारण धनाभाव था। इसके विपरीत अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी की आर्थिक दशा बड़ी दृढ़ और अच्छी थी। अंग्रेज इस बात को कभी नहीं भूले कि उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना है और लड़ाइयों में भी वे अपना व्यापार निरन्तर करते रहे। डूप्ले राज्य बढ़ाने के उत्साह में व्यापार को एक गौण काम समझने लगा था, परन्तु अंग्रेज हर एक विजय से अपने लाभ की कोई न कोई बात अवश्य निकाल लेते थे। डूप्ले की इस नीति का फल यह हुआ कि फ्रैंच सरकार, कम्पनी को लाभ के साधन के स्थान पर एक व्यर्थ का भार समझने लगी। इसके विपरीत अंग्रेज कम्पनी के पास धन बढ़ता जाता था।

अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति की उत्कृष्टता भी उनकी विजय का एक कारण थी। अंग्रेज सत्तार भर की सर्वोत्तम सामुद्रिक शक्ति के स्वामी समझे जाते थे और प्रायः सम्पूर्ण अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति की उत्कृष्टता सामुद्रिक मार्ग उनके अधिकार में थे। वे किसी स्थान पर सामग्री और आदमियों को बड़ी मात्रा और संख्या में एकत्र कर सकते थे, पर फर्राँसीसियों के विषय में यह बात नहीं थी। फ्रांस को सात वर्ष के युद्ध में अनेक बार सामुद्रिक लड़ाइयों में हराया गया था, इस लिये उसकी सामुद्रिक शक्ति पर बड़ा विपरीत असर पड़ चुका था।

अंग्रेजों ने सन् १७५७ में बंगाल पर जो विजय प्राप्त की थी, उसका भी इस फ्रेंच-अंग्रेज युद्ध पर काफ़ी असर पड़ा। अंग्रेजों के हाथ में खाद्य सामग्री और सैनिक सामग्री काफ़ी मात्रा में आ गई थी। लाली ने वास्तव में अंग्रेजों की बंगाल-विजय एक ऐसा काम अपने हाथ में लिया था जिसमें काम-याबी की कोई सूरत नहीं दीखती थी। उसके भारत में आने से पहले ही फ़रासीसियों की स्थिति दुर्बल हो चुकी थी। पांडीचेरी से चल कर और एक ऐसी शक्ति से युद्ध करके, जिसके अधिकार में बंगाल था और जिसका समुद्र पर प्रभुत्व था, सिक्न्दर या नेपोलियन भी नहीं जीत सकता था।

साथ ही यह भी ठीक कहा गया है कि फ़रासीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग नहीं था। अनेक बार ऐसा अवसर आया, जब किसी फ़रासीसी को आपत्ति में देख पिट की नीति कर भी उसके संगी साथी विलकुल अलग रहे। पर इन सब कारणों में मुख्य कारण इंगलैंड के प्रधान मन्त्री पिट की प्रभाव-शालिनी नीति थी, जिससे फ़्रांस भारत के फ़रासीसियों को कोई सहायता न दे सका। अपने अमेरिका और यूरोप के युद्धों तथा विपत्तियों से फ़्रांस वैसे ही चकनाचूर हुआ जा रहा था। अतः यह बात ठीक कही जाती है कि फ़रासीसियों ने अपना भारत का साम्राज्य कबीचेरन और कबीचेक के युद्धक्षेत्रों में खोया, त्रिचिनापली और चांडिवाश में नहीं।

डूप्ले—अंग्रेजों और फ़रासीसियों की प्रतिस्पर्धा की

कहानी को समाप्त करने से पहले डूप्ले के कार्य और चरित्र पर एक दृष्टि डालना उचित होगा। इस संघर्ष में उसका एक विशेष स्थान है। अभी हम उसके प्रतिद्वन्द्वी क्लाइव का जिक्र आगे के लिए छोड़ देते हैं। भारत में क्लाइव का कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता, अभी उसे और भी बहुत से काम करने थे, और भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करनी थी।

डूप्ले की तारीफ़ भी की जाती है और निन्दा भी। परन्तु इस बात में किसी को सन्देह नहीं हो सकता कि वह भारत के इतिहास में एक अत्यन्त उल्लेखनीय व्यक्ति था। प्रायः उस की तथा-कथित दुर्बलताओं, झल, मिथ्या गर्व और रुपये पैसे के मामले में अनैतिक आचरण पर आवश्यकतासे अधिक जोर दिया जाता है, परन्तु ऐसी बातों में आकर हम यह भूल जाने हैं कि वह एक सुयोग्य शासक था और अपनी योजनाओं में मौलिक और साहसी था। कुछ समय तक उसने फ़रांसीसियों को दक्षिण में सबसे ऊँचा स्थान देने में सफलता भी प्राप्त की। परन्तु वह उन्हें उस उच्च स्थिति में अधिक दिनों तक नहीं रख सका; क्योंकि उसके पास अभीष्ट साधनों का अभाव था और इससे उसकी योजनाओं में बाधा पहुँचती थी।

उसने क्या सफलता प्राप्त की, इस दृष्टि से नहीं किन्तु उसने किम दह पर अपना काम किया, इस दृष्टि से विचार करने पर हम देह संवा के लिये उसकी दन्सयना और प्रयत्नों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। अपने देश के हित-साधन के लिए उसने

अपनी सम्पत्ति को भी खर्च करने में संकोच नहीं किया। हमें उसी के शब्दों में कहना चाहिए कि उसने एशिया में अपनी जाति को समृद्ध बनाने के लिए अपना यौवन, अपनी सम्पत्ति और यहां तक कि अपने जीवन को भी अर्पण कर दिया। पर उसके स्वदेश में इस देशभक्ति और आत्मत्याग की प्रशंसा नहीं हुई। वह सन् १७५५ में फ्रांस को अपमानित दशा में वापिस हुआ और कुछ वर्ष विपत्ति में काट कर जैसे जैसे के लिए तंग हो कर मरा।

हम इस परिच्छेद को समाप्त करने से पहले डूप्ले के विषय में एक इतिहास-लेखक की सम्मति देना उचित समझते हैं। अनेक दुर्बलताएँ होते हुए भी वह अपने समय के और वस्तुतः इतिहास के अप्रणी फ्रांसीसियों में गिना जाएगा। उसने सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न बड़े साहस और वीरता के साथ किया, परन्तु वह असफल रहा, उसको जैसी स्थिति के आदमी के लिए हार अपमान-जनक बात नहीं थी। जब कभी वह साम्राज्य का स्वप्न देखता था, उसका देश उसमें प्रमुख स्थान ग्रहण किये होता था। उसके जीते जी उसके देशबन्धुओं ने उसके गुणों का आदर नहीं किया, तथापि ऐतिहासिकों ने उसे फ्रेंच वीरों में अग्रगण्य स्थान दिया है और वह अपने देशवासियों के हृदयों में एक महान् देशभक्त और अंग्रेजों के दिलों में एक वीर शत्रु के रूप में सदैव अंकित रहेगा।

प्रश्न

१. कारणों, घटनाओं और परिणामों पर प्रकाश डालते हुए

करनाटक की दूसरी लड़ाई का संक्षिप्त वर्णन करो ।

२. दक्षिण पर प्रभुत्व बैठाने में अंग्रेजों की सफलता और फरासीसियों की असफलता का कारण लिखो ।

३. इण्डे की नीति और चरित्र के विषय में तुम क्या जानते हो ?

४. निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखो:—

काउण्ट डी लाली, बुसी, अर्काट और वाडिवाश ।



तीसरा अध्याय

बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की बढ़ती

सिराजुद्दौला—दिल्ली के प्रति बंगाल की राजभक्ति कभी स्थिर रूप से नहीं रही, क्योंकि दूरवर्ती प्रदेश होने के कारण दिल्ली के शासक उस पर अपना काफ़ी प्रभुत्व बनाए न रख सके। मुग़ल शक्ति के ह्रास होते ही देश में अनेक सूबेदारों और शासकों ने अपनी अपनी स्वतन्त्र रियासतें कायम कर लीं। उन्हीं में बंगाल का एक अलीवर्दीख़ां भी था। वह एक चतुर और योग्य शासक था। उसने यूरोपियन लोगों के व्यापार में कभी दख़ल नहीं दिया। वह सन् १७५६ में अपने दोहते सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी नियुक्त करके मर गया। सिराज विवेकहीन और आचरणा-भ्रष्ट युवक था, जिसे किसी तरह की शिक्षा नहीं मिली थी। बाल्यकाल में उसके नाना अलीवर्दीख़ां ने वेहद लाड़ प्यार से उसकी आदतें बिगाड़ दी थीं।

ब्लैकहोल की दुर्घटना—सिराज ने अंग्रेज़ व्यापारियों

की सम्पत्ति के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें सुन रखी थीं और वह उनके साथ युद्ध करने का कोई न कोई वझाना ढूंढना चाहता था। यह वझाना मिलने में देर न लगी। जब यूरोप में सात वर्ष का युद्ध शुरू हुआ तो उसकी तैयारी के लिये अंग्रेजों ने अपने किले की मरम्मत शुरू की। इस पर सिराज ने, जो लडाई के अवसर की तलाश में ही था, फोर्ट विलियम किले के गवर्नर के पास कहला भेजा कि पुराने किले में उसने जितनी नई मरम्मत कराई है, उसे वह गिरा दे। इसके लिये अंग्रेजों के एक कार्य से नवाब को इस बात का एक और कारण मिला। उन्होंने एक ऐसे आदमी को शरण दी, जिसे नवाब सजा देना चाहता था। जब मांगने पर भी नवाब के हाथ में अपराधी को न सौंपा गया और किलेबन्दी भी न गिराई गई तो सिराजुद्दौला ने युद्ध करने का निश्चय कर लिया।

सिराज ने कासिम बाजार की अंग्रेजों की कोठी को लूट लिया और फिर कलकत्ते की ओर एक बड़ी सेना के साथ प्रस्थान कर दिया। किले की सेना ने पांच दिन तक वीरता के साथ अपनी रक्षा की, परन्तु अन्त में किले की रक्षा का भार हालवेल नामक व्यक्ति की अवीनता में थोड़े से आदमियों को छोड़ कर सेनापति डेक नदी के एक रास्ते छोटी-सी नाव में बैठ कर भाग निकला। किले की सेना ने अपनी रक्षा के लिये दो बार और प्रयत्न किया, पर वाद को इसका कुछ फल न होते देख कर आत्मसमर्पण कर दिया।

सिराज ने किले में घुस कर सिपाहियों को कैद कर लिया। उन्हें एक मामूली कर्मचारी को सौंप दिया, जिसने कहा जाता है कि एक बीस फीट लम्बी चौड़ी कोठरी में इन सब (१४६) अंग्रेजों को ठूस दिया, जहाँ वे रात भर खिड़की के पास जगह पाने की कोशिश में एक दूसरे पर टूटते रहे। जब सुबह को दरवाजा खोला गया तो केवल तेईस आदमी ज़िन्दा निकले। ❀

इस काल कोठरी वाली दुघटना से सारे ब्रिटिश साम्राज्य में क्रोध और उत्तेजना की लहर दौड़ गई और प्रतिहिंसा की ध्वनि जोर से उठ खड़ी हुई। संयोग से, उस समय सहायक सेना एडमिरल वाटसन अपने छोटे-से दस्ते के साथ मद्रास ही में था। क्लाइव, जो अपनी सन १७५३ की सफलता के बाद घर चला गया था, वापस आगया था। दोनों ने मिल कर यथासम्भव सेना इकट्ठी की और कलकत्ते की ओर फूँच कर दिया। २ जनवरी सन १७५७ को बहुत मामूली से युद्ध के बाद कलकत्ते पर अधिकार कर लिया गया। एक सप्ताह में हुगली पर भी अधिकार कर लिया गया। इस दशा में सिराजुद्दौला मुल्ह ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया, उन्हें उनके सारे अधिकार लौटा दिए। उनका माल वापस कर दिया और उन की सम्पूर्णा क्षति की पूर्ति करदी।

❀ अनेक इतिहासकार इस प्रकार की दुघटना की वास्तविकता को अस्वीकार करते हैं।

इसी समय खबर मिली कि फ्रांस के साथ फिर युद्ध छिड़ गया है, अतः अंग्रेज सेनापतियों ने अपनी सेना का रुख चंद्रनगर की ओर फेर दिया और उस पर अधिकार कर लिया ।

मीरजाफर के साथ षड्यंत्र—सन्धि हुए अभी बहुत समय न हुआ था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ अन्य प्रयत्न आरम्भ किए । उसने फ्रेंच सेनापति बुसी को निमन्त्रण दिया कि वह दक्षिण से आकर अंग्रेजों को सम्पूर्ण बङ्गाल से निकाल दे । क्लाइव इस सारी स्कीम को जान गया था । अतः उसने अन्तिम आघात करने का निश्चय किया । और इस के लिए उसे मौका भी जल्दी मिल गया । नवाब के दरबारी उसके शासन से असंतुष्ट थे और मृत नवाब अलीवर्दीखान का बहनोई जाफर—जिसके ज़िम्मे तनख्वाह बांटने का काम था—उन सब का अगुआ था । वह बंगाल की गद्दी पर अधिकार करना चाहता था । उसने क्लाइव से बातचीत करनी आरम्भ की, फलतः एक षड्यन्त्र रचा गया । क्लाइव ने हाल ही में नवाब के साथ एक सन्धि की थी, तथापि उसने इस षड्यन्त्र में पूरा सहयोग दिया । बात बहुत दिनों तक नहीं छिपी रह सकी और नवाब के कानों तक भी इस षड्यन्त्र की खबर पहुँच गई, जिससे उसके दिल में सन्देह उत्पन्न होगया, परन्तु यह सन्देह नवाब के खज़ाँचो अमोचन्द के कौशल से जल्दी ही जाता रहा । यह षड्यन्त्रकारियों के एजेण्ट के रूप में काम कर रहा था । उसने धमकी दी कि यदि

लाल कागज़ और
सफ़ेद कागज़

उसे तीस लाख रुपया न दिया गया तो वह सारा भण्डाफोड़ कर देगा। इस पर मीर जाफ़र और क्लाइव ने एक भूठा प्रतिज्ञा पत्र लिखा। क्लाइव ने अपने आप को अमीचन्द की चाल में उससे बढ़कर साबित किया। तथापि क्लाइव के इस कार्य को उचित नहीं कहा जा सकता। क्लाइव ने प्रतिज्ञा-पत्र की दो कापियां कीं, एक सफ़ेद कागज़ पर, दूसरी लाल कागज़ पर। पहली सच्ची थी और दूसरी धोखा देने के लिए बनाई गई थी। उस नकली प्रतिज्ञा पत्र में अमीचन्द का नाम दर्ज कर दिया गया था। इस प्रकार आई हुई मुसीबत को टाल दिया गया। वाटसन ने इस भूठे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। इस पर क्लाइव ने उसके भी जाली हस्ताक्षर बना लिए।

पलासी की लड़ाई—जून २३, सन् १७५७—बस, अब आक्रमण की ही देर थी। क्लाइव ने नवाब को एक लम्बा चौड़ा पत्र लिखा जिसमें उसने वे सब कष्ट लिखे जो उस समय तक अंग्रेज़ों को नवाब के हाथों मिले थे, और उस पर हाल ही में की गई संधि को भंग करने का दोष भी लगाया। उसी दिन वह अपनी तीन हजार फौज के साथ मुंशदाबाद की ओर रवाना हो गया। नवाब की सेना ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें ५०,००० पैदल और १८,००० घुड़सवार थे, पलासी गांव के निकट, जो चन्द्रनगर से २३ मील दूर था, मोर्चाबन्दी की थी। यह पहले से ही तय हो गया था कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही मीर जाफ़र अपनी सेना के साथ अंग्रेज़ों की ओर आ

मिलेगा। मीरजाफ़र ने वादा पूरा करने में देरी
 क़ाइव की द्विविधा की, अतः क़ाइव ने अपने को भयंकर संकट
 में पाया। शत्रु की सेना इतनी विशाल थी कि क़ाइव अपने जीवन
 में पहली बार हमला करने से म्किम्का। पर वह साइस करके
 लड़ाई के लिये आगे बढ़ा। यह लड़ाई परियाम में तो अत्यन्त
 महत्वपूर्ण थी, पर वीरता की दृष्टि से किसी भी अंश में प्रशंसनीय
 नहीं कही जा सकती। सर आयरकूट के धावे से नवाब की सेना
 में भगदड़ मच गई और तुरन्त ही मुर्शिदाबाद पर अधिकार कर
 लिया गया। नवाब को मीरजाफ़र के लड़के ने
 मीरजाफ़र पकड़ कर मार डाला। मीरजाफ़र को बंगाल का
 को नवाब नवाब बना दिया गया। नए शासक को अपने
 बनाया गया पद के लिए काफ़ी रकम देनी पड़ी। क़ाइव और
 अन्य अफसरों को बड़ी बड़ी रकमे दी गईं। मीरजाफ़र ने
 अंग्रेज़ों को एक बड़े से इलाके पर, जो आज कल चौबीस परगना
 के नाम से प्रसिद्ध है, जमींदारी का अधिकार दे दिया।

क़ाइव का बंगाल में पहला शासन-प्रबंध (१७५७-१७६०)

पलासी के युद्ध से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रसिद्धि बढ़ी,
 और यद्यपि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासक मीरजाफ़र
 कहलाता था, तथापि असली शासक क़ाइव ही
 अली गौहर था। कुछ अन्य घटनाएं ऐसी हुईं जिनसे मीरजाफ़र
 का आक्रमण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भार से और भी दब
 गया। सन १७५६ में शाहजादा अली गौहर ने, जो मुग़ल सम्राट का

था, दिल्ली की बादशाही सेना लेकर अवधके नवाब शुजाउद्दौलाके साथ बिहार पर हमला कर दिया। मित्र सेनाएँ पटने की ओर बढ़ीं और उन्होंने ने शहर के चारों ओर घेरा डाल दिया। मीरजाफर डर गया पर क्लाइव ने आक्रमणकारियों का सामना करके उन्हें भागाने के लिए विवश कर दिया।

कम्पनी की बढ़ती हुई शक्ति से मीरजाफर की घबराहट दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसने चुपके चुपके डचों से बातचीत की।

ये लोग उम समझ चिन्सुरा में रहते थे। बटेविया डचों को हार से डच सेनाओं के जहाज़ आए। परन्तु क्लाइव ने फुर्ती के साथ डचों को बुरी तरह हरा दिया और उन्हें हर्जाने के रूप में एक बड़ी रकम भी अर्पण करनी पड़ी। बस डचों की यह आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद वे भारत के राजनीतिक क्षेत्र से हमेशा के लिये चले गए।

बंगाल की जीत से अंग्रेज़ भारत में प्रधान शक्ति बन गए और जब दक्षिण में उनकी फरासीसियों से लड़ाई हुई तो बंगाल से उन्हें बड़ी मदद मिली। फरासीसियों के युद्ध के बाद दक्षिण में जीत ही में क्लाइव को मालूम हुआ कि लाली दक्षिण में फरासीसियों का पहिले जैसा प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। जिस समय दुसी को लाली ने अपने पास बुला लिया, उसी समय क्लाइव ने अच्छा मौका देख कर कर्नल फोर्ड को एक सेना देकर दक्षिण की ओर भेज दिया। कर्नल फोर्ड ने फरासीसियों से उत्तरी सरकार का इलाका छीन लिया समझ उसके बाद

वांडिवाश में अंग्रेजों की जीत हुई और फरॉसीसियों की शक्ति की भारत में समाप्ति हो गई। इधर क्लाइव का स्वास्थ्य खराब हो चला था, अतः सन १७६० के फरवरी मास में उसे भारत छोड़ना पड़ा। उसने बड़े बड़े काम कर दिखाए थे, पर अभी उसका सारा काम समाप्त नहीं हुआ था।

क्लाइव की अनुपस्थिति का समय—(१७६०—१७६५)—

कम्पनी ने अपनी सफल चालों से नवाब के अधिकारों को तो नष्ट कर दिया था पर वह शासन-भार अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं थी। अब अंग्रेज व्यापार ही में ध्यान लगाना चाहते थे।

पुरे शासन का
जमाना

वे कहते थे कि व्यापार ही “हमारा इन देशों में वास्तविक उद्देश्य है।” वैसे कहने को तो बंगाल में नवाब का शासन था, परन्तु वास्तव में शासन किसी का नहीं था। क्लाइव के बंगाल से खाना होते ही चारों ओर अव्यवस्था, असंतोष, अशांति और रिश्वत का जोर चलने लगा। मीर जाफर को एक तो इस दुर्दशा को ठीक करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था, पर यदि उसे यह अधिकार होता तो भी वह इस कार्य के लिए योग्य ही नहीं था। बड़ी बड़ी भेटों के कारण, जिन्हें वह क्लाइव और अन्य अफसरों को दिया करता था, उसकी आर्थिक दशा बड़ी खराब हो गई और शासन चलाने में उसे बड़ी असुविधा होने लगी।

थोड़े ही सालों में कम्पनी के नौकर सौदागर से हाकिम बन गए थे। उनमें से कुछ ने तो मीर जाफर के गद्दी पर बैठते ही

कम्पनी के नौकरो
की बढ़ती

बहुत-सी सम्पत्ति इकट्ठी कर ली थी और बाकी भी सब तरह के साधनों से अपनी आर्थिक दशा को उन्नत करने में लगे हुए थे। नया गवर्नर वैनिस्टार्ट तक इस मर्ज़ से नहीं बचा था, और यद्यपि उसे कम्पनी से १८,००० पौण्ड वापिक वेतन मिलता था, तथापि वह अपना निजी व्यापार भी चलाता था।

मीर कासिम को नवाब बनाया गया—नई नई असु-विधाएं उत्पन्न होने लगी। कम्पनी का बोध खाली होगया था। उधर नवाब के सिपाही अपनी पिछली तनख्वाहे माग रहे थे। मीरजाफर के नाममात्र के प्रभु, नए मुगल सम्राट् शाहआलम ने नवाब पर चढ़ाई कर दी, परन्तु उसे ब्रिटिश सेना से हार कर अंग्रेजों से सान्ध कर लेनी पड़ी।

बंगाल कोसिल को धन की बड़ी आवश्यकता थी। अब मीरजाफर उनके लिए बेकार हो गया था। इसलिए उन्होंने, कुछ परिवर्तन करने की इच्छा से मीर जाफर के जमाई मीरकासिम को गद्दी पर बैठा दिया। इस सहायता के बदले में मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्दवान, मिदनापुर और चिटागाव के किले दे डाले।

यह नया नवाब नालायक नहीं था, और यदि उसे अवसर दिया जाता तो वह सुशासन भी कायम कर देता, परन्तु वह अपनी योग्यता के कारण ही अंग्रेजों की आंखों में शीघ्र ही खटकने लगा। वे ऐसा कोई सुधार नहीं होने देना चाहते थे जो उनके रूपया पैदा करने के मार्ग

मीर कासिम की
परेशानिया

वांछिवाश में अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसियों की शक्ति का भारत में समाप्ति हो गई । इधर क्लाइव का स्वास्थ्य खराब हो चला था, अतः सन १७६० के फरवरी मास में उसे भारत छोड़ना पडा । उसने बड़े बड़े काम कर दिखाए थे, पर अभी उसका सारा काम समाप्त नहीं हुआ था ।

क्लाइव की अनुपस्थिति का समय—(१७६०—१७६५)—

कम्पनी ने अपनी सफल चालों से नवाब के अधिकारों को तो नष्ट कर दिया था पर वह शासन-भार अपने पुरे शासन का जमाना ऊपर लेन को तैयार नहीं थी । अब अंग्रेज व्यापार ही में ध्यान लगाना चाहते थे ।

वे कहते थे कि व्यापार ही “हमारा इन देशों में वास्तविक उद्देश्य है।” जैसे कहने को तो बंगाल में नवाब का शासन था, परन्तु वास्तव में शासन किसी का नहीं था । क्लाइव के बंगाल से खाना होते ही चारों ओर अव्यवस्था, असतोष, अशांति और रिश्वत का जोर चलने लगा । मीर जाफर को एक तो इस दुर्दशा को ठीक करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था, पर यदि उसे यह अधिकार होता तो भी वह इस कार्य के लिए योग्य ही नहीं था । बड़ी बड़ी भेटों के कारण, जिन्हें वह क्लाइव और अन्य अफसरों को दिया करता था, उसकी आर्थिक दशा बड़ी खराब हो गई और शासन चलाने में उसे बड़ी असुविधा होने लगी ।

थोड़े ही सालों में कम्पनी के नौकर सौदागर से हाकिम बन गए थे । उनमें से कुछ ने तो मीर जाफर के गद्दी पर बैठते ही

कम्पनी के नौकरो
की बड़ी

बहुत-सी सम्पत्ति इकट्ठी कर ली थी और
वाक्की भी सब तरह के साधनो से अपनी
आर्थिक दशा को उन्नत करने मे लगे हुए
थे । नया गवर्नर वैनिस्टार्ट तक इस मर्ज़ से नहीं बचा था, और
यद्यपि उसे कम्पनी से १२,००० पौण्ड वाषिक वेतन मिलता था,
तथापि वह अपना निजी व्यापार भी चलाता था ।

मीर कासिम को नवाब बनाया गया—नई नई असु-
विधाएं उत्पन्न होने लगी । कम्पनी का धोप खाली होगया था ।
उधर नवाब के सिपाही अपनी पिछली तनख्वाहे मांग रहे थे ।
मीरजाफर के नाममात्र के प्रभु . नए मुगल सम्राट् शाहआलम ने
नवाब पर चढ़ाई कर दी, परन्तु उसे ब्रिटिश सेना से हार कर
अंग्रेजो से सान्ध कर लेनी पडी ।

बंगाल कोसिल को धन की बड़ी आवश्यकता थी । अब मीर-
जाफर उनके लिए बेकार हो गया था । इसलिए उन्होने, कुछ परि-
वर्तन करने की इच्छा से मीर जाफर के जमाई मीरकासिम को
गद्दी पर बैठा दिया । इस सहायता के बदले मे मीर कासिम ने
अंग्रेजो को बर्दवान, मिदनापुर और चिटागाव के जिले दे डाले ।

यह नया नवाब नालायक नहीं था, और यदि उसे अवसर
दिया जाता तो वह सुशासन भी कायम कर देता, परन्तु वह अपनी
योग्यता के कारण ही अंग्रेजो की आंखो मे शीघ्र
मीर कासिम की
पेशानिया
ही खटकने लगा । वे ऐसा कोई सुधार नहीं होने
देना चाहते थे जो उनके रुपया पैदा करने के मार्ग

मे रुकावटें डाले । उन्होंने यह अपना अधिकार बनाया कि वे बिना किसी प्रकारकी चुन्नीके व्यापार करें यद्यपि नवाब की प्रजा को चुन्नी देनी पड़ती थी । एक ओर कम्पनी नवाब से उसकी रक्षा के लिए रखी गई सेनाके निर्वाहके लिए बड़ी रकममें मांगती और दूसरी ओर कम्पनी के नौकर आण दिन निरागर दावे पेश करते, जिनमें नवाब की आय में और भी कमी होनी जाती और उसकी प्रजा को असुविधा होती । इस प्रकार का सिलसिला अधिक दिनों तक नहीं चल सकता था । नवाब ने हताश होकर अपनी राजधानी मुंगेर को हटा दी और यह घोषणा कर दी कि सब व्यापारों पर से चुंगी हटा ली जाय । इससे सम्पूर्णा व्यापारियों का समान अधिकार हो गया और अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचा । अब युद्ध अनिवार्य था । अंग्रेजों ने पटना पर अधिकार कर लिया, पर मीर कासिम ने उस पर पुनः कब्जा कर लिया और वहाँ के सारे यूरोपियनों को कैद कर लिया । अंग्रेजों ने उस पर धावा किया और उसे कटवा और बेरिया की दो लडाइयों में हरा दिया । अब मीर कासिम का टिपा हुआ क्रोध बाहर निकल पड़ा और उसने पटना के अंग्रेजों का इत्तेआम कर दिया । उस आजा का पालन नवाब के एक जर्मन कर्मचारी ने, जिमका उपनाम मसरु था, पटना का इत्तेआम बड़ी सख्ती के साथ किया । इस पर मन १७६३ में मीरकासिम को हमेशा के लिए सख्ती से उबार दिया गया और उसकी जगह मीरजादर को पुनः नवाब बना दिया गया ।

मीरजादर से बचन ले लिया गया कि वह अंग्रेजों को धिक्का

किसी प्रकार के कर के व्यापार करने दे और मोर कासिम द्वारा उन्हें पहुँचाई गई सारी ज़तियों को पूरा कर दे। इधर मोरकासिम बङ्गाल से भागकर अवध के नवाब शुजादौला के पास पहुँचा। वहाँ दिल्ली का मुग़ल सम्राट् शाह आलम भी था। इन तीनों ने एक साथ बङ्गाल की ओर कूच किया, पर इन्हें बक्सर में मेजर मुनरो ने बुरी तरह से हरा दिया। यह युद्ध पलासी के युद्ध से भी ज्यादा भीषण था, इमने सदा के लिए निर्णय कर दिया।

बक्सर की लड़ाई

१७६४

पलासी से आरम्भ किया गया काम यहाँ समाप्त हुआ। नाम-मात्र के भारत सम्राट् ने विजेता को आत्मसमर्पण कर दिया।

अवध का नवाब अपने देश को भाग गया। उसकी शक्ति इस समय विस्कुल चूर्ण हो चुकी थी।

क्लाइव का बंगाल में दूसरा राज्य-प्रबन्ध—

(१७६५—१७६७)—इधर बङ्गाल के कुशासन की खबर कम्पनी के संचालकों के कानों में पहुँच चुकी थी। उन्होने शीघ्र ही क्लाइव को (जो अब लार्ड क्लाइव हो गया था) बङ्गाल का गवर्नर बना कर, और कम्पनी के प्रबन्ध में सुधार करने का अधिकार देकर भारत को भेज दिया। वह मई सन् १७६५ में इस देश में पहुँच गया। उसके आने से पहले मोरजाफर मर गया था, और उसकी जगह उसका लड़का नवान नजमुद्दौला गद्दी पर बैठ चुका था।

क्लाइव ने आने के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया।

और अवध के नवाब के साथ सुलह की गई जिसके अनुसार नवाब को अवध का राज्य वापस मिल गया। पर इलाहाबाद और कोरा के इलाके बादशाह को दिए गए, और इस के बदले बादशाह ने कम्पनी को बङ्गाल विहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया, जिसकी आय में से २६ लाख रुपया सालाना बादशाह को देना नियत किया गया।

इस सन्धीके अनुसार कम्पनी के अधिकार में सौंपे गए प्रदेशका शासन जिस प्रणाली पर चलने लगा, उसे दोहरा शासन (Dual system) कहते हैं। कम्पनी को दीवानी का अधिकार मिल जाने से अब नज़मुद्दौला कम्पनी का पेंशनमात्र ही रह गयाथा। पर क्लाइव ने भारतीय शासन का रंग रूप बनाये रक्खा। कम्पनी को इन सूबों पर शासन करने का जो अधिकार मिला था, उसका उपयोग स्वयं करने की बजाय उसने बहुत से महकमे नायब नाज़िमों के सुपुर्द कर दिये। लगान, कर आदि को एकत्र करने का कार्य, दीवानी, फौज़दारी और पुलिस के महकमे—सब नायबों के ही हाथों में थे, जिन में कम्पनी बहुत कम दखल देती थी। शासन-कार्य चलाने के लिये नवाब को ५३ लाख रुपये दिए जाते थे। दोहरा शासन इस बात में था कि यद्यपि देश की असली शासक कम्पनी ही बन चुकी थी, पर वह अपने सारे कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहती थी और एजन्सी से काम चला रही थी।

क्लाइव का स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया और वह

में इङ्गलैंड को खाना हो गया । कुछ दिनों तक वह लण्डन बड़ी शान के साथ रहा; पर उस के शत्रुओं ने उस पर भारत-दुराचरण करने का अभियोग लगाया । उसने अपनी रुफ़ाई पे की और अन्त में उसे हाउस आफ़ कामन्स ने निर्दोष ठहराया पर इस तरह लाञ्छित होकर वह अधिक दिनों तक जी न सका और २ नवम्बर १७७४ में, पचास साल की उम्र में उसने आत्महत्या कर ली ।

क्लाइव का कार्य—कहा जाता है कि क्लाइव भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के इतिहास का संक्षिप्त रूप था—पहले व्यापारी, फिर

कम्पनी का
साधारण क्लर्क

सिपाही, और अन्त में शासक । जब वह छोटी उम्र का था तो उसके मां बाप उससे परेशान रहते थे और उसे एक आवारागर्द

और नटखटी लड़का समझते थे । जब उसे कम्पनी में क्लर्क की जगह मिलने लगी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल ही उसे भारत को भेज दिया । वे क्या जानते थे कि यही नटखटी लड़का भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक होगा ।

क्लाइव ने भारत में आकर शीघ्र ही कलम रख कर तलवार छठा ली और करनाटक की दूसरी लड़ाई में यह सिद्ध हो गया

सैनिक

कि वह बड़ा योग्य सेनापति है । उसे युद्ध-कला से किसी तरह का परिचय नहीं था, पर अर्काट

की लड़ाई में उसने जो ढङ्ग अपनाये, युद्ध-विद्या के आचार्यों को भी शायद वही ढंग अपनाने पड़ते । पलासी से उसकी प्रसिद्धि

और भी बढ़ी और उसे इंग्लैण्ड के महामन्त्री पिट ने “द्वैवी सेनापति” की उपाधि दी। उस में आश्चर्य-जनक प्रतिभा और स्वाभाविक शक्ति मालूम पड़ती थी और उसे देखते ही लोगों में विश्वास उत्पन्न हो जाता था। अर्काट और

पलासी लड़ाइयो में उसे अपार सेना के अर्काट और पलासी विरुद्ध लड़ना पड़ा, पर—जैसा हम इतिहास में प्रायः देखते हैं—क्लाइव जैसे आदमियों के लिये सेना की संख्या कोई विशेष महत्वपूर्णा बात नहीं होती।

पर अभी क्लाइव को एक कार्य भी करना था—यह काम शासन-प्रबन्धक का था। बङ्गाल की दूसरी गवर्नरी के अवसर पर उसकी इस विषय की योग्यता भी पूरी शासन-प्रबन्धक तरह सिद्ध हो गई। जिस समय वह बक्सर के युद्ध के बाद भारत में आया, तो राज्य बढ़ाने में ब्रिटिश सेना के मार्ग में कोई रुकावट नहीं थी। पर क्लाइव ने जान लिया कि “आगे बढ़ना एक बड़ी फजूल आकांक्षा है।” बाद के इतिहास से मालूम हो जाता है कि उसका निर्णय किनना ठीक था। इस रुझावा उसके नागरिक और सैनिक सुधार, देशो शासका से सम्बन्ध स्थापित करने के ढङ्ग और दोहरा शासन—ये सब बातें यद्यपि बहुत ही अपूर्ण और काफी अंश तक दोषपूर्ण भी थीं, तथापि यह निस्संकोच होकर कहा जा सकता है कि भविष्यमें उन्हीं के द्वारा बङ्गाल में सुनियन्त्रित शासन की नींव पड़ी। इस काम में ने बड़ी धीरता के साथ अनेक असुविधाओं का सामना

यद्यपि क्लाइव की वीरता, और किसी हद तक उसका शासन-कौशल देखकर हृदय में उसके लिए स्वयं ही प्रशंसा के भाव आ जाते हैं, तथापि उसके जीवन की अनेक ऐसी घट-कुछ बुरे कार्य नाएं भी हैं, जिनके लिए हम उसे धिक्कारने को मजबूर हो जाते हैं, और जिनके कारण उसकी यादगार सदा के लिए कलंकित हो जाती हैं। चाहे कितनी ही सफ़ाईया पेश की जाय, तथापि वह नकली प्रतिज्ञा-पत्र वाला मामला उसकी यादगार पर काला धब्बा ही बना रहेगा। यह कहने से कि जिस पुरुष ने उस के साथ सहज व्यवहार नहीं किया, वह भी उसके साथ सहज व्यवहार करने को वाध्य नहीं था, यह लाइन धुल नहीं जाता। वह धन प्राप्त करने में अच्छे बुरे ढङ्ग का ख्याल नहीं करता था, यह इस बात से अच्छी तरह साबित हो जाता है कि वह नज़रें लिया करता था और उसने अपने निजी व्यवहार के लिए मीरजापुर से एक जागीर भी स्वीकार की थी। इन सब दुर्बलताओं के होते हुए भी, उसने जो कुछ किया, उसमें इतना महत्व है कि लार्ड मेकाले का यह कथन हमें अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं जंचता कि “ब्रिटेन ने इससे बड़ा पुरुष—चाहे वह शत्रु में हो या कौंसिल में—अभी तक शायद ही पैदा किया हो।”

सन १७६७ से १७७२ तक—बङ्गाल का दूसरा गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, पर उसकी नियुक्ति 'सन १७७२ में हुई थी। इस लिए हमें हेस्टिंग्स से पहले क्लाइव के वाद के पांच सालों का बर्णन कर देना चाहिए। इस ज़माने में ब्रेलेस्ट

और कार्टियर की अधीनता में दोहरे शासन की बुराइयाँ और असफलता अच्छी तरह मालूम हो गई। नवाब पर ज़िम्मेदारियों का भार तो रख दिया गया था, परन्तु उसे अधिकार नहीं दिए गए थे। उधर कम्पनी के पास अधिकार तो थे, पर वह अपने पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। नवाब शासन कर नहीं सकता था, कम्पनी करना नहीं चाहती थी। इस प्रकार लोगो को उन हिन्दुस्तानी और यूरोपियन अफसरों की दया का भरोसा ही एकमात्र आश्रय-स्थान था, जो निजी व्यापार में लगे रहते थे और लोगो की भलाई का कभी खयाल नहीं करते थे। सन् १७६६—१७७० के वर्ष में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। यह अनुमान किया गया है कि बंगाल की कुल आबादी का एक तिहाई हिस्सा (लगभग एक करोड़ आदमी) इस अकाल में भूख और रोग से छटपटा कर मर गये और खेती वाली ज़मीन का एक तिहाई हिस्सा बेकार पड़ा रहा। उधर कम्पनी के अधिकारियों ने लोगो के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करने के बजाय खूब ख़ाबल खरीदे और ऊँची कीमत पर बेच कर बड़ा मुनाफ़ा उठाया।

उधर उत्तर भारत में मराठों की लूटमार का अघातक दुरी तरह छाया हुआ था। पानीपत की लड़ाई की हार के बाद मराठे अथ संभल चले थे। महादजी सिंधिया ने, जो उत्तर भारत उस समय मराठों में सब ज़्यादा ताकतवर था, शाह आलम की गद्दी पर बैठाने का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया

और यह इस शर्त पर कि वह उसके संरक्षण में ही राज्य करे । यह लालच काम कर गया और मुगल बादशाह ने ब्रिटिश संरक्षण छोड़ दिया । सन १७७१ में उसे बड़ी धूमधाम के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया । महादजी उसका संरक्षक बना—उसे तो जेलर कहना चाहिए, क्योंकि बादशाह उसके हाथों में क़ैद-सा था ।

दक्षिण भारत में नई अशांति उठ खड़ी हुई थी अंग्रेजों का मित्र मुहम्मदअली केवल नाममात्र का नवाब था । अब दक्षिण में तीन शक्तियां ज़ोर पकड़ने लगी थीं । दक्षिण में हैदरअली इनमें एक मैसूर का नवाब हैदरअली भी था, का उदयान जिसने हिन्दू राजा को गद्दी से उतार कर राज्य पर अधिकार कर लिया था । यह हिन्दू राज्य सन १५६५ में विजयनगर साम्राज्य के विनाश के बाद कायम हुआ था । दूसरा भय मराठों की सम्मिलित शक्ति का था । उधर निज़ाम भी अपने काफी बड़े राज्य को और अधिक बढ़ानेकी कोशिश कर रहा था । जैसे कहने को तो वह अंग्रेजों का मित्र था पर वह चुपचाप हैदरअली और मराठों से अन्दर ही अन्दर गुप्त सम्बन्ध भी स्थापित करता जाता था ।

मैसूर की पहली लड़ाई (१७६७—१७६६)—हैदरअली की बढ़ती हुई ताकत से और शक्तियों को ईर्ष्या हुई और उसके विरुद्ध अंग्रेज, मराठे और निज़ाम तीनों मिल गए । पर हैदरअली ने मराठों को रुपया देकर

संतुष्ट कर लिया और निज़ाम को भी अंग्रेजों का साथ न देकर अपना साथ देने पर सहमत कर लिया। इन मित्र सेनाओं को कर्नल स्मिथ ने चंगामा और विनोमली में हरा घटनाएँ दिया। अब निज़ाम ने हैदरअली का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों के साथ मेल कर लिया।

परन्तु मद्रास में अयोग्य अफ़सरों का युद्ध-प्रबन्ध इतना दोषपूर्ण था कि सन १७६६ में हैदरअली कर्नाटक को रौंद कर मद्रास जा पहुँचा और वहाँ उसी की शर्तों पर संधि परिणम स्थापित होगई। विजित प्रदेशों को वापिस कर दिया गया और आत्मरक्षा के युद्ध में एक दूसरे की सहायता करना निश्चित किया।

प्रश्न

१. तुम क्लाइव के प्रारम्भिक जीवन के बारे में क्या जानते हो ? उसके बंगाल के पहले और दूसरे शासन प्रबन्ध का संक्षेप में वर्णन करो। इस बात की चर्चा करो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने वाला वास्तव में वही था।

२. क्लाइव भारत में अंग्रेजों के इतिहास का संक्षिप्त रूप है, इसे साबित करो।

३. निम्नलिखित घटनाओं का राजनीतिक महत्व क्या है ?

- (१) पलासी का युद्ध
- (२) बक्सर का युद्ध
- (३) इलाहाबाद की सन्धि

की कौंसिल का सदस्य बन कर आया। सन् १७७२ में क्लाइव के वाद वह बङ्गाल का गवर्नर बनाया गया। कम्पनी के डाइरेक्टर उस पर बड़ा विश्वास करते थे और उसकी योग्यता और आचरण का बड़ा आदर करते थे।

गवर्नर की हैसियत से—जिन दिनों हेस्टिंग्स को गवर्नर बनाया गया, उन दिनों बंगाल में घोर अकाल फैला हुआ था। इस पर दोहरे शासन ने लोगों को और भी शासन संबंधी तबाह कर रक्खा था। पुराने कुशासन की सारी भसुविधाएँ बाते व्यवहार में आरही थीं। जिन निरीक्षकों को मालगुजारी के हिन्दुस्तानी अफसरों के हिसाब किताब की जाच करने के लिये मुक़रर किया जाता था, वे इस देश की भाषा और रहन सहन से अनभिज्ञ होते थे और इन हिन्दुस्तानी अफसरों के हार्थों में नाचते रहते थे। लोगो पर जुल्म किया जाता और कम्पनी के हिसाब में भी बेईमानी की जाती थी। न्याय और शासन-प्रबन्ध के महकमों में बड़ी गड़बड़ थी। उसका सबथा नवीन इन्तज़ाम करनेकी ज़रूरत थी। जिस समय हेस्टिंग्स गवर्नर बना, शासन की ऐसी ही घोर दुदेशा थी।

हेस्टिंग्स के सुधार—कम्पनी ने दीवान की हैसियत से काम करने का निर्णय कर ही लिया था, अतः अब मालगुजारी से कलकत्ते के मालगुजारी बोर्ड थाप कर दिया गया। कर तथा माल-

गुजारी इकट्ठी करने का काम अंग्रेज़ अफसरों को सौंप दिया गया, जिन्हें कलैक्टर कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग्स ने मालगुजारी के पंचवापिक बन्दोवस्त का ढङ्ग चलाया। खेती करने का पट्टा सबसे ऊँची बोली बोलने वाले को दिया जाने लगा।

प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें कायम की गईं। कलैक्टर के सुपुर्द सिविल-विधान का काम सौंपा गया और फौजदारी अदालतों में हिन्दुस्तानी ही काम न्याय विभाग करते रहे। हेस्टिंग्स ने कलकत्ते में दीवानी मुकदमों के लिये सदर दीवानी अदालत और फौजदारी के मुकदमों के लिये सदर निज़ामत अदालत नाम की। दो सबसे बड़ी अदालतें कायम करके न्याय की सुव्यवस्था की नींव डाली। उसकी देख-रेख में हिन्दू और मुसलमान-विधान भी बनाए गए।

डाइरेक्टरों की आज्ञानुसार हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब के लड़के की वृत्ति को आधा करके कम्पनी के व्यय में बचत करनी

शुरू की। शाहआलम मराठों के साथ मिल ही चुका था,

बचत इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने उसे २६ लाख रुपये का कर देना

बन्द कर दिया। कम्पनी का कथन था कि वह उस कर को देने के लिए तैयार नहीं, जो मराठों की जेबों में जाकर उनकी शक्ति बढ़ाए।

बादशाह से इलाहाबाद और कोटा के जिले वापस लेकर उन्हें

पचास लाख रुपये में शुजाउद्दौला को दे दिया गया। इसी

सम्बन्ध में नवाब ने हेस्टिंग्स को रहलौ के विरुद्ध किए जा रहे

युद्ध में हस्तक्षेप करने का मौका दिया और कम्पनी ने इस युद्ध में

नवाब को जो मदद की, उसके बदले में कम्पनी को चालीस लाख

रुपया दिया गया ।

रुहेलों की लड़ाई—इससे कुछ ही समय पहले अफ़ग़ान रुधिर की रुहेला नामी जंगली जाति रुहेलखण्ड में आ बसी थी । मराठों के प्रतिदिन के धावों से घबरा कर रुहेला सरदारों ने नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी और इसके बदले में चालीस लाख रुपया देने का वचन दिया । सन् १७७३ में मराठों की सेना ने रुहेलखण्ड पर हमला किया, पर अवध की फौजों से डर कर वह बिना लड़े ही वापस लौट गई । शुजाउद्दौला का काम समाप्त हो गया और उसने रुहेलों से वायदे के चालीस लाख रुपये मांगे, परन्तु उसे कुछ न दिया गया । इस पर बदला लेने के लिए नवाब ने अंग्रेजों से मदद मांगी । उससे सेना का सारा खर्च स्वयं उठाने का वचन दिया और वे चालीस लाख रुपये भी उन्हीं को देने का वायदा किया । हेस्टिंग्स इस मामले में हिस्सा लेने के लिए कुछ विशेष उत्सुक नहीं था, पर वह नवाब को नाराज़ भी नहीं करना चाहता था । उसने नवाब की सहायता के लिए एक सेना भेज दी । रुहेलों को हरा दिया गया । नवाब की सेना ने, जिसे लड़ने भिड़ने से कोई खास प्रयोजन नहीं था, कुछ गांवों को आग लगा दी और कुछ लूटमार भी की । इस विजय के पश्चात् रुहेलखण्ड को अवध में मिला दिया गया ।

हेस्टिंग्स ने रुहेलोंके सम्बन्धमें जो नीति ग्रहण की थी, उसकी तीव्र आलोचना की गई है, और वह आलोचना किसी हद तक ठीक

आलोचना भी है। यह कार्य सचमुच अनुचित था, क्योंकि हेस्टिंग्स ने, रुहेलों से कम्पनी का किसी किस्म का झगडा न होने पर भी, बिना किसी कारण के उन्हें कुचलने में मदद दी। परन्तु इस में हेस्टिंग्स का जो उद्देश था, वह भी हमें न भूलना चाहिए। वह समझता था कि यदि रुहेलों को एक अन्य शक्ति के अधीन कर दिया जायगा तो ब्रिटिश राज्य निष्कण्टक हो जायगा। इसके अतिरिक्त उसे इस युद्ध द्वारा कम्पनी की आर्थिक दशा सुधारने का भी मौका मिला, जो उस समय बहुत खराब थी।

जिस समय भारत में ये घटनाएं हो रही थीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मामले में हाथ डालना अपना तरेगुल्टिंग कर्तव्य समझा। कम्पनी के कुशासन की खबर इंग्लैंड में भी जा पहुंची थी और उसके प्रति लोगो में घृणा-सी फैल गई थी। जो लोग कम्पनी किस्मत जगा कर बंगाल से इंग्लैंड वापिस आते थे, उनकी खुशहाली लोगो की नजरों से छिपी न रहती थी। दूसरी ओर कम्पनी की अपनी आर्थिक हालत अच्छी न थी। उसे भारत के विभिन्न प्रान्तों में अपनी सेनाएँ रखने के लिए घाघ्य होना पड़ता था। कम्पनी के कर्मचारी कम्पनी के हित की अपेक्षा अपने नफे का अधिक ख्याल रखते थे। जिस समय कम्पनी के डाइरेक्टरो ने इंग्लैंड के प्रधान मन्त्रो लार्ड नार्थलिफ़ से सन १७७० में दस लाख पाउण्ड उधार मांगे और कहा कि उनके दिना वे अपना

काम ही नहीं चला सकते, तो सनसनी-सी फैल गई। पार्लियामेंट ने कम्पनी के ऊपर नियन्त्रण रखना अपना कर्तव्य समझा। वह अपने कुप्रबन्ध से ग्रीटेन के नाम को कलंकित कर रही थी। इस लिए पार्लियामेंट ने सन् १७७३ में एक ऐक्ट पास किया, जिसका नाम था रेगुलेटिंग ऐक्ट, क्योंकि यह भारत की सरकार को नियमित करता था। इस ऐक्ट के अनुसार निश्चय किया गया कि—

(१) कम्पनी की प्रबन्ध-सम्बन्धी और सैनिक बातों से सम्बन्ध रखने वाला सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार ब्रिटिश कैबिनेट (मन्त्रिमण्डल) या सम्राट् के सामने मजूरी के लिए पेश किया जाया करे।

(२) बङ्गाल के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कौंसिल बनाई गई। इसका बहुमत गवर्नर जनरल के लिए मान्य था। गवर्नर जनरल को एक साधारण और एक अतिरिक्त (कास्टिंग) वोट देने का अधिकार दिया गया।

(३) गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल को अन्य प्रेसीडेन्सियों के ऊपर अन्य रियासतों के सम्बन्ध में शासनाधिकार दिया गया।

(४) कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, जिस में एक चीफ़ जस्टिस और हाईकोर्ट के साधारण जज नियुक्त किए गए।

(५) कम्पनी का कोई शासन विभाग का या फ़ौजी कर्मचारी

किसी देशी राजा या नवाब से अथवा उसके किसी एजेण्ट के द्वारा कोई भेट स्वीकार नहीं कर सकता था और न वह किसी तरह का व्यापार ही कर सकता था ।

ऐक्ट के दोष--यह ऐक्ट केवल आधी कमी ही पूरी करता था और इसकी कई बातें स्पष्ट नहीं थीं । इस ऐक्ट में सुप्रीम कोर्ट के कर्तव्यों का निर्णय नहीं किया गया था न इस में सुप्रीम-कोर्ट के कोसिलों से सम्बन्ध का ही कुछ जिक्र था । परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही कोर्ट और कौन्सिल में भगडा उठ खड़ा हुआ । बङ्गाल कौन्सिल का बम्बई और मद्रास प्रेसिडेन्सियों पर कोई शासनाधिकार नहीं था और वे अपना प्रबन्ध आप अच्छी तरह कर सकती थीं । सब से बुरी बात यह थी कि कौन्सिल के सदस्य

हेस्टिगज के मार्ग
में कठिनाइयां

अपना गुट बना कर गवर्नर-जनरल के काम में रुकावटें खड़ी कर सकते थे । पर ये सब दोष होते हुए भी ऐक्ट ने महत्वपूर्ण

कार्य किया और भारत में नई शासन व्यवस्था की नींव डाली ।

हेस्टिगज गवर्नर जनरल की हैसियत से—रेगुलेटिंग ऐक्ट सन १७७४ से व्यवहार में आया और वारन हेस्टिगज को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया । उसको कौन्सिल में प्रोविस, क्लेवरिंग, मानसन और वारल नामक चार व्यक्ति रक्ते गए । सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ़ जस्टिस सर एलीजाह स्मिथ बनाया गया । कौन्सिल के सदस्यों में से पहले तीन जज हेस्टिगज की जगह पर बहुत दिनों से नजर गड़ाए बैठे थे और ऐसा साजूम

होता था कि वे कौन्सिल में गवर्नर-जनरल को सहायता देने के लिए नहीं, अतः उसके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए आए हैं। उन्होंने उसके विरुद्ध एक प्रकार का गुट-सा तैयार कर लिया और बहुमत उनके पक्ष में होने के कारण हेस्टिगज़ विल्कुल असहाय हो गया। रहेला युद्ध में हेस्टिगज़ ने जो आचरण किया था, कौन्सिल ने उसकी निन्दा की और हेस्टिगज़ के घोर विरोध करते रहने पर भी शुजाउद्दौला के उत्तराधिकारी (जो सन १७७५ में मर गया) से एक नई सन्धि कर ली जिसके अनुसार बनारस अंग्रेजों को मिल गया।

जब आपस के इन झगड़ों की खबर फैल गई तो बहुत से लोगों ने हेस्टिगज़ पर अभियोग लगाने शुरू कर दिए।

सब से अधिक भीषण अभियोग एक ऊँचे ओहदे वाले प्रभाव-

शाली ब्राह्मण, महाराज नन्दकुमार की ओर से
नन्द कुमार लगाया गया। उसने हेस्टिगज़ पर रिश्वत लेने

और नौकरियाँ बेचने का इल्जाम लगाया। कौन्सिल ने हेस्टिगज़ से वह सब रूपया खजाने में जमा करने को कहा, पर हेस्टिगज़ ने अपना विचार अपनी ही कौन्सिल में कराने से इन्कार कर दिया और नन्दकुमार पर षड्यन्त्र का मुद्दमा चलाया। जिन दिनों यह मुकदमा चल रहा था, उन्हीं दिनों मोहनलाल नामक एक आदमी ने नन्दकुमार पर जालसाजी का इल्जाम लगा दिया। इस अभिप्राय का विचार सर इलीजाह इम्पे ने किया। उसने नन्दकुमार को दोषी ठहराया और शीघ्र ही उसे फाँसी दे दी गई। इस पर सब ओर

और भी सनसनी बढी। इम्पे हेस्टिगज़ का मित्र था, इस लिये कहा जाने लगा कि हेस्टिगज़ ने किसी न किसी तरह अपने शत्रु से छुटकारा पा लिया है। वास्तव मे इस मामले की सत्यता जान सकने के लिये कोई पुष्ट प्रमाण मौजूद नहीं हैं। जो कुछ भी हो, यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों कानून, जिसमें जाल-साज़ी की नज़ा फांसी थी, भारत में लागू नहीं होना चाहिए था। हेस्टिगज़ की इस फाररवाई से उसका रोव फिर वैसा ही हो गया और उसके विरुद्ध कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया।

शीघ्र ही ऐसा समय आया, जब हेस्टिगज़ एक बार पुनः बंगाल का स्वामी बन गया। मानसून भर गया। अब हेस्टिगज़ अपने निजी वोट, एक कास्टिंग वोट और अपने पुराने सहायक वारवैल के वोट से अपने विरोधियों की एक न चलने देता था। फ्रांसिस ने अपना प्रयत्न बराबर जारी रक्खा, पर वह अपनी अल्पसंख्या के कारण कुछ न कर सका।

कौन्सिल की एक बैठक मे हेस्टिगज़ ने फ्रांसिस पर लांछन लगाया कि वह सच्चाई और मान दोनों से वंचित है। इस पर फ्रांसिस ने उसे द्वन्द्वयुद्ध को चुनौती दी और हेस्टिगज़ ने मूर्खतावश यह चुनौती स्वीकार कर ली। फ्रांसिस का पदत्याग द्वन्द्व-युद्ध में फ्रांसिस घायल हुआ। इसके बाद ही वह इंग्लैण्ड में वापस चला गया और पार्लियामेंट में अपने शत्रु हेस्टिगज़ पर बराबर इल्ज़ाम लगाता रहा। परन्तु इसके बाद जब तक हेस्टिगज़ भारत में रहा, उसके शत्रु यहां उसका कुछ

न बिगाड़ सके ।

मराठों की पहली लड़ाई (१७७५-८२)— हम पहले ही कह चुके हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के भयंकर आघात के बाद मराठों ने अपनी ताकत पुनः यथापूर्वक कर ली थी । चौथे पेशवा माधवराव ने बड़ी योग्यता के साथ शासन किया और निजाम तथा हैदरअली को युद्धों में कई बार हराया । इस बात का भी जिक्र आ चुका है कि महादजी सिधिया ने किस प्रकार दिल्ली और आगरे में कामयाबी हासिल की थी । इसी बीच में माधवराव अचानक मर गया और उसकी जगह नारायणराव गद्दी पर बैठा, जिसे साल भर के भीतर ही उसके चचा राघोबा के पदवालों ने मार डाला । राघोबा पेशवा बनना चाहता था, पर उसका विरोध किया गया और उस समय के एक अत्यन्त सुयोग्य मराठे नाना फडनवीस ने नारायणराव के पुत्र का समर्थन किया । इस तरह मुँह की खाकर राघोबा ने बम्बई सरकार से सहायता मांगी और

सूरत में उसके साथ सन्धि करके उसकी सहायता के मूल्य-स्वरूप साल्सट और बसीन देने का वचन दिया । बंगाल कौन्सिल ने यह कार्य नापसन्द किया । उसे परिवर्तन का पूर्ण अधिकार था ही, इस लिए उसने पुरन्दर में नाना फडनवीस के साथ संधी की जिसके अनुसार अम्रेज़ राघोबा का साथ इस शर्त पर छोड़ने को राज़ी हुए कि साल्सट पर उन्हीं का अधिकार रहेगा । यह नई सन्धी अभी कठिनता से समाप्त हुई

सूरत की

सन्धि, १७७५

पुरन्दर

की सन्धि

होगी कि कम्पनी के डाइरेक्टरों का पत्र आया, जिसमें उन्होंने सुरत की सन्धि को पसन्द किया।

अब राघोबा के साथ फिर से मित्रता स्थापित की गई और पूना की ओर एक सेना रवाना की गई, जिसे तेलगांव के पास मराठा सेना ने हरा दिया और उसे अपमानजनक शर्तें मानने को मजबूर कर दिया। इसके अनुसार अंग्रेजों को लिए हुए प्रदेश वापिस करने और राघोबा को मराठों के हाथों में सौंप देने को राजी होना पड़ा। पर बाद में डाइरेक्टरों ने इस सन्धि को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार की आज्ञा बिना सेना के अफसरों को इस तरह की सन्धि करने का कोई अधिकार नहीं था। कर्नल गोर्डन ने वज्राल से आकर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया और कप्तान पोपहम ने ग्वालियर के मजबूत किले पर आक्रमण किया। आगे चल कर लड़ाई ने और भी भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। बात यह हुई कि लगभग सम्पूर्ण मराठे राजाओं, निजाम और हैदरअली ने अंग्रेजों की शक्ति को नष्ट करने के लिए सन १७७६ में एक गुट बना लिया था। हेस्टिंग्स ने इस नाजुक हालत का सामना बड़ी धीरता और चतुरता के साथ किया और यह गुट कुछ विशेष सफलता प्राप्त न कर सका।

वारेन हेस्टिंग्स इस युद्ध से उकता-सा चला था। वास्तव में यह युद्ध उसकी इच्छा के प्रतिकूल ही लड़ा जा रहा था और इस का कम्पनी की आर्थिक हालत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था।

कम्पनी की हैदरअली के साथ दुश्मनी दिन पर दिन बढ़ती जाती थी, इसलिए वह भी मराठों के साथ मेल करना चाहता था ।

सल्वाई की सन्धि—फलतः महादजी सिंधिया के द्वारा सन्धि करली गई और उस पर सल्वाई में हस्ताक्षर हुए । अंग्रेजों को साल्स्ट का इलाका दिया गया और माधोराव नारायण को पेशवा मान लिया गया । राघोबा के लिए तीन लाख रुपये प्रति वर्ष की पेन्शन नियत हो गई । इस सन्धि के बाद २० वर्षों तक मराठों और अंग्रेजों में मित्रता बनी रही ।

मैसूर की दूसरी लड़ाई (१७८०—१७८४)—
सन १७५६ का गुट तो टूट गया पर हैदरअली उसी तरह अंग्रेजों का दुश्मन बना रहा । सन १७६६ में मद्रास की सरकार ने हैदरअली को उसके दुश्मनों से रक्षा करने का वचन दिया था, पर वह वचन पूरा न किया गया । इस वायदे के कुछ ही दिनों बाद जब मराठों ने उसके राज्य पर चढ़ाई की, तो हैदरअली को सहायता देने से मद्रास सरकार ने साफ़ इन्कार कर दिया था । हैदरअली को वह बेइज्जती याद थी, परन्तु वह मौके की ताक में था । सन १७७६ में अंगरेजों और फ़रांसीसियों ने यूरोप में लड़ाई छिड़ गई और अंगरेजों ने दक्षिण भारत में उनके सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, जिसमें माही भी शामिल था । हैदरअली इस बन्दरगाह की तरफ पहले ही से बहुत आशा लगाए बैठा था, क्योंकि फ़रांसीसियों ने उससे

वायदा किया था कि वे वहां से उसके पास युद्ध की सामग्री भेजेंगे । उसने माही को बचाने का घोर प्रयत्न किया, परन्तु वह असफल रहा । अब मौका आ गया था, अतः हैदरअली ने अंगरेजों के साथ युद्ध ठान लिया ।

आरम्भ में हैदरअली की जीत हुई । अपनी २०,००० सेना लेकर वह कर्नाटक पर जा चढ़ा । वह जिधर से निकला, उधर ही से विनाश का भाहू फेरता पटनाए गया । कर्नल वेली को उसका सामना करने के लिये भेजा गया था, पर उसे अपनी सेना सहित आत्मसमर्पण करना पड़ा । बक्सर की लड़ाई के प्रसिद्ध वीर मुनरों ने भी अपनी तोपें एक तालाब में फेंक दीं और वह मद्रास को भाग गया । हैदरअली की सेना ने मद्रास तक मैदान साफ़ कर दिया । लगभग सारा दक्षिणी भारत हैदरअली के हाथ में चला गया ।

इस समय हेस्टिंग्स ने बड़ी चतुरता से काम लिया । उसने दक्षिणी भारत की तीनों शक्तियों के शत्रु को तोड़ दिया । निजाम को फोड़ कर उसने अपनी ओर मिला लिया और मराठों ने मेल की घातचीत आरम्भ कर दी, जिससे वह निश्चिन्त हो कर कर्नाटक की ओर ध्यान दे सके । मराठों की लड़ाई कुछ समय पहले महत्वपूर्ण अवश्य थी, पर इस समय उसे गौण स्थान दे दिया गया था । बांडीबाश के विजेता सर आयरकूट को बुलाया गया और उसे हैदरअली के विरुद्ध लड़ने वाली सेना का सेनापति

पोर्तो नोवो वना दिया गया । उसने हैदरअली को सन् १७८०
मे, पोर्तो नोवो, पोलीलूर और सोलीघर पर
लड़ाइयों मे हरा दिया ।

परन्तु कुछ समय बीतते ही हैदरअली फिर से ताकतव
हो उठा । उसके पुत्र टीपू को तंजौर के इलाके मे बड़ी सफलत
मिली थी । उसने दो हजार अंग्रेज सिपाहियों की सेना को घे
कर नष्ट कर डाला था । जब उसने उसी साल एक फ्रैच जहाज
को सफरन की अधीनता मे आते देखा तो उसको
हैदरअली वड़ी आशा हुई । मगर भाग्य से इन्हीं
की मृत्यु दिनों हैदरअली मर गया और अंग्रेजों ने छुट
कारा-सा पाया ।

तथापि युद्ध का अन्त अभी नहीं हुआ था । टीपू को फ्रांस
से युद्ध की सामग्री बराबर मिल रही थी, अतः उसने भी लड़ाई
करना बराबर जारी रक्खा । परन्तु दूसरे वर्ष
मंगलोर की यूरोप मे शान्ति हो गई और टीपू को अपने
सन्धि, १७८२ पैरों पर खड़ा होना पडा । हेस्टिंग्स उसे हराने
के लिये सब तरह की कोशिशें कर रहा था, परन्तु मद्रास सरकार
ने सन् १७८४ मे उससे मंगलोर मे सन्धी कर ली । सन्धी की
शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने युद्ध के कैंदियों और एक दूसरे
से जीते हुए प्रदेशों को वापिस सौंप दिया ।

हैदरअली— वहाँ अंग्रेजों के उस घोर शत्रु के कार्य-कलाप

पर भी दृष्टि डालना उचित होगा जो अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम पचास वर्षों में अंग्रेजों के लिए सब से बड़ी आफत था। हैदरअली किसी बादशाह के वंश में से नहीं था, उसका पिता माल-गुजारी का एक साधारण कर्मचारी था। उसे किसी तरह की शिक्षा नहीं मिली थी। वह बर्खा माला तक भी नहीं पढ़ सकता था। पर वह बहुत बड़ा वीर और योद्धा था। प्रारम्भ में मैसूर की सेना के सिपाहियों में भरती होकर क्रमशः वह सेनापति बन गया। फिर एक राज्य का मालिक और अन्त में मैसूर का सुल्तान बन गया।

हैदरअली ने जो कुछ हासिल किया, उस पर अपनी बुद्धि-मत्ता की वदौलत उसने बराबर अधिकार भी बनाए रक्खा। वह सुयोग्य शासक था और राज्य के प्रत्येक महकमे पर निगाहरखता था। वह आतंक बैठाने को बहुत अच्छा समझता था। उसने अपने कई बड़े-बड़े वज़ीरों को सड़कों पर कोड़े तक लगवाए थे। शिवाजी और अकबर की तरह, जो उसी की तरह अनपढ़ थे, ठीक जगह के लिए ठीक ही आदमी चुनने का बुद्धिकौशल भी उसमें चधेष्ट था। उसे किसी तरह की अकतावी शिक्षा नहीं मिली थी, पर उसमें सतर्कता, याददास्त और दृढ़-निश्चय के गुण थे, और इन तीनों के मेल ने उसे एक प्रबल शासक बना दिया था।

चेतसिंह का मामला—हैदरअली और मराठों के साथ युद्ध करते रहने के कारण वारेन हेस्टिंग्स को धन की बढ़ी

हुई । इससे उसने कुछ ऐसे कार्य किये जिनके कारण उसकी घोर निन्दा हुई । सन् १७५५ में अवध के नवाब ने बनारस अंग्रेजों को दे दिया था । अंग्रेजों ने अपनी तरफ से चेतसिंह को बनारस का राजा बना दिया था और वे उससे हर साल साढ़े बाईस लाख रुपया कर लेते थे । सन् १७७८ में वारेन हेस्टिंग्स ने उससे पांच लाख रुपया और मांगा और वाद के दो वर्षों में भी इतनी ही रकम पाने की कोशिश की । राजा ने हेस्टिंग्स के इस तरह रकम मांगने का विरोध किया, पर उसे यह रकम अदा करनी पड़ी । आखिरी रकम अदा करने में कुछ देर हो गई थी, इस लिये वारेन हेस्टिंग्स ने उस पर पचास लाख जुर्माना कर दिया और जुर्माना वसूल करने के लिये वह खुद रवाना हो गया । राजा की गिरफ्तारी पर विद्रोह हो गया और गवर्नर-जनरल को भाग कर चुनार में शरण लेनी पड़ी । अन्त में विद्रोह दबा दिया गया । चेतसिंह भाग कर ग्वालियर जा पहुँचा, अतः उसे गद्दी से उतार कर उसके भतीजे को उसके स्थान पर राजा बना दिया गया और उसे अपने चचा से भी कहीं अधिक कर देना पड़ा ।

अवध की वेगमें—परन्तु इतने से भी कम्पनी के खाली खजाने का खालीपन न भरा और हेस्टिंग्स ने धन पाने के लिये और किसी जगह की ओर निगाह दौड़ाई । अत्र उसने अवध के नवाब वज़ीर से “सहायता” की रकम मांगी जो उसे कम्पनी को देनी थी । उधर आसफुद्दौला अपने पिता के मरने के बाद से अपनी माता और दादी के कब्जे से (जो अवध की वेगमों के

नाम से मशहूर थीं) असंख्य रुपया और जागीर निकालना चाहता था। उसने वारेन हेस्टिंग्स के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि जब तक वेगमों के पास से राज्य का रुपया न निकले वह उसकी रकम न दे सकेगा। नवाब ने सन १७७५ में ही हेस्टिंग्स को काफ़ी बड़ी रकम दी थी और यह बात तय हो गई थी कि उससे फिर कभी कोई रकम न मांगी जायगी। कलकत्ते की कौंसिल ने भी इस बात को बहुमत से पास कर दिया था। हेस्टिंग्स ने वेगमों पर चेतसिंह के साथ मिलकर विद्रोह करने का अभियोग लगाया और आसफुद्दौला को जागीरों और धन पर कब्ज़ा करने का अधिकार दे दिया। कुछ मुकाबला भी किया गया, परन्तु इस मौके पर ब्रिटिश सेना से सहायता ली गई और वेगमों को अपना जमा किया हुआ रुपया दे देना पड़ा। इस तरह वारेन हेस्टिंग्स को ७५ लाख रुपया तो मिल गया, पर उसका यह कार्य उसके लिए बड़ी बदनामी का कारण बना।

हेस्टिंग्स के शासन का अन्त (१७८५) — उसके दीर्घ शासन काल का अन्त आ चला था। वास्तव में उसकी हुकूमत का अन्त मैसूर की दूसरी लड़ाई के बाद ही हो गया था। उसने चेतसिंह और अवध की वेगमों के साथ जो वर्ताव किया था, उसकी कम्पनी के डाइरेक्टरो में बड़ी आलोचना हो रही थी। प्रधान मन्त्री पिट ने भी सन १७८४ के अन्त में उसकी बहुत सी बातों को नापसन्द किया था। हेस्टिंग्स को पता लग गया कि अब उसका उस पद पर अधिक देर तक रहना उचित नहीं

असाधारण योग्यता वाले व्यक्ति के आश्रय पर ही कम्पनी भारत में बराबर अपना सिर उठाए रह सकी ।

उसके मार्ग में अनेक बाधाएं थीं । वह उस समय गवर्नर बना था, जब भारत में कोई उल्लेखनीय शासन-व्यवस्था ही नहीं थी । पर जब वह भारत से वापिस गया तो देश में अशान्ति की जगह शान्तिपूर्ण शासन-व्यवस्था कायम हो चुकी थी इसी कारण उसका नाम “ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन-व्यवस्थापक ” पड़ा । दक्षिण भारत में तीन बड़ी शक्तियां, जिनका मुकाबला करना कम्पनी के लिए आसान नहीं था, आपस में गुटबन्दी कर रही थीं और यह हेस्टिंग्स जैसे कुशल शासक की दूरदर्शिता का ही फल था कि कम्पनी को इस बड़े खतरे का सामना करने की जरूरत ही न रह गई । इसके साथ ही कौंसिल के विरोध का सामना करना भी साधारण बात नहीं थी, इस लगातार विरोध के कारण वह कभी कभी निराश-सा भी हो जाता था । यदि उन दिनों कोई उस से कम दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति उस पद पर होता तो वह अवश्य ही सब कुछ छोड़ भागता । कम्पनी का खजाना खाली था और हेस्टिंग्स को इसी लिए कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़े, जिनके कारण उसके नाम पर ध्वजा लग गया । परन्तु उसने यह सब अपने देश के लिए किया ।

एक अंग्रेज ऐतिहासिक ने हेस्टिंग्स के सम्बन्ध में लिखा है—“वैसी कठिन परिस्थितियों में काम करने वाला ऐसा कोई अन्य मनुष्य नहीं पैदा हुआ जो इतनी हिद्वान्वेगी और प्रतिकूल

आंखों के सामने भी अपना निजी और सार्वजनिक आचरण इतने प्रशंनीय ढंग से शुद्ध बनाए रख सका हो।”

प्रश्न

१. वह्माल का गवर्नर होने पर हेस्टिंग्स को कौनसे असुविधाओं का सामना करना पड़ा और उसने उनका सामना किस ढंग से किया ?

२. उसने जिन जिन सुधारों की भारत में नींव डाली थी, उनके नाम गिनाओ। उसको ‘भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन-व्यवस्थापक’ कहना कहा तक ठीक है ?

३. हैदरअली के आचरण और कार्य-कलाप पर एक नोट लिखो।

४. मराठों की पहली लड़ाई का संक्षेप में वर्णन करो।

५. निम्नलिखित पर नोट लिखो—

नंदकुमार, चेतसिंह, सल्वाई की सन्धी, रेगुलेटिंग ऐक्ट।

६. क्लाइव और हेस्टिंग्स तथा उनकी नीति व कार्यों की परस्पर तुलना करो।



पांचवां अध्याय

लार्ड कार्नवालिस

पिट का इण्डिया बिल - हेस्टिंग्स के शासन काल के अन्त में भारतवर्ष की ओर ब्रिटिश सरकार का काफी ध्यान आकर्षित हो गया था । रेगुलेटिंग ऐक्ट के दोषों के कारण एक और विधान बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई । अमेरिका इंग्लैंड के हाथ से निकल गया था, अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए अङ्गरेज-राजनीतिज्ञों ने भारत का शासन सुधारने और उसे अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ लेने का निश्चय किया ।

इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री पिट ने पार्लियामेंट से एक बिल पास करा लिया, जो " पिट का इण्डिया बिल " के नाम से मशहूर है । इस बिल के पास हो जाने पर कम्पनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों में परस्पर भेद स्पष्ट कर दिया गया । इसके द्वारा दीबानी, सेना और कर सम्बन्धी सारे कार्य

राजनीतिक और
व्यापारिक विभागों
में भेद

के सपुर्द कर दिए गए, जो “बोर्ड आफ़ कंट्रोल” कहलाता था, इसमें छः सदस्य होते थे और उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी।

युद्ध करने और भारतीय नरेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का पूर्ण अधिकार अब इसी बोर्ड को प्राप्त था। हां, व्यापार के मामले में कम्पनी के डाइरेक्टरों को नवीन नीति पहले जैसी सुविधा थी। वाद में लार्ड कार्नवालिस

के जोर देने पर गवर्नर-जनरल को अधिकार दे दिया गया कि वह अत्यन्त आवश्यक कार्यों में कौन्सिल की अनुमति बिना भी काम कर सकता है। गवर्नर जनरल के विरुद्ध गुटबंदी करना असम्भव बनाने के लिए कौंसिल के सदस्यों की संख्या चार से तीन कर दी गई और यह भी घोषित किया गया कि भविष्य में भारत में राज्य-विस्तार की जगह शांति की नीति का पालन किया जायगा।

इस प्रकार कम्पनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहले से भी अधिक नियन्त्रण हो गया और भारत के शासन का अधिकार कम्पनी के हाथ से निकाल कर सम्राट के हाथ में देने की ओर एक और कदम बढ़ाया गया।

लार्ड कार्नवालिस(१७८७—१७९३) — वारेन हेस्टिंग्स ने भारत से जाते समय अपने पद का भार अपनी कौन्सिल के ज्येष्ठ मैम्बर सर जान मैकफरसन को सौंप दिया था। सर जान मैकफरसन वार्डस महीने तक गवर्नर-जनरल के पद पर काम करता रहा। इसके बाद लार्ड कार्नवालिस नामक एक प्रभावशाली लार्ड

और उच्च धाचर्या वाला व्यक्ति गवर्नर-जनरल बनाया गया । इस व्यक्ति पर ब्रिटिश मंत्रियों का पूर्ण विश्वास था । हम पहले ही कह आए हैं कि इसे आवश्यक मामलो मे कौन्सिल के निर्याय को रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया था । साथ ही इसे सेना का कमाण्डर-इन-चीफ भी बनाया गया था । कार्नवालिस भारत मे

तटस्थता की नीति का आरम्भ
 पिट के “इंडिया बिल” के अनुसार तटस्थता की नीति बरतने का निश्चय करके आया था और भारत मे कार्यभार अपने पर लेते ही

उसने यह घोषणा कर दी कि वह अपना ध्यान कम्पनी की कार्य-प्रणाली के सुधार मे लगाएगा और जहाँ तक सम्भव होगा युद्ध से दूर रहेगा ।

उसका इस पद पर नियुक्त किया जाना इस दृष्टि से भी महत्व-पूर्ण था कि इस कार्य के द्वारा भारत मे एक नई नीति का आरम्भ किया गया जो बाद मे भी पालन की जाती रही और आज तक भी वही नीति बरती जाती है । वह यह भी कि भविष्य मे भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल ऐसा पुरुष बनाया जाय, जिसने भारत में पहले कभी कोई नौकरी न की हो ।

सुधार—लार्ड कार्नवालिस का महत्व उसके किए हुए सुधारों मे है । उसके आने से पहले कम्पनी के शासक कर्मचारी

मालगुजारी और न्याय-विभाग सिविल कोर्ट के जज भी होते थे और माल-गुजारी भी एकत्र करते थे । उसने मालगुजारी इकट्ठी करने वाले शासक कर्मचारियों से

न्याय-निर्णय के अधिकार छीन लिए और उनके जिम्मे सिर्फ मालगुजारी इकट्ठा करने का काम ही रहने दिया। न्याय-व्यवस्था के लिये कार्नवालिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की, जिसका प्रधान एक यूरोपियन होता था। ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में चार प्रांतीय अदालतें नियत की गईं, कलकत्ता सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत क्रम से दीवानी और फौजदारी की सर्वोच्च अदालतें रहीं। पुलिस के महकमे का पुनः संगठन किया गया और हर जिले की पुलिस का चार्ज दारोगा को सौंप दिया गया।

कार्नवालिस ने कम्पनी के कर्मचारियों में से नज़रें लेना, निजी व्यापार करना आदि बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। वास्तव में उनकी तनखाहे इतनी थोड़ी थी कि किसी तरह अपनी आय को बढ़ाना उनके लिए स्वाभाविक ही था। कम्पनी के डाइरेक्टर पुरानी प्रथा में परिवर्तन लाने के लिए विवश किए गए और नौकरों के वेतनों में वृद्धि कर दी गई, जिससे वे लोग अपने वेतनों पर ही संतुष्ट रह सकें।

बङ्गाल का स्थायी बन्दोबस्त—लार्ड कार्नवालिस ने बङ्गाल में जो सबसे बड़ा मुद्धार किया, जिसके कारण रमझा नाम चिरम्यायी रहेगा, वह बङ्गाल की स्थायी लगान-व्यवस्था है।

भारतवर्ष सदा से कृषि-प्रधान देश रहा है। इस देश की

आमदनी का मुख्य भाग लगान से ही प्राप्त होता रहा है। उपज का भाग लेने और कर इकट्ठा करने के सम्बन्ध में अलग अलग शासनो में अलग अलग इन्तज़ाम रहे हैं। जब कम्पनी को बङ्गाल की दीवानी मिली तो उसे पता चला कि वहाँ लगान-व्यवस्था लग-भग वैसी ही है, जैसी मुगलो के ज़माने में थी। किसान अपनी उपज का एक निश्चित भाग ज़मींदार को दे देते थे, जो उसे इकट्ठा करके सरकार को देने के प्रतिफल स्वरूप उसका कुछ भाग स्वयं रख लेता था। ज़मींदारी की प्रथा पुश्तैनी-सी हो गई थी। हम देख ही चुके कि वारेन हेस्टिंगज़ ने पांच साल तक लगान का पट्टा नीलाम करने का रिवाज चलाया था। तब बिना किसी हैसियत के आदमी भी नीलाम पर ऊची बोली बोल देते थे, परन्तु वे अपनी बोली की रकम अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए पट्टे की अवधि साल भर करदी गई। मगर इसका भी कोई विशेष अच्छा नतीजा न निकला, क्योंकि इस थोड़ी अवधि से ज़मींदार अनुत्साहित हो गए और ज़मीनो की उपज बढ़ाने की ओर उन्हें कोई उत्साह न रहा। क्योंकि ज़मीन की पैदावार बढ़ने पर उन्हें तो उस में से कुछ मिलना ही नहीं था। कार्नवालिस की राय थी कि ज़मींदारो को विश्वास दिला दिया जाय कि सरकार उनसे जमीनें नहीं छीनेगी और यदि वे अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उपज की शक्ति बढ़ाने में लगाएंगे तो वह मालगुजारी में वृद्धि न करेगी। अतः सन १७६३ में तय किया गया कि सरकारी माल-

गुज्जारी निश्चित कर दी जाय । कान्वालिस की सिफारिशों को इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री और बोर्ड आफ् कन्ट्रोल के सभापति ने स्वीकार कर लिया और उसी साल बङ्गाल में स्थायी बन्दोवस्त की घोषणा कर दी गई ।

इस नई योजना से लगान की व्यवस्था में कुछ स्थिरता आ चली और उससे जमींदारों को जमीन की हालत सुधारने का प्रोत्साहन मिला । अब जमींदारों को लगान की एक निश्चित मात्रा ही देनी पड़ती थी, अतः उपज बढ़ा कर वे अपनी आय बढ़ाते थे । इस तरह धीरे धीरे उनके पास अच्छा धन जमा हो गया । धनी जमींदारों की इस जमात का सरकार को दूसरा लाभ यह हुआ कि इस देश में राजभक्तों की एक जमात पैदा होगई, जिसे अपने हितों की ही चिन्ता रहती थी ।

पर जहाँ कलम की एक गति से इस नए बन्दोवस्त द्वारा जमींदारों को जमीन के स्वामियों के रूप में बदल दिया गया था, वहाँ किसानों के पुराने अधिकारों की पूरी उपेक्षा की गई थी और उन्हें इन नए जमींदारों के रहम पर छोड़ दिया गया था । आगे चल कर नए कानूनी सुधारों से उनकी दशा भी संतोष-जनक बनाई गई । पर कुछ दिनों के बाद कम्पनी और सरकार को यह मालूम होगया कि इस नए बन्दोवस्त द्वारा सरकार को आर्थिक नुकसान होता है । क्योंकि जमीनों की पैदावार तो क्रमशः पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई और जमींदारों की आम-

दनी मे भी वेहद इजाज़ा हो गया, परन्तु सरकार को अभी तक सन १७६३ की मालगुजारी ही मिलती जाती है। अतएव, बङ्गाल के ज़मींदारों की सुविधाएं बनाए रखने के कारण, अपना अपना बजट पूरा करने के लिए भारत सरकार को बहुत दिनों तक शेष भारत पर ज्यादा सख्ती से कर लगाना पड़ा है।

मैसूर की तीसरी लड़ाई (१७९०—१७९२)—

यद्यपि कार्नवालिस की बड़ी इच्छा थी कि शान्ति बनी रहे—और
कारण पिट के ब्रिल ने उसे इसके लिए और भी बाध्य कर दिया था—परन्तु वह मैसूर के साथ कम्पनी के विरोध को दूर न कर सका। सन १७७६ मे टीपू ने ट्रावनकोर नाम की हिन्दू रियासत पर धावा कर दिया और वहां अशान्ति मचा दी। जब वहां के राजा ने, जो ब्रिटिश संरक्षण मे था, ब्रिटिश सरकार से सहायता की प्रार्थना की, तो कार्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध निजाम और मराठो से मेल कर लिया।

मद्रास कौन्सिल ने पहले की तरह युद्ध की तैयारियों मे देर करनी शुरू की। इस पर कार्नवालिस ने दक्षिण पहुँच कर सेना-घटनाएं संचालन का काम स्वयं अपने हाथ में लिया। उसने बङ्गलौर पर अधिकार कर लिया और टीपू को उस की राजधानी से नौ मील दूर, अरीकेर नामक स्थान पर हरा दिया। परन्तु युद्ध-सामग्री खतम हो गई थी इस लिए मित्र सेनाओं को वापिस लौटना पड़ा और कार्नवालिस बङ्गलौर लौट गया। यहां उसने सेना को पुनः तैयार किया और टीपू की राजधानी की

और दुवारा कूच कर दिया। टीपू को सिरद्दापट्टम की ओर खदेड़

सिरद्दापट्टम
की सन्धि

दिया गया, और उस ने युद्ध जारी रखने में
लाभ न देख कर सन्धि की प्रार्थना की। वह युद्ध
की क्षति के एवज़ में तीन करोड़ रुपया और अपना

आधा राज्य देने को राजी होगया। अंग्रेज़ों ने उस के दो लड़के
भी अमानत स्वरूप रख लिए। इस आधे राज्य को मित्र शक्तियों
में बराबर बराबर बांट दिया गया। अंग्रेज़ों के हिस्से में करनाटक,
कीमा और मालावार तट के प्रदेश आए।

सन १७६३ के अन्त में कार्नेवालिस वापस चला गया। वह
दुराचरण का शत्रु था, अतः वह भारत को छोड़ने से पहले
शासन-व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार करने में सफल हुआ था। उस
ने शासन-व्यवस्था को एक नया रूप दे दिया—यह निस्संकोच
होकर कहा जा सकता है।

सर जान शोर (१७९३—१७९८)—यह नियम बना

दिया गया था कि भारत का गवर्नर-जनरल वही व्यक्ति हो सकेगा,

जिसने पहले कभी वहां नौकरी न की हो, पर कलकत्ता
तटस्थता कौन्सिल के एक सदस्य सर जान शोर के लिए यह
की नीति नियम अपवाद के रूप में शिथिल कर दिया गया। उसे

गवर्नर-जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। शोर ने तटस्थता
की नीति का पूरी तरह पालन किया, और उसको इस हद तक
अपनाया कि कुछ लोगो को भारत में ब्रिटिश राज्य के नष्ट होने
तक का खतरा होने लगा। मराठों को यह बात जानने में देर न

लगी कि नया गवर्नर जनरल उनके कामों में रुकावट न डालेगा, इस लिए अब उन्होंने अपने पुराने शत्रु निजाम को कुचलने का निश्चय किया। निजाम ने ब्रिटिश सरकार से सहायता की प्रार्थना की। पर सर जान शोर अपनी धुन का पक्का था, उसने किसी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। निजाम को मराठों से चर्खा अकेले लड़ना पड़ा और सन १७६५ में उसकी बुरी तरह हार हुई। निजाम को अंग्रेजों के इस विश्वासघात पर क्षोभ हुआ, उसने अपने राज्य से ब्रिटिश सेना को बर्खास्त कर दिया और अपनी सेना की शिक्षा के लिए एक फ्रेंच अफसर रख लिया।

सन १७६७ में अवध के नवाब आसफुद्दौला की मृत्यु हो गई और गद्दी के लिए झगडा उठने पर शोर ने अपनी नीति में कुछ शिथिलता कर दी। उसने पिछले नवाब के भाई सआदतअली को अवध की गद्दी पर बैठा दिया और उसके साथ सन्धि करली। कम्पनी ने ७६ लाख रुपये सालाना पर अवध की रक्षा का भार अपने जिम्मे ले लिया।

सर जान शोर ने अपने शासन-काल में तटस्थता की जिस नीति का अनुसरण किया, उससे जहां कम्पनी के व्यापार को बड़ा लाभ पहुँचा, वहां उसका सैनिक रोव अवश्य कम होगया। अब तक भारत में अंग्रेजी सेना अपने भंगठिन और चतुरता पूर्ण आक्रमणों के कारण यहां के अन्य शासकों के लिये भय का कारण बनी हुई थी। परन्तु सर जान

शोर की इस नई रीति के कारण उनका डर धीरे धीरे कम होने लगा । परिणाम यह हुआ कि टीपू सुल्तान और मराठे अपना बल बढ़ाने लगे । इसी बीच में सन १७६३ में सर जान शोर को त्यागपत्र देकर इंग्लैंड लौट जाना पड़ा । उन दिनों उत्तर भारत में महादजी सिधिया का बोलवाला था, उसकी सेना में फ्रेंच लोग भी थे । दक्षिण में मराठे अपना राज्य-विस्तार कर रहे थे और उधर टीपू सुल्तान कावुल के अमीर के साथ सन्धि स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था ।

प्रश्न ।

१. पिट के इण्डिया बिल पर एक नोट लिखो ।
२. बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विशेष रूप से जिक्र करते हुए लार्ड कार्नवालिस के शासन का संक्षिप्त विवरण लिखो ।
३. सर जान शोर के शासन में जिस तटस्थता की नीति का पालन किया गया था, उसके परिणाम दिखाओ ।



छठा अध्याय

लार्ड वैलज़ली (१७९८-१८०५)

भारत का नया गवर्नर-जनरल लार्ड मारोंगटन (बाद को लार्ड वैलज़ली) भारत में विजय कार्य और साम्राज्य-सीमा के विस्तार का काम जारी रखने के उद्देश से नहीं अप्रसन्न नीति आया था, किन्तु तत्कालीन नाजुक अवस्था ने, जिसका वृत्तान्त हमने पिछले अध्याय में देने की चेष्टा की है, उसे विश्वास दिला दिया कि भारत में एक ऐसी शक्ति का होना अत्यावश्यक है, जो सब से अधिक सामर्थ्य रखती हो, जिसके आदेशों का सब पालन करे, और जो विभिन्न शक्तियों को आपस में युद्ध करने से रोक सके। लार्ड वैलज़ली ने अपने देश के लाभ के लिए सोचा कि ऐसी शक्ति अंग्रेजों की ही हो सकती है। अतः शासन काल के इतिहास में तटस्थता की नीति के स्थान पर एक नई ही नीति बरती गई।

उसने अपना उद्देश पूरा करने के लिए एक ऐसी आयोजना अपनाई, जो बाद को सहायता सम्बन्धी व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध

हुई। वह सम्पूर्ण देशी नरेशों के सामने, जिनसे सहायता-विधान अंग्रेजों का किसी भी तरह का सम्बन्ध रह चुका था, सन्धि के प्रस्ताव रखना चाहता था, इस का उद्देश्य यह था कि वे सब भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठ सत्ता स्वीकार कर लें। उसने उन्हें लिखा कि वे अपनी रक्षा का भार अंग्रेजों को सौंप दें, अपने राज्यों में एक अंग्रेजी सेना रखें और उसका खर्च खुद उठाएं। इस सेना का प्रधान कर्तव्य यह होगा कि वह उनके शत्रुओं से रियासत की रक्षा करे और रियासत के भीतर शान्ति बनाए रखे। वैलजलो ने सम्पूर्ण देशी नरेशों के सामने यह आयोजना भी रखी कि कोई रियासत दूसरी किसी रियासत के साथ बिना अंग्रेजों की सम्मति के, आक्रमणकारी या आत्म-रक्षात्मक विग्रह या सन्धि न करे। सब नरेशों को अपने दरबारों में एक एक अंग्रेज रेजीडेण्ट को भी स्थान देना होगा। इस सेना के व्यय को "सहायता" का नाम दिया गया था, अतः यह व्यवस्था भी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था (Subsidiary Alliance) कहलाई जाने लगी।

इस सन्धि के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाला पहला नरेश हैदराबाद का निज़ाम था। उसे मराठों के निज़ाम ने सहायता हाथों काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी, इस व्यवस्था स्वीकार को लिए वह अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के लिए बहुत इच्छुक था।

मैसूर की चौथी लड़ाई (१७९९) — अब गवर्नर

जनरल ने अपना ध्यान टीपू की ओर केन्द्रित किया। उस समय

कारण मिश्र से फ्रैंच सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट भारत पर

अधिकार करने का स्वप्न देख रहा था, अतः टीपू के

फरासीसियों से मुलह कर लेने पर अंग्रेजों में घोर आतंक फैल गया

था। वैलजली ने टीपू से फ्रैंचों के साथ समझौता करने की

कैफियत मांगी, इसका उसने जो उत्तर दिया, वह निरर्थक और

टालमटोल करने वाला समझा गया, और उस पर चढ़ाई कर दी गई।

एक प्रबल सेना, जिसके साथ निज़ाम की भी थोड़ी-सी फौज थी,

जनरल हेस्टिंग्स के सेनापतित्व में मद्रास से चल पड़ी। उधर बम्बई

से जनरल स्टुअर्ट के मातहत एक साधारण-सी सेना भी चली।

स्टुअर्ट से टीपू की मुठभेड़ सन्दासिर में हुई। यहाँ टीपू बहुत कुछ

क्षति उठा कर पीछे हट गया। इसके बाद उसने मद्रास वाली सेना

से मेलपेली में युद्ध किया। यहाँ भी उसकी हार हुई और वह

अपनी राजधानी को चला गया। वहाँ भी घेरा

डाल दिया गया और भयकर संघर्ष के बाद

रगपट्टन पर अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार उस पर अंग्रेजों

का अधिकार हो गया। लड़ाई में टीपू बहादुरी के साथ लड़ता

हुआ मारा गया।

उसके राज्य का मध्यभाग उसी पुराने हिन्दू राजवंश को सौंपा

गया, जिसे गद्दी से उतार कर टीपू का बाप खुद मालिक बन बैठा

था। उक्त राजवंश का वंशज कृष्णराज

ओडयर एक पांच वर्ष का बालक था। उसे

गद्दी पर बैठाया गया और एक "बलीयों की

प्राचीन हिन्दू राज-
वंश की स्थापना

था। उक्त राजवंश का वंशज कृष्णराज
ओडयर एक पांच वर्ष का बालक था। उसे
गद्दी पर बैठाया गया और एक "बलीयों की

से उसका विस्तार करने का प्रयत्न किया। तंजौर में तंजौर गडबड थी। यह कहा गया कि वहाँ की प्रजा पर अत्याचार किया जाता था। साथ ही वहाँ के राजा के मरने के बाद राज्य के उत्तराधिकारी के विषय में झगडा उठ खड़ा हुआ था। लार्ड वैलजली ने मृत राजा के पुत्र को पेशवा दे दी और तंजौर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। दूसरे वर्ष कर्नाटक कर्नाटक के नवाब को भी इस आधार पर सिंहासन और सूरत से उतार दिया गया कि उसने टोपू सुल्तान से विश्वासघातपूर्ण पत्र-व्यवहार किया था। सूरत के नवाब की भी यही दशा हुई।

मराठे—जिस समय वैलजली ने शासनाधिकार अपने हाथ में लिया, उस समय मराठों के राज्य में अशांति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। महादजी सिंधिया का मृत्यु हो गई थी और उसकी जगह दौलतराव सिंधिया सिंहासन पर बैठ चुका था। माधवराव ने नाना फडनवीस के नियन्त्रण से उकता कर सन् १७६५ में आत्महत्या कर ली थी और अब राघोवा के लडके द्वितीय बाजीराव को पेशवा बना दिया गया था। उसमें और नाना फडनवीस में—जिसने राघोवा के पिता के अधिकारों का विरोध किया था—आपस में अच्छे भाव नहीं थे। नाना फडनवीस इस नए पेशवा के हाथों काफी अपमानित होकर मर गया, और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र की बुद्धि और विवेक

नाना फडनवीस
की मृत्यु

अब दोनों ने मिल कर अपने प्रधान पुरुष के रक्तक के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया, जिससे मराठों के उज्ज्वल नाम पर धब्बा न लगने पाए ।

मराठों की दूसरी लड़ाई (१८०३-१८०५)—

दक्षिण और हिन्दुस्तान के युद्ध, प्रधान युद्ध थे । दक्षिण के युद्ध के लिए सेनापति का भार आर्थर वैलजली को सौंपा गया और हिन्दुस्तान की लड़ाई का भार जनरल लेक के सुपुर्द हुआ । आर्थर वैलजली ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और ऐसेई नामक स्थान पर घमासान युद्ध के बाद ऐसेई और सिधिया और भोसले की सम्मिलित शक्ति को हरा आरगाव दिया । उत्तर में जनरल लेक ने अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के किले की दीवारों के निकट सिधिया की सेना को हरा दिया । शाह आलम लाहवागि अंग्रेजों के हाथ में पड़ गया और इसके कुछ दिनों बाद ही सिधिया की सेना को लासवारी में हरा दिया गया ।

इस विजय के बाद अंग्रेजों का सिधिया के साथ युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि वर्ष के अन्तम दिन, सूरजी अरजनगांव नामक स्थान पर, सिधिया सहायता सम्बन्धी व्यवस्था पर दस्तखत करने को राजी हो गया । उसने बरोच का बन्दरगाह, अहमदनगर का बन्दरगाह तथा गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश—ये सब

स्थान अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिए। इधर देवगांव और अरजन-भोसला ने भी अरगांव में हार खाकर गाव की सन्धिया देवगाँव में अंग्रेजों से सन्धि कर ली थी। उसने वरार और कटक के प्रदेश कम्पनी के सुपुर्द कर दिए।

होल्कर के साथ युद्ध—अब केवल जसवन्तराव होल्कर ही एक ऐसा राजा शेष बचा था, जिसने अभी तक हार नहीं मानी थी। अंग्रेजों के हित की दृष्टि से यह अत्यावश्यक था कि उसका अंग्रेजों के साथ कोई न कोई समझौता हो जाय। परन्तु सन्धि के लिए होल्कर ने जो शर्तें पेश कीं, उन्हें वैलजली ने स्वीकार नहीं किया। अतः उसने अंग्रेजों के मित्र राजपूत राजाओं के देशों को रौंद डाला। इस पर गवर्नर जनरल ने होल्कर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

आरम्भ में अंग्रेजों की क्षति हुई। कर्नल मानसन राजपूताने में बहुत आगे बढ़ गया था। उधर नदियों में बाढ़ आई हुई थी। उसे बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। मानसन को भारी हार खानी पड़ी और मुकन्दरा के दर्रे में तो उसकी तीन सेनाएं

बिल्कुल ही नष्ट हो गईं। इस पर होल्कर की धारणा होगई डीग कि जिस शक्ति से सिधिया और भोसला परास्त होगए उसे शायद वह जीत सकेगा। परन्तु उसे जनरल लेक ने फरुखाबाद और डीग में हरा दिया। तथापि लेक भरतपुर का किला विजय करने में असफल रहा और उसकी सेना को बार बार पीठ दिखानी पड़ी। इसलिए उसे वह यश न मिल सका। अंग्रेजों के साथ

भरतपुर का घेरा

तीन महीनों तक युद्ध करने के बाद होल्कर युद्ध से अक गया और उसने भी सन्धि करली। इसी नाज़ुक मौके पर वैलज़ली को भारत से लौट जाना पड़ा, होल्कर के लिये यह अच्छा ही हुआ, अन्यथा सम्भव था कि उसकी भी वही दशा होजाती, जो अन्य मराठा नरेशों की हुई थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टर इस तरह कम्पनी की तरफ से युद्ध होते रहने की नीति का बहुत दिनों से विरोध कर रहे थे, क्योंकि इससे उनके हिस्सों के मुनाफे पर असर पड़ने की सम्भावना थी। फर्नल मानसन की हार के बाद उन्हें यह कहने का

अवसर मिल गया कि स्वयं ही किसी से युद्ध

वैलज़ली को वापस

शुरू कर देने में केवल धन ही का व्यय नहीं

बुलाया गया

होता, वह निष्फल भी साबित हो जाता है।

और यह विरोध इतने प्रबल रूप से किया गया कि सन १८०८ में लार्ड वैलज़ली को भारत से वापस बुला लिया गया।

वैलज़ली के कार्य—वैलज़ली ने भारत में जो काम किए थे, उनके कारण उसकी गणना अंग्रेज़ी हुकूमत के प्रमुख शासकों में की जाती है। जिस समय उसने शासन की वागडोर अपने हाथ में ली, उस समय भारत में आंतरिक युद्ध जारी थे, जिनसे ब्रिटिश राज्य के विस्तार के लिए बड़ी मदद मिल सकती थी। वह ताड़ गया कि पिट के कानून की नीति, कार्नवालिस और शोर की नीति, साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, अतः उसने उसे त्याग दिया। उसे यह समझ आगया कि

भारत में अंग्रेज़ लोग इनने बढ़ आए हैं कि अब इस देश की सब से बड़ी शक्ति बन सकते हैं। साथ ही उसका यह विचार भी था कि यदि हम इस अनुकूल परिस्थिति से लाभ न उठाएंगे तो हमारे स्थान पर कोई और लाभ उठा लेगा। और कोई नहीं तो फ्राँसीसियों की नेपोलियन के नेतृत्व में बढ़ती हुई शक्ति भारत में अंग्रेज़ों के अस्तित्व को खतरे में डाल देगी।

वैलज़ली के सारे कार्यों का प्रधान उद्देश भारत में कम्पनी की सत्ता स्थापित करना था। उसने इस काम के लिए जो तरीके चरते, उनकी सफलता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि जिस समय वह यहाँ से गया उस समय तक अंग्रेज़ भारत में प्रधान शक्ति बन चुके थे। उसने टीपू का पतन कर दिया, निज़ाम से अधीनता स्वीकार करवाली और मराठों का संव तोड़ दिया। उससे पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य भी था, पर उसके जाने के बाद यहाँ केवल ब्रिटिश साम्राज्य ही रह गया। कम्पनी के डाइरेक्टरों ने उसकी शासन विस्तार की नीति को नापसन्द किया, पर बाद के इतिहास ने यह साफ़ बता दिया कि वैलज़ली ने जो कुछ किया, उससे भारत में अंग्रेज़ी शासन पूरे रूप में कायम हो गया।

प्रश्न

1. वैलज़ली ने उदासीनता की नीति को क्यों त्यागा ?
2. भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने में वैलज़ली का कितना

हाथ था ?

३. मराठों की दूसरी लड़ाई का हाल संक्षेप में लिखो ।

४. इन पर संक्षिप्त नोट लिखो—

टीपू सुल्तान, महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस ।



सातवां अध्याय

सर जार्ज बारलो और लार्ड मिंटो

लार्ड कार्नवालिस को पुनः भारत का गवर्नर-जनरल बनाकर भेजा गया और उसे हिदायत की गई कि वह भारत में उदासीनता की नीति से काम ले। परन्तु इस बार वह कुछ अधिक कार्य न कर सका, क्यों कि भारत में आने के तीन महीने बाद ही उसका देहान्त हो गया।

सर जार्ज बारलो (१८०५-१८०७)—सर जार्ज बारलो कौन्सिल का प्रधान सदस्य था। वह उदासीनता की नीति का बड़ा हिमायती था। लार्ड कार्नवालिस के बाद उसी को गवर्नर-जनरल बनाया गया। उसने अपने शासन के प्रारम्भ में ही होल्कर के साथ, सुविधा-जनक शर्तों पर सन्धि स्थापित करली। सिधिया के साथ एक नई सन्धि की गई, जिसके अनुसार उसे कुछ नवीन प्रदेश मिले। कुछ राजपूत रियासतों से ब्रिटिश संरक्षण हटा लिया गया। पहले

उन्हें सिधिया और होल्कर के आक्रमणों से बचाने का आदेशों ने वचन दिया हुआ था।

बारलो के शासन काल की एक और महत्वपूर्ण घटना वेलोर के सैनिकों का विद्रोह था। [सेना में कुछ परिवर्तन किए गए थे। सिपाहियों को आदेश दिया गया कि वे वेलोर का सिपाही एक खास तौर का साफ़ा बांधें, खास ढङ्ग से विद्रोह दाढ़ी के बाल कटाएँ, कानों में छल्ले न पहिने, और क़वायद के समय जाति-सम्प्रदाय-सूचक चिह्न माथे पर न लगाएँ। इसका अर्थ सिपाहियों ने यह लगाया कि उन्हें धर्मभ्रष्ट करके ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने विद्रोह कर दिया और लगभग सौ सैनिकों को क़त्ल कर डाला। किन्तु, इसी विद्रोह को बड़ी सख्ती के साथ दबा दिया गया। टीपू के पुत्र वेलौर ही में रहते थे। यह सन्देश किया गया कि भगाड़े की जड़ ये लोग ही हैं। अतः उन्हें कलकत्ते में भेज दिया गया। लार्ड विलियम बैंटिक उस समय मद्रास का गवर्नर था। उसे वापस बुला लिया गया।

लार्ड मिण्टो (१८०७-१८११)—बारलो के बाद सन १८०७ में लार्ड मिण्टो आया। उसे भी हिदायत की गई कि वह अपने पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल की नीति बरते, पर भारत में आने के कुछ ही दिनों बाद उसने यह अनुभव किया कि इस नीति से ब्रिटिश रोबदाब को धक्का पहुँच रहा है। उसका शासन साफ़ तौर से प्रकट करता है कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में वह स्वयं युद्ध

कर दिया। इस प्रकार वहां विद्रोह मच गया।
 ट्रायनको परन्तु इसका शीघ्र ही दमन कर दिया गया।

विदेशी शक्तियों के सम्बन्ध में नई नीति—पर लार्ड
 मिण्टो ने विदेशी शक्तियों के—विशेष कर सिक्ख शक्ति के—
 साथ जिस ढङ्ग की नीति बरती, उससे पता चलता है कि वह
 उदासीनता की नीति पसन्द नहीं करता था।

हम यह पहले ही कह आये हैं कि किस प्रकार सिक्ख
 सम्प्रदाय, जो प्रारम्भ ने एक धार्मिक सम्प्रदाय-मात्र था, सैनिक
 शक्ति के रूप में बदल गया। जब पानीपत की तीसरी
 सिक्ख लड़ाई के बाद अहमदशाह अब्दाली अफ़गानिस्तान
 में वापिस चला गया, तो सिक्खों को अपनी शक्ति बढ़ाने का
 मौका मिला। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए छोटे छोटे दल बनाए।
 परन्तु, यद्यपि वे आत्मरक्षा अच्छी तरह कर सकते थे, तथापि
 उनमें कभी कभी आपस में भी मारकाट हो जाती थी और उनमें
 उस सघ-शक्ति का भी अभाव था, जिससे वे कोई बड़ो शक्ति
 बन सकते।

रणजीतसिंह—इस अभाव को एक सिक्ख राजा के
 पुत्र रणजीतसिंह ने पूरा किया। उसने इन विभिन्न दलों का एक
 शक्तिशाली संघ स्थापित किया। मुगल साम्राज्य
 उल्लेखनीय के नाश के बाद जिन राजाओं ने शक्ति प्राप्त की,
 कार्यकलाप उनमें रणजीतसिंह विशेष उल्लेखनीय है। वह

सन १७८० में पैदा हुआ था। वह बारह वर्ष की उम्र में ही अपने पिता की छोटी-सी जागीर का मालिक बनाया गया। अकबर और शिवाजी की तरह उसे भी पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला। उसमें भी इन दोनों महापुरुषों की तरह जन्म ही से लोगों का नेतृत्व करने और शासन प्रबन्ध करने की असाधारण योग्यता थी। जब यह युवा ही था, तो अहमदशाह अब्दाली के पुत्र ज़मानशाह का ध्यान उसकी ओर खिंचा और उसने सोलह वर्ष की आयु में ही उसे लाहौर का सूबेदार बना दिया। तीन वर्ष के भीतर वह आज़ाद हो गया। उधर अफ़ग़ानों में घरेलू युद्ध हो रहे थे। उन्हें रणजीतसिंह की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं था। रणजीतसिंह ने ३०,००० सिपाहियों की एक बढ़िया-सी सेना यूरोपियन ढङ्ग पर तैयार की और उसकी सहायता से अपना राज्य सतलुज तक बढ़ा लिया।

कुछ समय तक सतलुज उसके राज्य की उत्तरी सीमा रही। सन १८०६ में कुछ सिक्ख सरदारों में, जिन्हें सतलुज और यमुना के बीच में जागीरें मिली हुई थीं, आपस में झगड़ा हो गया और उन्होंने रणजीतसिंह से फ़ैसला करने को कहा। इस पर उनके विरोधियों ने ब्रिटिश सरकार से अपील की, क्योंकि यह प्रदेश (जो कुछ समय सरहिंद के नाम से मशहूर रहा था और जिस पर किसी समय सिंधिया का अधिकार था) सिंधिया की पराजय के बाद अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था। लार्ड मिण्टो अपने पड़ोस में सिक्ख शक्ति को प्रबल होने देना

अमृतसर की सन्धि नहीं चाहता था। अतः उसने समझौते के लिये सैटकाफ़ को पंजाब में भेजा। बहुत कुछ वादविवाद के बाद सन् १८०६ में अमृतसर में एक सुलहनामा तैयार किया गया, जिसके अनुसार सतलुज नदी को सिक्खों के राज्य की सीमा मान लिया गया। रणजीतसिंह ने सरहिंद पर से अपना हाथ उठा लिया और इस प्रकार दोनों शक्तियों में मित्रता स्थापित हो गई।

नील और ट्रैफ़लगर के युद्ध के बाद अब फ़राँसीसियों के लिये भारत पर सामुद्रिक मार्ग से चढ़ाई करना असम्भव हो गया था। परन्तु ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को अब एक फ़रासीसियों की ओर दिशा से भय हो गया था। उन्हें ओ से आशंका फ़ारस और अफ़ग़ानिस्तान की ओर से हमले की आशंका थी। तिलसिट की सन् १८११ की शांति-स्थापना के अनुसार रूस ने फ़्रांस को यूरोप में मनमानो करने और फ़्रांस ने रूस को एशिया में मनमानी करने की छुट्टी दे दी थी। इस कारण अमेज़ और भी अधिक शक्ति थे। भारत पर रूस और फ़्रांस की गृध-दृष्टि देखकर लार्ड मिण्टो ने फ़ारस को अपना एक दूत भेजा। उधर इंग्लैंड से भी होम गवर्नमेण्ट ने फ़ारस को एक दूत भेज दिया था। अब दोनों में झगडा उठ खड़ा हुआ। अन्त में फ़ारस का शाह इस बात पर राज़ी हो गया कि वह किसी यूरोपियन शक्ति को अपने राज्य की सीमा में से नहीं गुजरने

देगा। इसके बाद मिण्टो ने फाबुल के शासक शाहसुजा और मिन्य के जमीनों के पास भी इसी सम्बन्ध में दूत भेजे और उन से मित्रता स्थापित करती।

सामुद्रिक आक्रमण—गवर्नर जनरल मिण्टो इनने हीमें गन्तु न रहा। फ्रेंच-भग के विरुद्ध दूत भेजने के बाद उगने हिन्द-महासागर के फर्मीमियों द्वारा अधिष्ठित द्वीपों को हस्तगत करने के लिये एक सामुद्रिक सेना भेजी। इन द्वीपों में आकर फ्रेंच सामुद्रिक सेना ब्रिटिश व्यापारियों पर आमानी में आक्रमण कर सकती थी। बोरबन मारीशस के द्वीप अंग्रेजों के अधिकार में आया। मारीशस द्वीप अब भी अंग्रेजों के पास ही है। इसके बाद एक और सेना भेजी गई, गवर्नर जनरल स्वयं इस सेना के साथ गया। इसमें जाया पर अधिकार किया। उस पर उस समय तुर्कों का कब्जा था और तुर्क फर्मीमियों से मिले हुए थे।

कम्पनी का नवीन अधिकार पत्र (१८१३)—सन १७७२ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पूर्वे में व्यापार करने का वास वर्षान्त के लिये जो अधिकार द दिया गया था, वह सन १७७३ में समाप्त हो गया। ब्रिटिश जनता ने आपत्त किया कि इस व्यापारिक अधिकार को अब स्पष्ट किया जाय और व्यापार का आसक्त हो दिना सन १७७३ अगस्त कम्पनी को बीस वर्षों के लिये व्यापार करने का अधिकार द दिया जाय, पान्तु जगत में व्यापार करने की सब से स्वतंत्रता हो गई। जिस प्रकार नवीन अधिकार पत्र दिया गया, उस समय फर्मीमियों ने

कम्पनी के डाइरेक्टरों को आदेश दिया कि वे भारत की शिक्षा के लिये कम से कम दस हजार पौण्ड सालाना अवश्य खर्च करें। अब तक उनके राज्य में पादरियों को जाने की आज्ञा नहीं थी। अब उनके लिये भी कोई रुकावट न रही। इसके थोड़े ही दिनों बाद शिक्षा के क्षेत्र में और लोग भी आगे बढ़े। सन १८१६ में डेविड हेयर और ब्रह्म समाज के प्रवर्तक भारतीय समाज-सुधारक राजा राममोहन राय के प्रयत्न से कलकत्ते में हिन्दू कालेज स्थापित किया गया।

प्रश्न

१. बेलोर के गदर पर एक संक्षिप्त नोट लिखो।
२. महाराजा रणजीतसिंह के कार्य-कलाप का वर्णन करो। सन १८०९ को अमृतर की सन्धि किस कारण से हुई ?
३. मिष्टो का विदेशी शक्तियों के साथ कैसा सम्बन्ध रहा ?



आठवां अध्याय

मार्क्स आफ़ हेस्टिंगज़ और लार्ड एम्हर्ट (१८१३-२८)

बेल्जियम में लेफ़्ट हेस्टिंगज़ तक के शासन का
पर्यालोचन--बेल्जियम ने भारतवर्ष में जो नीति स्वीक
र दी, उसका परिणाम यह हुआ कि उसके लौटने तक अंग्रेज
भारतवर्ष की सभ से बड़ी शक्ति बन गए । उसकी, एक
के साथ मिल कर दूसरी शक्ति को पर
तदनुसार ही कर देने की नीति का जहां यह प्रभाव
नेति का प्रभाव । कि धीरे धीरे अंग्रेजी राज्य बहुत वि
शाल, बड़ा उसका एक प्रभाव यह भी हुआ कि कम्पन
आपस आसनाय अकल्प होने लगा । इसी कारण कम्प
हानेच्छा में भारत के अर्थों अनुरोध को धारित किया ।
बेल्जियम की नीति में कारण । अन्ततः प्रभाव की दिशा में
अन्ततः भारत के अर्थों की नीति में अन्ततः अन्ततः अन्ततः
अन्ततः अन्ततः पर ही पर अन्ततः अन्ततः अन्ततः २ ११

की नीति को नहीं छोड़ा। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि देश की तत्कालीन छोटी छोटी शक्तियां निर्भय होकर बढ़ने का प्रयत्न करने लगीं। मराठे, राजपूत, गोरखे, सभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गति करने लगे। खास तौर से मध्य भारत में तो ठगों के गिरोहों ने बिलकुल अराजकता मचा रखी थी। उन्हीं दिनों मार्किस हेस्टिग्स भारत में आया। जब उसने देखा कि इस देश में अपना राज बढ़ाने का खूब खुला अवसर है, तो वह भी वैलजली की तरह से इस मौके का उपयोग उठाने से न चूका। परिणाम यह हुआ कि तटस्थता की नीति व्यवहारिक रूप में पुनः टूट गई।

नैपाल के साथ युद्ध (१८१४-१८१६)—जिस समय हेस्टिग्स ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली उस समय, स्वयं उसी के शब्दों में, भारत में इस तरह के सात झगड़े थे, जिनमें हथियारों द्वारा ही फैसला होना सम्भव था। इन सातों में सब से अधिक गम्भीर भलाड़ा गोरखों के सम्बन्ध में था, जिन्होंने सन १७६८ में राजपूतों के प्राचीन राज्य पर अधिकार कर लिया था। साथ ही वे पूर्व की ओर से भूटान और पश्चिम की ओर से सतलुज की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। उनका साहस इतना बढ़ गया कि सन १८१४ में उन्होंने दो ब्रिटिश जिलों पर अधिकार कर लिया। हेस्टिग्स ने उन्हें ब्रिटिश सरहद्द कारण से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी, इस पर जब वे वापिस न गए तो उनके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी गई।

निश्चय हुआ कि गोरखा राज्य पर ब्रिटिश सेना चारों ओर से घावा करे। परन्तु प्रारम्भ में देश के अपरिचित होने के कारण और गोरखों के खूब बहादुरी से युद्ध करने की वजह से उन्हें घटनाएं अनेक कष्ट उठाने पड़े। हाँ, पश्चिम में जनरल ओकटरलोनी ने सारी रुकावटों को पार करके ब्रिटिश क्षति की पूर्ति कर दी। उसने गोरखों के सरदार अमरसिंह को मैलोन मलौन के किले में चारों ओर से घेरा डालकर बन्दी कर दिया और अन्त में विवश होकर उसे आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। अब गोरखों ने शांति की इच्छा प्रकट की, परन्तु उनके आगे जो शर्तें रखी गईं, वे इतनी कठोर थीं कि गोरखे उन्हें मंजूर न कर सके और दोनों ओर से पुनः कशमकश जारी हो गई। उधर जनरल ओकटरलोनी बराबर आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसने गोरखों को कई बार हराया और अब गोरखों को अपनी राजधानी तक की रक्षा के विषय में आशंका होने लगी। उन्होंने पुनः समझौते का प्रस्ताव किया। सन १८१६ की सगोली की सन्धि के अनुसार वे तराई से निकल जाने और अंग्रेजों को कमाऊँ, गढ़वाल, देहरादून और शिमला के आसपास का प्रदेश देने को राजी हो गए। इन पहाड़ी इलाकों के मिल जाने से शिमला, नैनीताल और मसूरी आदि पहाड़ी नगर बसाए गए, जिनकी बढ़ती प्रचण्ड गर्मियों में अंग्रेजी सरकार के कर्मचारियों को वहाँ जाने का सुभीता होगया है। उस समय से अब तक नैपाल ब्रिटिश सरकार

का घरावर मित्र रहा है, और उसने भारतीय सेना में अपने हज़ारों वीर गोरखे भर्ती कराये हैं।

पिडारियों का विनाश—अब हेस्टिंग्स का ध्यान पिडारियों की ओर गया। उन्होंने मध्य भारत में अशांति मचा रखी थी। ये अनिश्चित ढंग से लड़ाई करते थे। किसी खास जाति या श्रेणी से इनका सम्बन्ध नहीं था। उनमें परस्पर केवल एक ही सम्बन्ध था—दस्युवृत्ति प्रहण करना। वर्षा ऋतु के समाप्त होजाने पर वे अपने घोड़ों पर सवार होकर जिधर निकल जाते, उधर ही ब्रह्मि और बर्बादी के सिवाय और कुछ नज़र न आता। जब हम इतिहास में यह देखते हैं कि गांव वाले इन डाकुओं के निर्दय पंजों से बचने के लिये अपने घरों में खुद आग लगा लेते थे और उनमें अपनी स्त्रियों और बच्चों समेत भस्म हो जाते थे, सैकड़ों स्त्रियां उनके पाशविक हाथों में पड़ कर शर्मनाक अपमान होने के भय से कुओं में कूद कर जीवन समाप्त कर लेती थीं, तो उन दिनों के विनाश का भयानक चित्र आंखों के सामने खिंच जाता है। इन लोगों को नष्ट करना वास्तव में बहुत लाभ-कर सिद्ध हुआ।

हेस्टिंग्स मध्यभारत के ठगों को दवाने के लिये बड़ा इच्छुक था, परन्तु सब से पहले उसे डाइरेक्टरों की अनुमति लेनी थी।

सिंधिया और होल्कर की सेनाओं में पिडारी लोग भी काफ़ी संख्या में थे, उन्हें दण्ड देने से आशंका थी कि कहीं उनके संरक्षक न विगड़ खड़े हों। यही कारण था कि

डाइरेक्टर दुविधा में पड़े हुए थे और यह विरोध मोल न ले चाहते थे। परन्तु क्रमशः पिण्डारियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि वे ब्रिटिश इलाकों में भी बढ़ कर हाथ मारने लगे और ऐसे निर्दयतापूर्ण कार्य करने लगे कि डाइरेक्टरों को राय भी उन अपने अधीन कर लेने के पक्ष में हो गई और उन्हें दवाने व हेस्टिगज़ को पूरा अधिकार दे दिया।

हेस्टिगज़ ने इस आक्रमण के लिये आवश्यक प्रबन्ध जल्द से कर डाला। वह पिण्डारियों को केवल दवाना ही नहीं चाहता था, वह उनका मूल से विनाश करना चाहता था। तैयारियाँ उससे जहाँ तक हो सका, उसने पिण्डारियों को राजपूतों और मराठों की रक्षा से वंचित किया। १,२०,००० आदमियों की एक सेना एकत्र की गई, जिसमें बड़े बड़े वीर ब्रिटिश सैनिक भी सम्मिलित थे। इस प्रकार यह सेना अब तक भारत में एकत्र की गई सम्पूर्ण ब्रिटिश सेनाओं से अधिक बलशालिनी बन गई। इस कार्य में गवर्नर जनरल ने स्वयं भी भाग लिया। सन् १८१७ की हेमंत में हमला आरम्भ किया गया और दूसरे वर्ष की हेमंत तक सारा कार्य समाप्त हो गया। जिन डाकुओं को मैदान में नहीं मारा जा सका, उन्हें घरों में घेर कर टुकड़े टुकड़े कर डाला गया। ठगों के प्रधान प्रधान मुखियाओं में से एक करीम था, जो आत्मसमर्पण करके शांति के साथ एक बड़ी जागीर में रहने लगा, दूसरा वासिल था, जिसने आत्महत्या कर ली, तीसरा

चीतू था, जो जंगलों में भाग गया, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ उसे एक चीते ने समाप्त कर दिया ; इन सब कार्य में सफलता के सरदार अमीरखाँ ने जागीरदार होना मंजूर कर लिया, और उसे टांक का नवाब बना दिया गया ।

मराठों की तीसरी (अन्तिम) लड़ाई १८१७—

१८१९)—जैसा कि हेस्टिंग्स को पहले ही सम्भावना थी इस विनाश कार्य से अंग्रेजों की मराठों के साथ एक बार पुनः लड़ाई छिड़ गई । यह कहा ही जा चुका है कि बाजीराव अंग्रेजों के प्रभुत्व से निकल कर फिर मराठा संघ स्थापित करना चाहता था । जब उसने देखा कि अंग्रेज नैपालियों और पिडारियों के साथ युद्ध में लगे हुए हैं, तो उसने सोचा कि वस, कन्धे पर से जुआ उतार फेंकने का यह ठीक मौका है ।

सन् १८१५ में गायकवाड़ का एक ब्राह्मण दूत, जो कर के विषय में पेशवा और गायकवाड़ के भगड़े को शांत करने पूना गया था, पेशवा के मन्त्री जांबकजी के इशारे से अंग्रेजों के विरुद्ध बाजीराव के पञ्चम कि जांबक को हमें सौंप दो । उसे उन्हें सौंपा गया ; परन्तु वह भाग निकला और उधर कहा जाता है कि पेशवा भी उसके साथ छिपे छिपे बातचीत करता और रुपये तथा आदमियों की सहायता दे कर विद्रोह के लिये उत्साहित करता

रहा। यह सब घात पूना के रेजीडेण्ट को मालूम हो गई और उसने पेशवा को सन् १८१७ में एक नई सन्धि करने को बाधित किया। इस सन्धि से पेशवा के अधिकारों को बड़ा आघात पहुँचा और उससे मराठा संघ के प्रधान पुरुष की पदवी छीन ली गई।

पेशवा इसे सहन न कर सका। उसने शीघ्रता के साथ युद्ध की तैयारियाँ कीं और सारे मराठा नरेशों से स्वतन्त्रता के युद्ध में भाग लेने की अपील की। उसने नवम्बर सन् १८१७ में किर्की में ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया परन्तु अन्त में हार कर वह दक्षिण की ओर भाग गया और फिर सदैव भागता ही रहा।

तथापि उसकी योजना सफल हुई। अब अन्य मराठा नरेशों ने भी हथियार सम्हाले। अप्पा साहब ने, जिसने सन् १८१६ में राघोजी की मृत्यु के बाद अपने संरक्षण में रहने वाले उत्तराधिकारी राजा की हत्या करके उसका सिंहासन छीन लिया था, सीताबाद्री में ब्रिटिश रेजीडेण्ट पर आक्रमण कर दिया। परन्तु उसे भी भारी हार खाकर पीछे की ओर भागना पड़ा। जब वह फिर गद्दी पर बैठा तो दुबारा भगड़ा उत्पन्न करने लगा। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पर वह निकल भागा और किसी अज्ञात स्थान में जाकर मर गया। जसवन्तराव होल्कर की विधवा पत्नी तुलसीबाई के विरोध करते रहने पर भी उसके सरदारों ने

अप्पासाहब

भों स ले

उसकी हत्या करके अंग्रेजों से युद्ध ठान लिया। उस समय तुलसी चाई अपने नाबालिग लड़के की तरफ से स्वयं शासन कर रही थी। इस युद्ध में इन्दौर की सेना की बुरी तरह हार हुई और अब नवयुवक होल्कर को केवल अंग्रेजों की दया का भरोसा ही शेष रह गया। इन मराठा नरेशों की पराजय और हेस्टिंग्स के पास आजाने से सिधिया के छक्के छूट गए और उसने कोई कार्यवाही नहीं की। अब केवल भागे हुए पेशवा के पीछा करने का काम ही शेष बचा था। उसने भी अष्टी और कोरिया गांव में हार खा कर अन्त में अपने आप को अंग्रेजों के हाथ सौंप दिया। उसे गद्दी से उतार दिया गया और आठ लाख रुपये वार्षिक पेंशन दे कर कानपुर भेज दिया गया।

इस प्रकार ब्रिटिश प्रभुत्व के मार्ग में मराठा साम्राज्य रूपी अंतिम रुकावट भी दूर हो गई। पेशवा का पद तोड़ दिया गया। उसका देश ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। केवल शिवाजी के एक वंशज राजा के पास सितारा का छोटा-सा राज्य यथापूर्व रहने दिया गया। युवक नरेश होल्कर और नागपुर के राजा की स्थिति अब सामन्त राजाओं के समान कर दी गई, और वे किसी भी तरह युद्ध करने के योग्य न रहे।

आन्तरिक शासन—हेस्टिंग्स के शासनकाल के युद्धों और विजयों का इतिहास पढ़ते समय हमें यह न भूल जाना चाहिये कि उसने देश में शिक्षा और सभ्यता फैलाने के लिये भी बहुत काफ़ी कार्य किया था। उसने बङ्गाल में अदालतों

की संख्या अधिक कर दी और किसी हद तक हिन्दुस्तानी अफसरों के अधिकार भी बढ़ा दिए थे। रैयत को जमीन्दारों के चंगुल से बचाने का भी उसने यत्न किया था। उसके लिये नियम बन गया कि जब तक वे अपना लगान बदस्तूर देते रहेंगे, उनके खेत न छीने जा सकेंगे। लार्ड हेस्टिंग्स ने देशी भाषाओं के

शिक्षा स्कूल कायम करके शिक्षा की तरफ़ी की। उसकी पत्नी स्त्री-शिक्षा के लिये बड़ी उत्साहशालिनी थी शिक्षा के सम्बन्ध में ईमाई मिशनरी सब देशों में तरक्की कर रहे थे। अब यहाँ भी वे आगे बढ़े। उन्होंने बंगाल में काम आरम्भ किया, बंगाल में पुस्तकें लिखवाई और उन्हें प्रकाशित किया, साथ ही बहुत-सी नई पाठशालाएँ भी स्थापित करवाईं।

सन् १८२३ में लार्ड हेस्टिंग्स भारत में चला गया। ज़िम कार्य का बेलज़ली ने आरम्भ किया था उसे हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। नेपालियों को अपने अधिकार में कर लिया, मराठों को कुचल दिया गया और पिंडारियों को दबा दिया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि अनेक राजपूत रियासतों के राजा बहुत दिनों से पिंडारियों और मराठों के विरुद्ध सहायता मांग रहे थे। अब उन पर ब्रिटिश छत्रछाया हो गई। हेस्टिंग्स के कार्यों की बढौलत कम्पनी का सारे देश पर निर्विवाद प्रकाश बैठ गया।

लार्ड एम्हर्ट (१८०३-१८०८) — लार्ड हेस्टिंग्स के बाद लार्ड एम्हर्ट की नियुक्ति हुई। उसके गामन में यमा की

लड़ाई एक प्रधान घटना थी। तत्कालीन बर्मा की
 बर्मा की राजसत्ता अलमपोरा नामक एक व्यक्ति ने
 पहली लड़ाई १७५० में स्थापित की थी। बर्मी लोग सारी
 अठारहवीं शताब्दी में देश विजय करते रहे थे और इस समय तक
 अपने उत्तरीय बर्मा वाले प्रदेश के अतिरिक्त अराकान और
 आसाम के एक भाग के स्वामी भी बन चुके थे। उनकी राजधानी
 आवा थी। इन विजयों से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। सन
 १८२३ में उन्होंने आसाम पर अधिकार कर लिया और बङ्गाल की
 खाड़ी में शाहपुरी नामक द्वीप पर, जो कम्पनी के अधिकार में था,
 कब्जा कर लिया। इस पर लार्ड एमहर्स्ट ने उनके साथ युद्ध
 छेड़ दिया।

बर्मा को जाने का मार्ग दलदल से भरे हुए जंगलो और दुर्गम
 पर्वतों से होकर था। अतएव ब्रिटिश सेना स्थलीय मार्ग से
 वहाँ न पहुँच सकी। तब यह निश्चय किया गया कि रंगून
 पटनाएँ को एक सामुद्रिक सेना भेजी जाय और फिर इरावदी
 नदी को पार किया जाय। इस स्कीम के अनुसार सर आर्चीबाल्ड
 कैम्पबेल ने रंगून पर अधिकार कर लिया और फिर उसकी बर्मी
 जनरल महा वयुला से मुठभेड़ हुई। महा वयुला ने उत्तर बर्मा में
 सफलता प्राप्त की थी, इसलिए अब उसे दक्षिण में रंगून के वासियों
 की सहायता करने के लिए भेजा गया था। वह कैम्पबेल की सेना
 से हार कर डोनाब्यू को भाग गया और वहाँ वीरता के साथ एक
 और युद्ध करने के बाद मारा गया। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने

प्रोम पर अधिकार कर लिया और थोड़ी-सी सेना ने वर्मा की राजधानी आवा से चालीस मील दूर यण्डावू पर भी धावा किया। इस पर वर्मा लोग डर गये और समझौता करने को राजी होगए।

यण्डावू की सन्धि

यण्डावू की सन्धि के अनुसार वर्मा के राजा ने आसाम, अराकान और टेनासरिम अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिये, एक करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के लिए दिया और अपने दरवार में ब्रिटिश राजदूत को रखने की अनुमति दे दी।

अन्य साधारण घटनाएँ—सन १८२५ में भरतपुर का राजा मर गया। उसके भतीजे ने मृत राजा के नावालिंग लड़के के अधिकारों को कुचल कर गद्दी पर खुद अधिकार कर लिया। नए उत्तराधिकारी के समर्थकों ने ब्रिटिश सरकार से अपील कीं। एक राजा ने कम्पनी को अपना मध्यस्थ बनाने से इन्कार कर दिया। अतः लार्ड एमहर्स्ट ने नावालिंग की तरफ से भरतपुर पर हमला करने का निश्चय किया। ब्रिटिश सेना भेजी गई और भरतपुर के किले को जिसकी मजबूती ने सेनापति लेक का नाक में दम कर दिया था—बहुत दिनों के घेरे के बाद विजय कर, उस नावालिंग उत्तराधिकारी को गद्दी पर बैठा दिया गया।

लार्ड एमहर्स्ट पहला गवर्नर जनरल था जिसने गर्मियों में शिमला को अपनी राजधानी बनाया। वह वहाँ सन १८२७ की अप्रैल से जून तक रहा। उसका अनुकरण उसके बाद के शासकों ने किया, और उन दिनों का मोपड़ियों

शिमला

वाला ज़रा-सा गांव आजकल भारत सरकार की अंग्रेजी सरकार का केन्द्र बना हुआ है।

प्रश्न

१. हेस्टिंग्स का नेपाल के साथ युद्ध कैसे हुआ? संक्षेप में लिखो।
 २. जिस कार्य को वेलज़ली ने आरम्भ किया था, उसे हेस्टिंग्स ने कैसे समाप्त किया?
 ३. हेस्टिंग्स की नीति अपने तीन पूर्ववर्ती शासकों से किस बात में भिन्न थी?
 ४. ब्रह्मा की पहली लड़ाई का संक्षिप्त विवरण लिखो।
-

गौरी अ-पाप

लार्डे विलियम वेन्ट्रिक (१८२८-३५)

नीतिक और भौतिक उन्नति

सन १८२८ के आरम्भ में लार्डे पाउण्डर्स चला गया और उस
के स्थान पर लार्डे विलियम वेन्ट्रिक को नियुक्ति हुई। वह भारत
को नियति में अजानबत नहीं था। वह पहले भी मद्रास
क गवर्नर की हैमियन में काम कर चुका था। उस
पद पर रहने हुए वेतोर के सिपाहों-विद्रोह के सम्बन्ध
में उसने जो नीति स्वीकार की थी, उसने कम्पनी के टाइरेक्टर
अमन्तुष्ट्र हांगए में और इस पर उमनत्याग-पत्र दिया था। अब तक
वह भारत में बाहर रहा, उसने अपनी आर्थिक योग्यता का
अच्छा परिचय दिया और जब सन १८२७ में नए गवर्नर
जनरल की नियुक्ति का सन्धान आया तो—क्योंकि वर्गों के युद्ध
के कारण कम उम्रों की बहुत जागरत थी—कम्पनी के टाइरेक्टरों
ने इस पद के लिए उसे ही योग्य समझा।

बैन्टिक भारत के प्रधान गवर्नर जनरलों में गिना जाने योग्य है, पर उसका कार्यक्षेत्र औरों से सर्वथा भिन्न था। उस समय इंग्लैंड में सुधार का युग था, उन दिनों वहाँ गवर्नर जनरल की कैथोलिक सम्प्रदाय की स्वाधीनता, दासप्रथा हैसियत से का मूलोच्छेदन और विल के पास होने के कार्य हो रहे थे। बैन्टिक के हृदय में भी अपने युग की सुधार-विषयक भावनाएँ काम कर रही थीं। अतः उसने भारत में आते ही सुधार का काम शुरू कर दिया। वैसे चाहे शांतिपूर्ण गृह-व्यवस्था की अपेक्षा तोपों की गडगडाहट, तलवारों की झनझनाहट और नफ़ारों की आवाज़ अधिक सनसनी पैदा करने की योग्यता क्यों न रखती हो, परन्तु इतिहास का फैसला है कि—“युद्ध की तरह शांति में भी विजय प्राप्त होती है।”

सुधार—यह पहले ही कहा जा चुका है कि लार्ड बैन्टिक की नियुक्ति के अन्य कारणों में एक प्रधान कारण यह था कि उस समय आर्थिक सुधार की अत्यन्त आवश्यकता थी। तब तक भारतवासियों को ऊँचे ओहदों पर नहीं रक्खा जाता था, अब वे पद उनके लिये भी खोल दिए गए। इससे शासन-प्रबन्ध में बहुत कुछ किफ़ायतशारी की सम्भावना थी, क्योंकि हिन्दुस्तानी थोड़े वेतनों से ही संतुष्ट हो जाते थे। उसने दीवानी और फ़ौज़ी अफ़सरों के भत्ते में कमी की और उत्तर-पश्चिम प्रान्त में (जो अब संयुक्त प्रान्त कहलाता है) तीन साल का लगान का पट्टा तय किया, इस प्रकार इस प्रान्त से राज्य को

मिलने वाले लगान में काफ़ी वृद्धि हो गई। अपने इन कार्यों से वह भारी घाटे के स्थान १५,००,००० पौण्ड की वचत करने में सफल हुआ।

पर वैन्टिक ने कुछ ऐसे काम भी किए जिनके सर्वजन-हितकार होने के कारण उसका नाम इतिहास में सदा के लिए प्रधान स्थान पर रक्खा जायगा। उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम

सतीप्रथा का उठा देना था। उन दिनों हिन्दू विधवाएं सामाजिक

अपने मृत पति के शव के साथ चिता में जल मरती थीं। अधिकांश अवसरों पर वे खुद प्राण त्यागने को तत्पर नहीं होती थीं, परन्तु उनके कुटुम्बी उन्हें पति के शव के साथ जल मरने

को बाधित करते थे। वैन्टिक ने सन १८२६ में एक सती और ठगी

कानून बनाया जिसके अनुसार सती-प्रथा को गैरकानूनी ठहराया गया और घोषणा कर दी गई कि जो पुरुष इस में सहायता देगे वे कानून की निगाह में हत्या के अपराधी समझे

जाएँगे। उसने दूसरा काम यह किया कि ठगी का मूलोच्छेदन कर दिया। उस समय ठगों के दल वेश बदले हुए इधर उधर घूमा

करते थे और बेखबर यात्रियों का गला घोट कर उन्हें मार डालते थे। यह काम मेजर स्लीमन के सुपुद किया गया, जिसने थोड़े

से ही समय में ठगों के दलों को नष्ट कर दिया और उनके इस

घृणित पेशे को समूल उखाड़ फेंका। वैन्टिक ने शिशु-हत्या

राजपूतों में लडकियों को मार डालने की प्रथा को रोकने का भी प्रशासनीय और सफल प्रयत्न किया।

उसने एक और बहुत बड़ा परिवर्तन यह किया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहन दिया। सन १८१३ में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने अपने कर्मचारियों को एक लाख रुपया शिक्षा प्रतिवर्ष शिक्षा के निमित्त लगाने की हिदायत कर दी थी। अब तक यह धन देशी भाषाओं की शिक्षा में खर्च किया जाता रहा था। वैन्टिक के शासन-काल में इस बात पर खूब वाद-विवाद हुआ कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिये। उस समय संयोग से लार्ड मैकाले भी कलकत्ते की अंग्रेजी कौंसिल के सदस्य की हैसियत से भारत ही में मौजूद था। उसने अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन का जोर के साथ समर्थन किया। लार्ड वैन्टिक स्वयं भी उससे सहमत था। अतः अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम करार दिया गया। सन १८३५ में एक विज्ञप्ति निकली जिसके अनुसार सम्पूर्ण स्कूलों और कालेजों में शिक्षा की पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था कार्य में लाई जाने लगी। इससे भारत को यूरोपियन साहित्य के उपभोग करने का अवसर मिला, यद्यपि इस पद्धति में कुछ हातियां भी अवश्य थीं।

राज्य विस्तार की नीति—वैन्टिक देशी रियासतों के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। पर खास खास मामलों में उसे ऐसा करना पड़ता था। उसने कुर्ग के राजा को—जिसके कुर्ग. कछार जुल्म से प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी—उतार और मैसूर दिया, और प्रजा की अभिलाषा के अनुसार राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। कछार

दसवां अध्याय

ऑकलैंड और ऐलेनवॉरॉ

(१८३६-१८४२ तथा १८४२-१८४४)

अफगानिस्तान—ऑकलैंड के भारत में आने के साथ ही सिंध नदी के उस पार उत्तर-पश्चिम में फसाद शुरू होता है। 'मौजूदा अफगानिस्तान के राजवंश का प्रवर्तक पानीपत का विजेता अहमदशाह अब्दाली था। उसका एक पोता था—ज़मानशाह, जिसका जिक्र हम रणजीतसिंह के प्रसंग में कर आए

शामक में हैं। इसे गद्दी से उतार दिया गया और उसकी आरसें परिवर्तन फोड़ दी गईं। उसका एक और पोता था—शाहशुजा जिसने अपने योग्य मन्त्री वज़ीर अलोत्रा की सहायता से शासन किया। वैन्टिड के शासन काल में शाहशुजा को उसके भाई महमूद ने अफगानिस्तान से निकाल दिया था। इसके बाद शाहशुजा के मन्त्री वज़ीरअली के भाटे, दोमन मुहम्मद ने महमूद

इन कौन्सिल" कहलाया जाने लगा और उसकी कौन्सिल में एक कानूनी सदस्य की भी वृद्धि की गई। लार्ड मेकाले—जिसने भारतीय दण्डविधान बनाया था—भारत का पहला कानूनी सदस्य था। अन्त में यह विधान बनाया गया कि "भारत के किसी देशी निवासी या सम्राट की किसी जन्म की प्रजा को केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ण या जाति के कारण कम्पनी के किसी भी पद से वंचित नहीं रक्खा जाएगा।"

सर चार्ल्स मेटकाफ़—सन् १८३५ में लार्ड विलियम वैन्टिक चला गया और उसकी जगह सर चार्ल्स मेटकाफ़ आया। उसके शासन की सब से अधिक उल्लेखनीय घटना यह है कि प्रेस की स्वतन्त्रता पर से सारी बंदिशें उठा ली गईं। उसके इस कार्य के कारण डाइरेक्टरों ने उस पर अविश्वास प्रकट किया और उसने त्याग-पत्र दे दिया। उसकी जगह सन् १८३६ में लार्ड आकलेंड की नियुक्ति हुई। अपने इस कार्य से सर मेटकाफ़ की भारतीयों में बड़ी प्रतिष्ठा हुई।

प्रश्न

१. भारत के इतिहास में वैन्टिक के शासन का क्या महत्व है ?
२. इस बात को साबित करो कि लार्ड वैन्टिक ने भारत में स्थायी शांति स्थापित की।
३. सती प्रथा और ठगी पर संक्षिप्त नोट लिखो।
४. सर चार्ल्स मेटकाफ़ ने त्यागपत्र क्यों दिया।

इन फौन्सिल" फहलाया जाने लगा और उसकी फौन्सिल में एक कानूनी सदस्य की भी वृद्धि की गई। लार्ड मेकाले—जिसने भारतीय दण्डविधान बनाया था—भारत का पहला कानूनी सदस्य था। अन्त में यह विधान बनाया गया कि "भारत के किसी देशी निवासी या सम्राट की किसी जन्म की प्रजा को केवल अपने धर्म, जन्म-स्थान, वर्ण या जाति के कारण कम्पनी के किसी भी पद से वंचित नहीं रक्खा जाएगा।"

सर चार्ल्स मेटकाफ़—सन् १८३५ में लार्ड विलियम वैन्टिक चला गया और उसकी जगह सर चार्ल्स मेटकाफ़ आया। उसके शासन की सबसे अधिक उल्लेखनीय घटना यह है कि प्रेस की स्वतन्त्रता पर से सारी बंदिशें उठा ली गईं। उसके इस कार्य के कारण डाइरेक्टरों ने उस पर अविश्वास प्रकट किया और उसने त्याग-पत्र दे दिया। उसकी जगह सन् १८३६ में लार्ड आकलेंड की नियुक्ति हुई। अपने इस कार्य से सर मेटकाफ़ की भारतीयों में बड़ी प्रतिष्ठा हुई।

प्रश्न

१. भारत के इतिहास में वैन्टिक के शासन का क्या महत्व है ?
२. इस बात को साधित करो कि लार्ड वैन्टिक ने भारत में स्थायी शांति स्थापित की।
३. सती प्रथा और ठगी पर संक्षिप्त नोट लिखो।
४. सर चार्ल्स मेटकाफ़ ने त्यागपत्र क्यों दिया।

या जाड़े से खुद ही मर गए ।

इस विपत्ति की खबर जब इङ्गलैंड पहुँची तो वहाँ आतंरु छा गया । लार्ड आकलैंड को वापिस बुला लिया गया और उसकी जगह लार्ड एलेनवॉरों को भेजा गया ।

लार्ड एलेनवॉरों (१८४२-१८४४)—नए गवर्नर जनरल का प्रधान कार्य अफ़ग़ानिस्तान से अंग्रेज़ों को छुटकारा दिलाना था । उसने कन्धार और जलालाबाद के अंग्रेज़ सैनिकों की सहायता के लिये ब्रिटिश सेना भेजी । वे अफ़ग़ानो की बड़ी सेना से अब तक वीरता के साथ अपनी रक्षा करते रहे थे । अब दोनों सेनाएँ मिलकर काबुल की ओर बढ़ीं और काबुल पर उनका पुनः अधिकार हो गया । ब्रिटिश बन्दि्यों को बन्धनमुक्त कर दिया गया और अफ़ग़ानों के आक्रमण का बदला लेने के लिए चालाहिस्सार नामक काबुल का प्रधान बाज़ार तोपों से उड़ा दिया गया । इस प्रकार अफ़ग़ानिस्तान में दुबारा ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने के बाद यह सेना भारत को वापस आ गई ।

दोस्त मुहम्मद पुन.
गद्दी पर बैठा

शाहशुजा को अकबरखा के सिपाहियों ने मार डाला था । अतएव दोस्त मुहम्मद को अफ़ग़ानिस्तान में वापस जाने की आज्ञा दे दी गई और उसे वहा का शासक मान लिया गया । इस प्रकार घीस हज़ार मनुष्यों का जीवन और उड़ करोड रुपया धिना किसी फल के नष्ट हो गया ।

सिन्ध पर विजय—सिन्ध का सवा तीन विभागों ने टंटा

हुआ था, इन पर तीन बलोची शासन करते थे, ये लोग अमीर कहलाते थे । इन अमीरों ने सन १८०६ में अंग्रेजों के साथ सन्धि कर ली थी, जिस के अनुसार उनकी अंग्रेजों से मित्रता स्थापित हो गई थी और अमीरों ने अपने प्रदेशों में फर्रासीसियों को न आने देने का वचन दे दिया था । सन १८३२ में उन्हें एक नए सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी कर लिया गया, जिसके अनुसार उन्होंने अंग्रेजों को सिन्ध में व्यापार करने की भी इजाजत दे दी; परन्तु वे अपने देश में से उनकी फौजें गुज़रने देने के लिए अभी राजी न हुए थे । परन्तु उनकी अनिच्छा की कोई परवाह न करके अंग्रेजों की सेना सिन्ध में से हो कर अफ़गानिस्तान को बराबर जाती और सिन्ध की सड़कों और नदियों को अपने उपयोग में लाती रही । कुछ समय बाद अमीरों को एक नवीन सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने को बाधित किया गया जिसके अनुसार उन्हें एक एक ब्रिटिश सेना अपने देशों में रखने और उनके गुज़ारे के लिए अपनी आय में से रकम देने को मजबूर होना पड़ा। अफ़गान युद्ध के समाप्त होजाने के बाद अमीरों पर अंग्रेजों का विरोध करने का इजाम लगाया गया और सर चार्ल्स नेपियर को—जिसे सिविल और मिलिटरी के सम्पूर्ण अधिकार मिले हुए थे—इस अभियोग को जांच करने के लिए भेजा गया । उसने पहले ही से यह तय कर लिया था कि सिन्ध को ब्रिटिश राज्य में मिलाना अनिवार्य है, अतः उसने सिन्धियों के पक्ष की कोई परवाह न करके अमीरों को एक नई मुलह करने

पर वाध्य किया, जिसके अनुसार उन्हें अपने देशों का अधिकांश भाग अंग्रेजों के सुपुर्द कर देना पड़ा। इस अत्याचार ने अमीरों को युद्ध करने के लिये उकसाया। सन १८४३ की फ़रवरी में

मियानी और उसके बाद दावो नामक स्थान पर मियानी और सिन्धी सेना को मुट्ठी भर अंग्रेज सिपाहियों ने दायो हरा दिया। अमीरों को गद्दी से उतार दिया गया

और सिन्ध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। नेपियर को सिन्ध का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। इस मामले में सच-मुच ज्यादाती से काम लिया गया था। स्वयं नेपियर भी उसे समझता था और उसने अपनी सैनिक सुलभ स्पष्टवादिता के साथ लिखा भी था—“हमें सिन्ध पर अधिकार करने का कोई हक नहीं है। पर हम ऐसा अवश्य करेंगे और यह बदमाशी हमारे लिये बड़ी लाभकारी, उपयोगी साथ ही लज्जाजनक सिद्ध होगी।” डाइरेक्टरों ने सिन्ध विजय की सारी कार्यवाही नापसन्द की, पर, फिर भी इस नए प्रदेश को अपने ही अधिकार में रहने दिया।

ग्वालियर—दौलतराव सिधिया सन १८२६ में मर गया और उसका धर्मपुत्र जनकजी सन १८४३ में मरा। उसके कोई पुत्र नहीं था। अतएव उसकी विधवा ने गवर्नर जनरल की सम्मति से एक लड़के को गोद ले लिया। अब यह समस्या उपस्थित हुई कि नावालिय लड़के का रक्षक कौन घनेगा। इस पर अंग्रेजों और रानी में झगडा उठ खड़ा हुआ और रियासत के दरबार में दलनन्दियां होने लगीं। अंग्रेजों के लिए सब से अधिक

ग्वालियर की सेना चिन्ता की बात यह थी कि ग्वालियर में उस समय ४०,००० सेना थी, जिसने अभी तक अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। यदि वह सेना सिक्खों के साथ मिल जाती तो एक नया और भारी उपद्रव खड़ा हो सकता था। इसलिए कोई न कोई कार्यवाही शीघ्र ही करना आवश्यक समझा गया।

सन १८४३ में ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर धावा बोल दिया और मराठा सेना को महाराजपुर में हरा दिया। उसी दिन

महाराजपुर और पनिवार मराठा सेना का एक दूसरा भाग पनिवार में हराया गया। रानी ने आत्म-समर्पण कर दिया।

एक नया सुलहनामा तैयार हुआ, जिसके अनुसार रियासत की सेना घटा कर ६,००० कर दी गई और शासन प्रबन्ध, लड़के के वालिया होने तक, कौन्सिल (कौन्सिल आफ् रीजेन्सी) के सुपुर्द कर दिया गया। यह कौन्सिल रेजीडेन्ट के परामर्श से काम करने को बाध्य थी। इसके बाद फिर कोई झगड़ा नहीं हुआ और उस समय से अब तक ग्वालियर के राजा बराबर अंग्रेजों के मित्र रहे हैं।

इसके बाद ही लार्ड एलेनबारा को भारत से चुला लिया गया। उसकी आक्रमण की नीति से कम्पनी के डाइरेक्टरों को चण-भर का भी विश्राम नहीं मिल सका था। अतः वे उससे असंतुष्ट हो गए थे। वह सन १८४४ में भारत से चला गया और उसकी जगह सर हेनरी हार्डिंग आया जो बाद को लार्ड हार्डिंग हुआ।

प्रश्न

१. अफगानों के साथ पन्ना युद्ध किस कारण हुआ ? युद्ध का संक्षिप्त विवरण लिखो ।
 २. लार्ड आकलैंड के शासन प्रबन्ध पर एक नोट लिखो ।
 ३. लार्ड एल्लिनबरा ने अपने शासन में कौन-सी नीति स्वीकार की थी । उसके शासन की प्रमुख घटनाएँ लिखो ।
 ४. सिन्ध अफ़्ग़ानों राज्य में कैसे मिलाया गया ?
-

ग्यारहवां अध्याय

लार्ड हार्डिंग (१८४४-१८४८) (ब्रिटिश राज्य का पंजाब में विस्तार)

रणजीतसिंह के बाद पंजाब की स्थिति—रणजीतसिंह बड़ा प्रबल और कूटनीतिज्ञ शासक था। जब तक वह जीवित रहा, उसके विरुद्ध सिर उठाने का किसी को साहस न हुआ। अपनी चतुरता, विचार शक्ति और मनुष्यों की योग्यता जाँचने की बुद्धि की बदौलत वह अपने दरबारियों और सैनिकों पर निरन्तर रोबदाब कायम रख सका था। सन् १८३६ के जून मास में यह 'पञ्जाब केसरी' परलोक सिधारा। उसके बाद उसका राज्य भी, जिसका वह प्राण था शीघ्र ही नष्ट होकर धूल में मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद के छः वर्षों में पञ्जाब में शान्ति और बुरे शासन का दौरादौरा रहा। रणजीतसिंह के सारे पुत्रों को एक एक करके सिक्ख सरदारों ने मार डाला। अन्त में उसके सबसे छोटे पुत्र दिलीपसिंह को गद्दी पर बैठाया

गया और उसकी माता रानी जिंदां, अपने कृपापात्र लालसिंह की सहायता से उसके लिये शासन करने लगी। परन्तु खालसा सेना, जिसमें ७०,००० सिपाही थे, बड़ी उत्कृष्ट सेना थी और उसे कावू में रखना असम्भव हो गया था। रानी और उसका मन्त्री लालसिंह भी कोई ऐसा उपाय सोच रहे थे, जिससे सेना को अपनी शक्ति काम में लाने का अवसर मिले। उन्होंने इस सेना को प्रोत्साहन दिया कि वह ब्रिटिश राज्य पर आक्रमण करे और पञ्जाब के अतिरिक्त अन्य भारत में भी अपना सिक्का बैठाने का प्रयत्न करे। तदनुसार सन् १८४५ में सिक्खों ने सतलुज नदी को, जो दोनों राज्यों की सीमा थी, पार कर लिया। यह एक तरह से युद्ध की घोषणा थी।

सिक्खों की पहली लड़ाई (१८४५-१८४६) —

अंग्रेजों को अब तक भारत में जितनी सेनाओं से पाला पड़ा था, उनमें खालसा सेना सबसे अधिक भयंकर और शक्तिशाली थी। लार्ड हार्डिंग ने स्वयं एक विशाल सेना के साथ यात्रा की। उसके साथ कमाण्डर इन चीफ सर ह्यू गफ़ भी आ मिला। सन् १८४५ के १८ दिसम्बर को मुदकी में पहला युद्ध हुआ। बहुत घमासान लड़ाई हुई, परन्तु विजय अंग्रेजों की ही रही। यह सिक्खों के साथ पहला मोरचा था और बाद की लड़ाइयों ने साबित कर दिया कि सिक्ख साधारण लड़ाके नहीं हैं। मुदकी की लड़ाई के तीन

दलीपसिंह और
रानी जिंदा

मुदकी और
फीरोज़शाह

दिन बाद फ़ीरोजशाह की लड़ाई हुई। अंग्रेज़ों को भारत में ऐसे घोर और भयंकर युद्ध का शायद पहले कभी अवसर नहीं पड़ा था। २१ दिसम्बर की रात इतनी भयानक थी कि बहुत से अंग्रेज़ अफ़सरों ने सेनापति को वापिस भाग चलने की सलाह तक दे डाली।—“उस रात को भारत के भाग्य का पलड़ा कभी इधर झुकता था, कभी उधर।” पर दूसरे दिन सुबह को रंग बदला और यद्यपि सिक्खों ने अपूर्व शूरता से काम किया, तथापि जीत अंग्रेज़ों के ही हाथ रही। एक महीने बाद सर हैरी स्मिथ ने सिक्खों पर पुनः धावा कर दिया। इस बार अलीवाल और भी अलीवाल के युद्ध क्षेत्र में उनके पैर पूरी तरह उखड़ गए और वे सतलुज के उस पार भागने को विवश हो गए। इसके बाद वे कई सप्ताह तक फ़ीरोजपुर के पूर्व सवराओं में लड़ाई की तैयारी करते रहे। उन्होंने सतलुज पर नावों के पुल की एक मजबूत किलेबन्दी की। यहीं पर सन् १८४६ की १० फरवरी को सिक्खों के साथ अंग्रेज़ों का अन्तिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी सिक्ख बुरी तरह नष्ट हुए। जिस पुल पर से होकर वे भागने की बात सोच रहे थे, उसे नष्ट कर दिया गया और करीब दस हजार सिक्ख वहीं मारे गए। खालसा सेना की पूरी पराजय हुई। लार्ड हाडिंग ने सोचा कि अभी पंजाब को मिलाने का उपयुक्त समय नहीं है। अतः उसने लाहौर में सिक्खों से सन्धि की। उसने एक ऐसी सिक्ख सरकार कायम कराने की नीति अपनाई, जो सेना और राज्य विस्तार की दृष्टि

से पहले की अपेक्षा कमज़ोर हो । सतलुज और व्यास के बीच
 का जालंधर-दोआब अंग्रेज़ों के राज्य में मिला
 लाहौर की लिया गया । सर हैनरी लारेंस नामक एक ब्रिटिश
 सन्धि रेज़ीडेण्ट को लाहौर में नियुक्त किया गया और
 सिक्खों की सेना घटा कर २०,००० कर दी गई । बाकी शासन-
 प्रबन्ध बदस्तूर रहा । सिक्ख सरदारों की इच्छा से ब्रिटिश सेना
 उस वर्ष के अन्त तक लाहौर में ही रही । बाद को एक और सन्धि
 की गई और उसमें ब्रिटिश सेना के लाहौर में रहने की अवधि
 और भी बढ़ा दी गई । हाडिंग ने सिक्खों से युद्धक्षति स्वरूप डेढ़
 करोड़ रुपया मांगा । पर लाहौर के राजकोष में केवल पचास लाख
 रुपया ही शेष था । काश्मीर और जम्मू के
 काश्मीर का राजा शासक गुलाबसिंह ने प्रस्ताव किया कि यदि
 गुलाबसिंह उसे अपने प्रांत का स्वतन्त्र शासक मान
 लिया जाय तो बाकी रकम वह अदा कर देगा । यह बात स्वीकार
 कर ली गई और उस समय से काश्मीर का शासन महाराजा
 गुलाबसिंह के वंशजों के ही अधिकार में है ।

सन १८४८ में हाडिंग भारत से लौट गया । यद्यपि वह युद्धों
 में ही फँसा रहा, पर उसने कुछ अन्य लाभदायक कार्य भी किए ।
 उसने भारत में रेलवे की योजना तैयार की, गङ्गा की नहर खुद-
 वाने की सिफ़ारिश की, देशी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन
 दिया और देशी रिवाजों में सती और शिशुहत्या को रोकने
 का प्रयत्न किया ।

प्रश्न

१. रणजीतसिंह के मरने के बाद पंजाब की क्या दशा थी ?
 २. सिक्खों का पहला युद्ध किन कारणों से हुआ ? उसका परिणाम क्या हुआ ?
 ३. काश्मीर के वर्तमान राजवंश का प्रारम्भ कैसे हुआ ?
-

बारहवां अध्याय

लार्ड डलहौज़ी (१८४८-१८५६)

लार्ड हार्डिंग ने अपने उत्तराधिकारी लार्ड डलहौज़ी को अधिकार सौंपते हुए कहा कि आगामी सात वर्ष तक भारत में एक भी गोली चलाने की ज़रूरत न पड़ेगी। परन्तु बाद की घटनाओं ने लार्ड हार्डिंग की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। उसने कहा था कि सात वर्ष तक एक भी गोली न चलानी पड़ेगी, परन्तु वही सात वर्ष देश में घमासान युद्धों के वर्ष सिद्ध हुए। डलहौज़ी को शासनभार सम्हाले तीन महीने ही बीते थे कि मुलतान के शासक मूलराज के यहां सन १८४८ में दो अंग्रेज़ अफ़सरों की हत्या होगई। यह दूसरे सिक्ख-युद्ध की भूमिका थी।

मूलराज से पंजाब सरकार ने रियासत का हिसाब कित्त मांगा था, परन्तु उसने इसे अपना अपमान समझ कर इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। तब उसे ब्रिटिश रेज़ीडेण्ट के प्रभाव से अपने पद से हटा दिया गया और उक्त

मूलराज

दो अंग्रेजों को उससे शासन का चार्ज लेने के लिए भेजा गया। परन्तु मुल्तान में उनकी हत्या कर दी गई। उसकी जगह एक सिक्ख गवर्नर की नियुक्ति होने वाली थी। उन दोनों अंग्रेज अफसरों की हत्या से सिक्खों में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो गया। यद्यपि सिक्ख हार चुके थे, परन्तु उनके हृदयों में प्रतिहिंसा की आग अभी तक जल रही थी।

मूलराज ने विद्रोह का झण्डा सन १८४८ में खड़ा किया था, परन्तु कमाण्डर-इन-चीफ़ लार्ड गफ ने युद्ध का कार्य जाड़ों तक के लिए मुल्तवी कर दिया था। इसका परिणाम

आरम्भ

यह हुआ कि इस स्थानीय विद्रोह ने फैलकर विशाल रूप धारण कर लिया। हर्वर्ट एडवर्ड्स ने, जो सिक्ख कौन्सिल आफ़ रीजेन्सी का सदस्य था, कुछ सैनिक बल इकट्ठा करके मूलराज पर धावा बोल दिया, और उसे दो हमलों में ही हरा दिया। लाहौर के रेजीडेण्ट ने शेरसिंह को एक भारी सेना देकर मुल्तान के चारों ओर घेरा डाल कर पड़ी हुई अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए भेजा, पर वह ब्रिटिश सेना की सहायता करने की बजाय दुश्मनों से मिल गया और इस प्रकार ब्रिटिश सेना को लाचार हो कर घेरा उठा लेना पड़ा। सिक्खों ने दोस्त मुहम्मद को पेशावर का लालच देकर उसकी सहायता भी प्राप्त कर ली थी।

सिक्खों का दूसरा युद्ध (१८४८-१८४९)—
इस समय के सम्पूर्ण बड़े बड़े सिक्ख सरदार अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र लेकर तैयार हो गए और डलहौजी ने भी युद्ध करने का

निश्चय किया। उसने कलकत्ते में भाषणा देते हुए कहा कि उमगी इच्छा युद्ध करने की नहीं थी, पर चूं कि सिक्ख युद्ध चाहते हैं, इस लिए उनसे युद्ध करना ही पड़ेगा और यह युद्ध खूब उट कर किया जायगा।

लार्ड गफ़ २० ००० सेना लेकर चिलियावाला पहुँचा, जहाँ सिक्ख मोर्चावदी किए तैयार थे। इस लड़ाई में भी सिक्खों ने

अपना जौहर दिखाया और यद्यपि अन्त में चिलियावाला जीत अंग्रेजों की ही रही, तथापि युद्ध में उनकी

इतनी भारी क्षति हुई कि सफलता का पलड़ा सिक्खों के पक्ष में ही झुका हुआ दिखाई देता है। इस लड़ाई के विषय में लार्ड डलहौज़ी ने कहा था—“हमारी याद ऐसी ही एक आध विजय और हो जाए तो हम वरवाद हो जाएंगे।” इंग्लैंड के अधिकारियों ने सिन्ध विजेता सर चार्ल्स नेपियर को लार्ड गफ़ का स्थान लेने के

लिए भेजा, परन्तु उसके भारत में पहुँचने तक लार्ड गुजरात गफ़ ने गुजरात की लड़ाई में सिक्ख-शक्ति को

छिन्न भिन्न करके अपनी खोई हुई प्रसिद्धि पुनः प्राप्त करली थी। उधर मुलतान पर आक्रमण किया गया और मूलराज को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात की लड़ाई के कुछ दिनों बाद सिक्खों ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिक्ख युद्ध का अन्त हो गया।

पंजाब की व्यवस्था—हाडिंग ने पञ्जाब के विषय में जो नीति वरती थी, वह असफल सिद्ध हो चुकी थी अब

पंजाब मिला डलहौज़ी उस नीति का और अधिक प्रयोग नहीं करना चाहता था । उसने पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का निश्चय कर लिया और यह कार्य सन १८४६ में कर लिया गया । महाराजा दलीपसिंह को पेंशन दे दी गई और पंजाब प्रान्त का प्रबन्ध एक बोर्ड को सौंप दिया गया, जिसमें हैनरी और जान लारेंस नामक दो प्रसिद्ध भाई और एक अन्य सिविलियन थे । तब यहां सड़कें और नहरें बनवाई गईं, ज़मीन का लगान बहुत कम कर दिया गया और अन्य बहुत से टैक्स भी घटा दिये गए । कुछ ही वर्षों के भीतर चारों ओर शान्ति दिखाई देने लगी और परिवर्तन सिक्ख अंग्रेज़ों की भक्त प्रजा बन गए । उस समय यह बात अच्छी तरह साबित होगई, जब सन १८५७ के गदर की लहर में भी पंजाब अचल रूप से खड़ा रहा और उस अवसर पर अंग्रेज़ लोग पंजाब को ' भारत का रक्तक प्रांत ' कहने लगे । सन १८५२ में यह बोर्ड तोड़ दिया गया और सर जान लारेंस को पंजाब का चीफ़ कमिश्नर बना दिया गया ।

वर्मा की दूसरी लड़ाई (१८५२) — वर्मियों को एमहर्स्ट के ज़माने में जो पराजय हुई थी, उससे भी वे सदा के लिये दब नहीं गए थे । उनमें अभी तक अंग्रेज़ों के लिए घृणा और बदला लेने के भाव थे । इसी कारण अंग्रेज़ व्यापारियों के साथ रंगून के दरगाह पर घुरा बर्ताव किया जाता था, इस पर जब अंग्रेज़ दूत वर्मा के राज दरबार में क्षतिपूर्ति के

पंजाब मिला डलहौज़ी उस नीति का और अधिक प्रयोग करना चाहता था । उसने पञ्जाब को ब्रि लिखा गया राज्य में मिलाने का निश्चय कर लिया और

कार्य सन १८४६ में कर लिया गया । महाराजा दलीपसिंह पैन्शन दे दी गई और पंजाब प्रान्त का प्रबन्ध एक बोर्ड को दिया गया, जिसमें हैनरी और जान लारेंस नामक दो भाई और एक अन्य सिविलियन थे । तब यहां सड़कें और बनवाई गईं, ज़मीन का लगान बहुत कम कर दिया गया अन्य बहुत से टैक्स भी घटा दिये गए । कुछ ही वर्षों के

परिवर्तन चारों ओर शान्ति दिखाई देने लगी सिक्ख अग्नेजों की भक्त प्रजा बन गए ।

समय यह बात अच्छी तरह साबित होगई, जब सन १८५७ ग्दर की लहर में भी पञ्जाब अचल रूप से खड़ा रहा । अक्सर पर अग्नेज लोग पञ्जाब को ' भारत का रक्षक प्रान्त' लगे । सन १८५२ में यह बोर्ड तोड़ दिया गया और लारेंस को पञ्जाब का चीफ कमिश्नर बना दिया गया ।

वर्षों की दूसरी लड़ाई (१८५७) — वर्षों के के ज्ञान में जो पराजय हुई थी, उनसे भी वे सदा के

नहीं गए थे । उनमें अभी तक अग्नेजों के और बढ़ता लेने के भाव थे । इसी कारण

व्यापारियों के साथ रंगून के दरगाह पर बुरा धर्तव्य किया था, इस पर जब अग्नेज दुःखियों के राज दरबार में

करेंगे तो उन्हें गद्दी से उतार दिया जायगा। परन्तु नवाब की ओर से इन चेतावनियों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया गया था। अब डलहौजी ने प्रस्ताव किया कि अवध के शासन का भार कम्पनी खुद ग्रहण करे। चाहे नवाब वाजिद अलीशाह के पास उसका पद और उपाधि वैसे ही रहने दिये जाएं। पर नवाब के विषय में डलहौजी की जो राय थी वह औरो को पसन्द न आई। इस पर अवध को भी अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। नवाब को लाखनऊ से हटा कर कलकत्ते भेज दिया गया और उसकी वीस लाख रुपया वार्षिक पेंशन नियत कर दी गई।

निज़ाम ने कम्पनी को हैदराबाद में ब्रिटिश सेना के व्यय की बहुत बड़ी रकम देनी थी, अतः उस रकम के भुगतान में चार उससे वरार ले लिया गया।

डलहौजी ने कुछ जागीरें और पेंशनें बन्द कर दी थीं। अर्काट के नवाब और तजोर के राजा से शासन का अधिकार बहुत दिन पहले ही ले लिया गया था, जब उनका देहान्त होगया तो उनकी पेंशनें और उपाधियां बन्द कर दी गईं। पदच्युत पेशवा वाजीराव के मरने पर डलहौजी ने उसके धर्मपुत्र दोदुपत को, जो नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है, आठ लाख वार्षिक पेंशन देते रहने से इनकार कर दिया। गवर्नर जनरल ने यह भी योजना पेश की थी कि शाह आलम के पोते बहादुरशाह के मरने पर, जो इस समय दिल्ली का नामनात्र का बादशाह रह गया था, उसके

बैन्टिक के समय में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने स्वीकार किया था, इसका असली उद्देश रियासतोंका अन्त करना था। परन्तु डलहौज़ी के पूर्ववर्ती शासकों ने, जहां तक हो सका, केवल इस आधार पर रियासतें शामिल करने की नीति से काम नहीं लिया था। परन्तु डलहौज़ी ने इस शामिल करने के विधान को, जहां तक सम्भव हो सका, अपनाया और उसने इसका एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। उसके शासनकाल में अनेक मातहत देशी नरेश, बिना किसी उत्तराधिकारी को छोड़े, मर गए। लार्ड डलहौज़ी ने इन अवसरों से लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बिना किसी तकलीफ़ के खूब विस्तार किया। सतारा और भांसी को इस आधार पर अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया कि उनके राजाओं ने धर्मपुत्र को गोद लेते समय अंग्रेज़ों की अनुमति नहीं ली थी। नागपुर को सन १८५६ में इसलिए मिला लिया गया कि वहां की गद्दी का कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं रहा था। करौली नामक रियासत के विषय में होम गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल की आज्ञा रद्द कर दी और घोषणा की कि वह मातहत रियासत नहीं है।

सन १८५६ में अवध को अंग्रेज़ी राज्य में इस आधार पर शामिल कर लिया गया कि वहाँ का शासन बड़ा दोषपूर्ण और बुरा था। एक के बाद दूसरे नवाब को धमकियां दी जाती रही थी कि यदि वे शासन प्रबन्ध में सुधार नहीं

करेंगे तो उन्हें गद्दी से उतार दिया जायगा। परन्तु नवाब की ओर से इन चेतावनियों की तरफ़ कुछ ध्यान नहीं दिया गया था। अब डलहौज़ी ने प्रस्ताव किया कि अबध के शासन का भार कम्पनी खुद ग्रहण करे। चाहे नवाब वाजिद अलीशाह के पास उसका पद और उपाधि वैसे ही रहने दिये जाएं। पर नवाब के विषय में डलहौज़ी की जो राय थी वह औरों को पसन्द न आई। इस पर अबध को भी अंग्रेज़ों राज्य में शामिल कर लिया गया। नवाब को लखनऊ से हटा कर कलकत्ते भेज दिया गया और उसकी वीस लाख रुपया वार्षिक पेंशन नियत कर दी गई।

निज़ाम ने कम्पनी को हैदराबाद में ब्रिटिश सेना के व्यय की बहुत बड़ी रकम देनी थी, अतः उस रकम के भुगतान में उससे वरार ले लिया गया।

डलहौज़ी ने कुछ जागीरें और पेंशनें वन्द कर दी थीं। अर्काट के नवाब और तंजोर के राजा से शासन का अधिकार बहुत दिन पहले ही ले लिया गया था, जब उनका देहान्त होगया तो उनकी पेंशनें और उपाधियां वन्द करदी गईं। पदच्युत पेशवा वाजीराव के मरने पर डलहौज़ी ने उसके धर्मपुत्र दोदुपंत को, जो नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है, आठ लाख वार्षिक पेंशन देते रहने से इनकार कर दिया। गवर्नर जनरल ने यह भी योजना पेश की थी कि शाह आलम के पोते वहादुरशाह के मरने पर, जो इस समय दिल्ली का नाममात्र का बादशाह रह गया था, उसके

वंशजों से राजा की उपाधि छीन ली जाय और उसके परिवार से किला खाली करा लिया जाय । डाइरेक्टरों ने इनमें से अंतिम दो योजनाओं को मंजूर कर लिया ।

राज्य का विस्तार—यह हम देल ही आये हैं कि किस प्रकार लार्ड डलहौजी ने युद्ध करने और रियासतें नष्ट करने की नीति से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में लगभग वद रूप दे दिया, जिसमें हम उसे इस समय देख रहे हैं । उसके शासनकाल में ही भारत के वर्तमान राजनीतिक विभाग का रूप निश्चित हुआ ।

रेल और तार का जो जाल आज कल देश भर में बिछा हुआ है, डलहौजी को उनका जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि

इन दोनों का आरम्भ उसी ने किया था । पब्लिक-

रेल, तार और

वर्क्स डिपार्टमेंट भी उसी ने बनाया था और

डाकखाना

गंगा की नहर का बनाना भी उसी के समय में

आरम्भ हुआ था । उसने सिंचाई के लिए अनेक व्यवस्थाएं की थीं । डाकखाने के महकमे का वर्तमान रूप भी उसी का दिया हुआ है । उसने भारतवर्ष भर में आध आना चिट्ठी का प्रबन्ध जारी किया ।

इसके अतिरिक्त उसने अन्य भी अनेक उपयोगी काम किए । उसने भारतीयों की शिक्षा के लिए असाधारण यत्न किया ।

उत्तर पश्चिम प्रांतों में देशी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था करने के अतिरिक्त सर चार्ल्स वुड (जो उस समय शासन परिषद् का सभापति था) के प्रसिद्ध खरीते को

भी, जो भारत की शिक्षा के विषय पर बड़ा महत्वपूर्ण खरीता है, उसी ने तैयार करवाया था। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी की शिक्षा तक, जहां तक सम्भव हो सके, अंग्रेजी और देशी भाषा की मिश्रित शिक्षा का प्रतिपादन किया गया था।

नवीन अधिकारपत्र (१८५३)—कम्पनी को नया अधिकारपत्र दिया गया और उसमें जो जो परिवर्तन किए गए, नए परिवर्तन उनका कारण लार्ड डलहौजी था। भारत के प्रदेशों को कम्पनी के शासन में उस समय तक रखने की बात लिखी गई “ जब तक पार्लियामेंट कुछ और निश्चय न करे। ” डाइरेक्टरों के संघ को सिविल सर्विस की नियुक्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया और उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता की परीक्षा आवश्यक हो गई। गवर्नर जनरल को बङ्गाल के शासन भार से मुक्त कर दिया गया और शासन प्रबन्ध एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में सौंप दिया गया। प्रत्येक प्रांत से एक सदस्य को गवर्नर जनरल की कौन्सिल में निर्वाचित किया गया, जिससे भारत में ‘शिशु पार्लियामेंट’ का जन्म हुआ—हा, भारतीय दृष्टिकोण से वह कौन्सिल लोकहित की सच्ची प्रतिनिधि नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसके सारे सदस्य सरकारी होते थे।

सन १८५६ के मार्च में डलहौजी ने भारत से विदा ली। कठिन परिश्रम से उसका स्वास्थ्य नष्ट हो गया था। इङ्ग्लैंड पहुँचने

उसके कार्य पर स्वदेश के लिए उसकी अमूल्य सेवाओं के बदले में उसे अनेक प्रकार से सम्मानित किया गया। परन्तु इसके कुछ ही समय बाद भारतवर्ष में भयंकर विद्रोह उठ खड़ा हुआ और तब डलहौज़ी की नीति की तीव्र आलोचना की जाने लगी। इससे उसके कमज़ोर स्वास्थ्य पर और भी घातक प्रभाव पड़ा और वह १६ दिसम्बर सन १८६० को मर गया।

डलहौज़ी की गणना ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापकों में की जाती है। उसने भारत में बहुत से सर्वजन हितकारी काम भी किए थे। हम पहले ही कह चुके हैं कि भारत के वर्तमान स्वरूप का जन्मदाता वही था। अपने शासन में वह अनथक रूप से और सब दिशाओं में काम करता रहा। परन्तु उसके राजनीतिक कार्य इतने उम्र थे कि बहुत से भारतीयों में उनके द्वारा तीव्र प्रतिहिंसा की भावना जाग गई। खास तौर से जिन राजाओं को उसने पदच्युत किया था, या जिनकी वृत्तियां बन्द की थीं, वे अंग्रेज़ी राज्य के कट्टर शत्रु बन गए और उसका परिणाम सन १८५७ के गदर के रूप में प्रकट हुआ।

प्रश्न

१. सिक्खों की दूसरी लड़ाई के क्या कारण थे ? पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का संक्षिप्त विवरण लिखो।
२. संक्षेप से बर्मा के दूसरे युद्ध का हाल लिखो।
३. "लेप्स के विधान" से तुम क्या समझते हो ? डलहौज़ी ने

इस विधान की सहायता से जितने प्रदेशों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था, उनके नाम लिखो ।

४. लार्ड डलहौजी के समय में भारत ने जो भौतिक और आर्थिक उन्नति की, उसका विवरण लिखो ।

५. अंग्रेजों ने मुल्तान को अपने राज्य में कैसे मिलाया ।



तेरहवां अध्याय

लार्ड कैनिंग (१८५६-१८५८)

सन ५७ का विद्रोह

डलहौज़ी के वाद जब लार्ड कैनिंग ने शासन की वागडोर अपने हाथ में ली, तो उस समय सरसरी निगाह से देखने पर

भारत सरसरी निगाह से देखने में शांत था तो भारत की अवस्था विल्कुल शांत प्रतीत होती थी, परन्तु वस्तुतः स्थिति यह नहीं थी। ऐसे लोग भी थे, जो ताड़ गए थे कि असली स्थिति अन्दर ही अन्दर भयंकर हो गई है। जब लार्ड

कैनिंग को कम्पनी के डाइरेक्टरों ने, उसके भारत में आने से पहले, सम्मान-प्रदर्शनार्थ भोज दिया तो उस अवसर पर उसने जो कुछ कहा, वह वाद में अचरशः सत्य सिद्ध हुआ। उसने कहा—“यह भी पूरा तरह सम्भव है कि भारतवर्ष के आकाश में जो यद्यपि आजकल विल्कुल शांत दिखाई पड़ रहा है, शीघ्र ही एक बादल दिखाई देने लगे, जो आरम्भ में एक आदमी के हाथ

से अधिक बढ़ा न हो, परन्तु बाद में ऐसा भयंकर रूप धारण कर ले कि वहाँ हमारी बर्बादी के लक्षण दिखाई देने लगे और उसका मुकाबला करने में हम बिल्कुल अशक्त साबित हों।” ऐसे तूफ़ान के चिन्ह उत्तर, पश्चिम की ओर से दिखाई देने लगे थे। फ़ारस वालों ने हिरात पर अधिकार कर लिया था, जो अफ़ग़ानिस्तान की कुंजी समझा जाता था। कौनिंग को फ़ारस की खाड़ी से एक सेना भेज कर युद्ध शुरू करना पड़ा। फ़ारस का शाह हार गया और उसने हिरात से अपना सम्बन्ध अलग कर लिया।

गदर और उसके कारण—भारत में भी अशांति की सामग्री काफ़ी मौजूद थी। भारत में पाश्चात्य तरीकों का इस्तेमाल शुरू हो जाने से लोगों के दिलों में सन्देह पैदा सामाजिक अशांति हो गया था कि सरकार सब जातियों को धर्म-भ्रष्ट करना चाहती है और ईसाई धर्म के सिवाय और किसी को नहीं रखना चाहती। रेल, तार पाश्चात्य शिक्षा और अन्य अनेक पुराने रातिरिवाजों के निषेध से लोगों ने समझा कि बस, सरकार का यही एक उद्देश्य है—सब को ईसाई बनाना।

जनसाधारण की इस प्रकार की भावनाओं से अपना राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करने वालों की भी कमी नहीं थी। सब से पहले मुग़ल सम्राट हो था, जो अच्छी तरह जानता था कि अब वह राजमहल में इने गिने दिन ही रह राज नीतिक आयगा। इसके बाद मृत पेशवा का धर्मपुत्र असुविधाएं नाना साहब था जिसकी पैन्शन बन्द कर दी गई

थी। झांसी की युवती रानी भी असन्तुष्ट थी। असन्तोष की इस लहर में जो कुछ कसर बाकी रह गई थी, उसे मुन्तकिल की नीति ने पूरा कर दिया अन्य देशों राजाओं को अपने सम्बन्ध में भी यह आशंका होने लगी कि जब ब्रिटिश सरकार राज्य बढ़ाने की नीति पर उतारू है तो न मालूम कब हमारी भी यही दशा हो जाय।

उधर सिपाहियों की अपनी कुछ निजी शिकायतें भी थीं। जो सारी शिकायतों के साथ मिल कर बहुत गम्भीर हो गई थीं। जनरल सर्दिस एन्लिस्टमेट के अनुसार, सैनिक अशांति जिसे कैनिंग के शासन काल में पास किया गया था, प्रत्येक सिपाही को आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी भेजा जा सकता था। यह विधान सिपाहियों को अच्छा नहीं लगा। विशेषकर उच्च जाति के ब्राह्मण इससे बहुत असन्तुष्ट हुए क्योंकि वे समुद्र यात्रा करना धर्म विरुद्ध समझते थे। हिन्दुस्तानी सिपाही संख्या में अंग्रेज सैनिकों से पाँचगुने थे, इसलिये उन्हें अपनी शक्ति में विश्वास हो गया। अर्काट और पलासी के युद्ध के समय से अंग्रेजों को अजेय समझा जाता था, उस धारणा को अफगान युद्ध, सिक्खों के अपूर्व शौर्य और क्रीमियन युद्ध में अंग्रेजों की सामयिक हार से गहरा धक्का लगा था। अंग्रेजों के पतन की इन किम्बदन्तियों को इस तरह की पुरानी भविष्य-वाणियों से और भी बल मिल गया कि अंग्रेजों की हुकूमत पलासी की लड़ाई के बाद १०० वर्ष तक ही रहेगी और अब १०० वर्ष

समाप्त हो गए थे ।

मसाला तैयार था, आग लगाने की देर थी । यह काम सेना में एक नए ढङ्ग की बन्दूक के इस्तेमाल किए जाने से खुदबखुद

विद्रोह का प्रत्यक्ष कारण ही हो गया । इस बन्दूक के कारतूस के कायज़ो सिरे पर चिकनाइट लगी होती थी और उसे इस्तेमाल करने से पहले दातों से फाड़ना पड़ता था ।

उस चिकनाइट में जानवरों की चर्वी इस्तेमाल की गई थी, अतः हिन्दू और मुसल्मान दोनों जाति के सिपाहियों को विश्वास हो गया कि यह सब उन्हें धर्मभ्रष्ट करने के लिए किया जा रहा है । मामला समझाने और गलती को दुरुस्त करने की भरसक कोशिश की गई । कारतूस को दांत से फाड़ने की आज्ञा वापिस ले ली गई, चिकने कारतूस का उपयोग बन्द कर दिया गया, पर जो बात होनी थी, वह हो चुकी थी ।

विद्रोह का आरम्भ सन १८५७ की १० मई को मेरठ की छावनी से हुआ । यहाँ पर कुछ सिपाहियों ने चिकने कारतूस

मेरठ इस्तेमाल करने से इनकार किया । उन्हें जेल में डाल दिया गया । इस पर सारी सेना एकत्र हो गई । उसने अपने अफ़सरो को कत्ल कर डाला, जेलखाना तोड़ डाला, अपने साथियों को मुक्त कर दिया और दिल्ली जाकर वहाँ मुग़ल बादशाह (बहादुरशाह) को देश का शाहशाह घोषित कर दिया । इस आग की चिनगारी सारे उत्तर पश्चिम प्रांत (सयुक्तप्रांत), अवध और निचले बङ्गाल तक फैल गई । पर सर जानलारैन्स के शासन की

वदौलत पंजाब का अधिकांश भाग शान्त और पंजाब शांत रहा। राज-भक्त ही बना रहा। तब से केवल आठ वर्ष ही पहले सिक्ख अंग्रेजों के घोर शत्रु थे, पर अब वे अंग्रेजों के शत्रुओं के विरुद्ध हथियार उठाने को तैयार हो गए। पंजाब न केवल तटस्थ रहा, परन्तु उसने विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों को मदद भी दी।

गदर के केन्द्रस्थल तीन थे—कानपुर, लखनऊ और दिल्ली। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब ने ग्रहण किया और त्रिटिश सेना का जीवन उसकी दया पर निर्भर रह गया। कानपुर के नाना साहब सैकड़ों यूरोपियन, जिनमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे तलवार के घाट पार उतार दिए

गए। नाना साहब के अनुयाइयों को हैबलाक के नेतृत्व में त्रिटिश सेना ने हरा दिया, पर वह स्वयं किसी प्रकार भाग निकला। विद्रोही लखनऊ के चारों ओर घेरा डाले पड़े थे। यूरोपियन लोगो ने रेजीडेन्सी में पनाह ली, जहां सर हैनरी लारैन्स

की मृत्यु होने पर वे उस समय तक वीरता के साथ अपनी रक्षा करते रहे, जब तक जनरल हैबलाक और औटराम ने आकर उन्हें छुटकारा न दिलाया। पर इस छुटकारा दिलाने वाली सेना को भी सर कालिन कैम्पवेल के आगमन तक, सब के साथ रेजीडेन्सी में ही घिरे रहना पड़ा। दिल्ली ने घेरे से तीन महीने तक अपनी रक्षा की और अन्त में उसे छुटकारा मिला और लोग निश्चिन्त हुए। दिल्ली पर पुनः अधिकार करने का श्रेय सर जान

दिल्ली लारेन्स को है, जिसने फ्रौजों पर फ्रौजें भेजना जारी रक्खा। आक्रमणकारियों में प्रमुख व्यक्ति जान निकल-सन था, जो ठीक विजय के अवसर पर ही मारा गया। इसके बाद ही मुगल सम्राट के लड़को को गिरफ्तार कर लिया गया और स्वयं सम्राट को भी कैद करके ब्रिटिश बर्मा में भेज दिया गया। मध्य भारत और बुन्देलखण्ड के विद्रोहियों के नेता तातिया टोपी और झांसी की रानी थे। झांसी की रानी बड़ी वीरता के साथ लड़ी और वीरता के साथ युद्ध में काम आई। तातिया अमेज़ों के कब्जे में आगया और उसे फासी दे दी गई। मुगल सम्राट के दोनों पुत्रों को दिल्ली में सरे बाज़ार फासी पर लटका दिया गया। इस तरह विद्रोह को दबा दिया गया।

सारे विद्रोह में गवर्नर जनरल ने अपूर्व समय से काम लिया। उसने बड़े से बड़े खतरे में भी अपनी बुद्धि को उद्विग्न नहीं होने दिया। देश में पुनः इतनी शांति स्थापित हो जाने का मुख्य श्रेय उसी को है।

इस गदर का तत्कालिक फल यह हुआ कि भारत का शासन कम्पनी के हाथ से निकल कर साम्राज्ञी बिकटोरिया के हाथ में चला गया। २३ अगस्त सन १८५८ को पास शासनाधिकार में परिवर्तन किए गए पार्लियामेंट के एक विधान के अनुसार डाइरेक्टरों का बोर्ड और शासन-परिषद् तोड़ दिए गए और उनके स्थान पर भारत मन्त्री की व युक्ति हुई और उसकी सहायता के लिए पन्द्रह सदस्यों की एक

कौन्सिल नियुक्त की गई जो इण्डिया कौन्सिल कहलाई जाने लगी। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी मिली और पहला वायसराय लार्ड कैनिंग नियुक्त हुआ।

भारत में इस अधिकार-परिवर्तन की घोषणा महारानी विक्टोरिया के प्रसिद्ध घोषणापत्र द्वारा १ नवम्बर सन १८५८ को की गई। यह अंग्रेज़ी भारत के अधिकारों का घोषणापत्र कहलाता है। इसमें देशी नरेशों के अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा करने का वचन दिया गया और हत्या के अपराधियों को छोड़ कर बाकी सारे विद्रोहियों को क्षमा कर दिया गया।

महारानी विक्टोरिया की इस प्रसिद्ध घोषणामें कहा गया था—
 “हमारी सम्पूर्ण प्रजाका प्रत्येक भारतीय चाहे वह किसी भी वर्ण, जाति, जन्म या धर्म का क्यों न हो—राज्य का कोई भी पद अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी तरह की रुकावट या पक्षपात न किया जायगा। जो जिस पद के योग्य होगा, वह उस पर नियुक्त किया जा सकेगा।” यह घोषणा सन १८३३ वाली घोषणा का अधिक प्रामाणिक और उत्तम स्वरूप था।

इस घोषणापत्र के अन्त में आश्वासन दिया गया कि प्रजा की भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए हर तरह का द्योग किया जायगा।

चौदहवां अध्याय

लार्ड कैनिंग से लार्ड नार्थब्रुक तक (१८५८ से १८७६ तक)

लार्ड कैनिंग (१८५८-१८६२) — कैनिंग अभी निश्चिन्त नहीं हुआ था । भारत में उसके जितने देशवासी थे, वे सब प्रतिहिंसा की नीति के पक्ष में थे, परन्तु यह शान्त करने की नीति नीति कैनिंग के विचारों के विलकुल खिलाफ थी । वह तो आपस में फिर मेलजोल कर लेने के पक्ष में था । उसने विद्रोहियों को दण्ड देते समय बुद्धि विवैक को कभी नहीं छोड़ा । अपनी नमी के कारण वह तिरस्कार-सूचक उपहास में “दयालु कैनिंग” कहलाने लगा । परन्तु वायसराय इस तरह के ताने सुन कर भी अपनी नीति से तनिक न टला । वह न लोगों के कोलाहल की विलकुल उपेक्षा करता रहा ।

इस गद्दर ने आंखें खोल देने का काम किया । कम्पनी के गोवानी और कौञ्जी शासन के दोष प्रकाश में आगए और

शासनप्रबन्ध में परिवर्तन तत्काल पुनर्व्यवस्था का कार्य आरम्भ कर दिया गया। सन १८६० में भारतीय दण्ड विधान, जिसे लार्ड मैकाले ने बनाया था, पास कर दिया गया।

इसके बाद दूसरे वर्ष सिविल और किमिनल प्रोसीजरकोड पास किये गये। पुराने डङ्ग की सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह वाकायदा हाईकोर्ट कायम किए गए। पर इन सारे परिवर्तनों से अधिक महत्वपूर्ण

परिवर्तन सन १८६१ में इण्डियन कौन्सिल एक्ट द्वारा किए गए। इस ऐक्ट के अनुसार कौन्सिल ऐक्ट गवर्नर जनरल की कौन्सिल में कम से कम आठ

सदस्यों का गैरसरकारी होना जरूरी होगया। गदर के कारण बहुत आर्थिक क्षति हुई थी, इसलिए जेम्स विल्सन नामी एव

आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन अग्रेज विशेषज्ञ को आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए भेजा गया, जो इस कौन्सिल का पहला अर्थ-सदस्य बना। उसने चुंग

और सिक्के में परिवर्तन किए और व्यय में बहुत कुछ काट छाट की। इसके अतिरिक्त जनता को शांत करने के लिए कैनिंग ने कुछ और काम भी किए। उसने "मुन्तकिल" की नीति को उठा दिया तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटिय स्थापित कीं।

अपना कार्यभार सन १८६२ की मार्च में अपने उत्तराधि

लार्ड एल्गिन (१८६२-१८६३)—लार्ड एल्गिन अपने पद पर एक वर्ष तक रहने के बाद सन १८६३ में धर्मशाला नामक स्थान में मर गया । उसके शासन काल की मुख्य घटना यह है कि पंजाब के उत्तर-पश्चिम प्रांत की ओर एक फ़ौज कुछ उपद्रवी अफ़ग़ानों को, जो बहावी नाम से प्रसिद्ध थे, दवाने के लिए भेजी गई ।

लार्ड लॉरेंस (१८६४-१८३९)—लार्ड एल्गिन की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक मद्रास का गवर्नर वायसराय का कार्य सम्हालने रहा । उत्तर-पूर्व प्रदेश में अशान्ति फैल रही थी । बात यह थी कि भूटान के राजा ने हिमालय की नलदुटी में दुआर्स नामक ब्रिटिश प्रदेश को रौंद डाला था । आराद्धा थी कि उससे कहीं नाजुक स्थिति उपस्थित न होजाय । इसलिए सर जान लॉरेंस को, जिसने पंजाब के शासन प्रबन्ध और सिपाही-विद्रोह में अपना कार्य इतनी चतुरता और बुद्धिमत्ता के साथ किया था, अब भारत का वायसराय नियुक्त किया गया । भूटान को संना भेजी गई और बोडो-सो अनियमित लड़ाई के बाद वहाँ शांति स्थापित होगई । ब्रिटिश सरकार ने भूटान को कुछ शुक च देना स्वीकार कर लिया, इस पर भूटान के राजा ने दुआर्स वापिस लौटा दिया ।

सन १८६३ में उड़ीसा में बयदूर अछाल पड़ा । अमी ठरु इस प्रांत में रेंडें नदी बनी थी, अतः अनाज प्रचुर परिमाण में

उड़ीसाका
अ काल

नहीं भेजा जा सकता था। बाढ़ों के कारण अकाल-प्रस्त प्रजा का कष्ट और भी बढ़ गया। अनुमान किया जाता है कि इस अकाल में कम से कम बीस

लाख आदमी मरे होंगे। एक अकाल कमिशन नियुक्त किया गया। इसने भविष्य में ऐसे अकालों का सामना करने के उपायों पर विचार किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह निश्चय किया गया कि अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे लोगों को भूखों मरने से बचाएँ। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के वार्षिक कार्यक्रम में सड़कों आदि में वृद्धि करना भी शामिल कर लिया गया।

सर जान लारेस देश के किसानों के सम्बन्ध में बड़ी दिल-चस्पी लेता था। पंजाब और अवध के लगान कानून पास होने का, जिसके कारण इन प्रान्तों में कृषि विषयक किसानों को बहुत कुछ सुविधाएं प्राप्त हो गईं, का नू न श्रेय भी उसी को है।

सन १८६३ में काबुल का शासक अमीर दोस्त मुहम्मदखां मर गया। अब राज्य के लिये उसके बेटों, अफज़लखां और शेरखां, में झगड़ा होने लगा। शेरखां को काबुल से खदेड़ दिया गया और उसने ब्रिटिश सरकार से सहायता की प्रार्थना की। सर जान लारैन्स ने कहा कि जो कोई गद्दी पर अधिकार करने में सफल होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को काबुल

अफ़ग़ानिस्तान
के प्रति "साव-
धान तटस्थता"

का शासक मान लेगी । उसने इस झगड़े में किसी तरफ़ का पक्ष प्रहण करने से इनकार कर दिया ; इस नीति को "सावधान-तटस्थता" की नीति कहा गया है, यह अंग्रेजों के लिए सुविधाजनक भी थी, क्योंकि वे इसी हस्तक्षेप की बदौलत हाल ही में काफ़ी नुक़सान उठा चुके थे । अन्त में शेरअलीखां को सफलता हुई और वायसराय ने उसे काबुल का अमीर स्वीकार कर लिया, परन्तु उसके साथ किसी प्रकार की विशेष मैत्री स्थापित करने से इनकार कर दिया ।

लार्ड मेयो (१८६१-१८७२)—सर जान लारेंस के वाद जनवरी सन १८६६ में भारत का शासन-भार लार्ड मेयो ने प्रहण किया । अपने आगमन के थोड़े दिनों बाद ही उसने अम्बाला में एक दरवार किया और उसमें शेरअलीखां को भेंट के लिए आमन्त्रित, किया । यहां उसकी बड़ी आवभगत की गई और इससे उसके मन में सर जान लारेंस के शुष्क व्यवहार से अंग्रेज़ी सरकार के लिए जो विरुद्ध भावनाएँ पैदा होगई थी, वे लगभग शान्त होगईं । अमीर स्वयं ब्रिटिश सरकार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध करना चाहता था, परन्तु वायसराय ने इस सम्बन्ध में अब भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई । हां लार्ड मेयो ने उसके नक़द शुल्क में वृद्धि कर दी और उसे हथियार प्राप्त करने में मदद देने का वचन भी दिया ।

भारतीय नरेश—गद्दर के वाद से भारतीय नरेशों के

प्रति भारत सरकार की नीति में भारो परिवर्तन आगया था । अब तक देशी रियासतो से उसका जितना सम्बन्ध था, अब सरकार उसे पहले से बहुत अधिक घनिष्ठ कर लेना चाहती थी ।

यह परिवर्तन कैनिंग के शासनकाल में आरम्भ हुआ था । लार्ड मेयो ने इस परिवर्तन की नीति को उसी प्रकार जारी रक्खा । उसका मृदुल स्वभाव और मिलनसार प्रकृति इस उद्देश्य की

पूर्ति में और भी अधिक सहायक सिद्ध हुए । उसने आश्वासन

राजपूताने में एक दरवार करके सारे भारतीय नरेशों को आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा की जाएगी । साथ ही उसने उन्हें भी

अजमेर का अंग्रेजी सरकार से सङ्योग करने की सलाह मेयो कालेज

दी । वायसराय सिर्फ इतना ही करके सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसने राजाओं के लड़कों की शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कालेज स्थापित किया । इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राजपुत्रों को अनुकूल शिक्षा देकर उन्हें स्वभाव ही से अपने प्रति मित्रतापूर्ण मनोवृत्ति वाला बना लिया जाय ।

आर्थिक व्यवस्था—लार्ड मेयो ने आर्थिक व्यवस्था को सुन्दर रूप देकर भारत की बहुत बड़ी सेवा की । उसके शासन-भार ग्रहण करने के समय धन का बड़ा अभाव था, इसलिए उसे कई नए कर लगाने पड़े और बड़ी किफायतशारी से काम लेना पड़ा । परन्तु उसके सारे सुधारों में सब से अधिक लाभकारी और उल्लेखनीय सुधार वह था, जिसके अनुसार उसने

किसी निश्चित सीमा तक प्रत्येक प्रांत को अपनी आर्थिक व्यवस्था का स्वयं जिम्मेवार बना दिया। अब तक यह कायदा

कि प्रांतीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार से वार्षिक रकमों मिलती थीं और प्रांत अनेक अवसरों पर उन बड़ी बेपरवाही के साथ खर्च कर डालते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे जो कुछ बचाएँगे वह स

केन्द्रीय सरकार के कोष में लौट जायगा। इस नवीन विधान अनुसार पांच वर्ष तक के लिए प्रांतीय सरकारों को अपने खर्च का भार उठाने के लिए कुछ रकमों मंजूर की गईं और उनके लिए आय के कुछ विभाग भी नियत कर दिए गए। यदि इस नव आर्थिक प्रवन्ध की बदौलत प्रांतीय सरकारें खर्च के बाद कुछ बचा सकें तो वह बचत उसी प्रांत के हित के लिए ही खर्च करने का सिद्धान्त मान लिया गया। इस प्रांतीय उत्तरदायित्व की नीति से प्रांतीय सरकारों को किफायतशारी से काम लेने के लिए काफी प्रलोभन मिलने लगा।

सन १८७२ की फरवरी में लार्ड मेयो अण्डमान में कैदियों के रहन सहन को देख कर शाम के समय बन्दरगाह की ओर लौट रहा था कि एक उन्मत्त पठान ने उसके वलक के धत्या चुपचाप पीछा किया और यकायक उसकी पीठ में छुरा भाँक दिया, जिससे वह तत्काल ही मर गया।

लार्ड नार्थब्रुक (१८७२-१८७३)—इस नवीन वायसराय में यद्यपि व्यवसायात्मिका बुद्धि का अभाव नहीं था, परन्तु

उसमें अपने पूर्ववर्ती शासक जैसी मिलनसारी भी नहीं थी, और इसी लिए काबुल के अमीर शेरअलीखां ने उसके शुष्क व्यवहार से निराश हो कर रूस से सहायता की प्रार्थना की।

वड़ौदा के शासक मल्हारराव गायकवाड़ पर रेजीडेण्ट को विष देने की कोशिश करने का अभियोग चला और उसे गद्दी से उतार दिया गया। लार्ड नार्थब्रुक के शासन काल में दूसरी शोचनीय दुर्घटना सन १८७३-१८७४ का बिहार का अकाल था। अकाल-पीड़ितों की सहायता करने के लिए हर तरह का यत्न किया गया, किन्तु उस प्रयत्न में व्यर्थता बहुत आ गई थी, आदमी भूख से तड़प तड़प कर मर गये।

नार्थब्रुक के समय में एल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस आफ वेल्स ने (जो बाद में सप्तम एडवर्ड कहलाए) सन १८७५-१८७६ में इस देश में भ्रमण किया और हर जगह उनका राजभक्तिपूर्ण स्वागत हुआ।

प्रश्न

१. लार्ड कैनिंग ने शासन व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए और उसने जनता को शान्त करने के लिए क्या क्या उपाय किए ?

२. लार्ड लॉरेस ने अफ़ग़ानिस्तान के शासक के प्रति कैसी नीति रखी ? उस नीति की संक्षिप्त आलोचना करो।

३. नाइं मेयो ने कौन कौन से आर्थिक मुद्धार किए ?—प्रतीय उत्तरदायित्व की ब्यवस्था पर प्रकाश जलो ।

४. निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखो—

इण्डियन कौन्सिल एक्ट १८६१, उर्गीसा का अकाल, “सावधान तटस्थता” और शेर अलीसा ।

पन्द्रहवां अध्याय

लार्ड लिटन और लार्ड रिपन

लार्ड लिटन (१८७६-१८८०)—जब सन १८७० में लार्ड नार्थग्रुक भारत से वापिस गया तो उसकी जगह लार्ड लिटन को नियुक्त किया गया। उसने सन १८७७ के जनवरी मास में दिल्ली में एक दरबार किया, जिसमें घोषणा की गई कि महारानी विक्टोरिया ने कैसरे-हिन्द की पदवी नियमपूर्वक धारण कर ली है। इस घोषणा को भारत के सारे जिलों में सुनाया गया और इस अवसर पर लोगो ने अपनी राजभक्ति दिखाई। इन दिनों दक्षिण में भयंकर अकाल फैला हुआ था और वहां हजारों आदमी भूखों मर रहे थे। अकाल निवारणार्थ लार्ड लिटन मद्रास प्रेज़ीडेन्सी में खुद गया और वहां उसने पीड़ित लोगो की सहायता करने की भरसक कोशिश की। काफ़ी रुपया खर्च किया गया और अकाल पीड़ित लोगो के भोजन का भी यथाशक्ति प्रबन्ध किया गया। परन्तु

भारत की
साम्राज्ञी
विक्टोरिया

दक्षिण का
अकाल

इतनी कोशिश करने पर भी लोग वही भारी संख्या में बाल के प्राम होने । भारत के इतिहास में ऐसा व्यापक और भयंकर अकाल एक नहीं मटना था । अनुमान किया जाता है कि दुर्भिक्ष-पीड़ित प्रदेश २,५०,००० वर्गमील रहा होगा । हर प्रकार की सहायता करने की कोशिश करने पर भी, कहा जाता है कि इस अकाल में पचास लाख से दस आठवीं नदी मरे होंगे ।

उस समय ब्रिटेन का रूस के साथ युद्ध छिडा हुआ था और रूस को सफल होता देख कर भारत के देशी भाषाओं के कुछ समाचार पत्रों ने राजद्रोहपूर्ण लेख प्रकाशित करने आरम्भ

वर्नाकुलर
प्रेस-अक्ट

कर दिए । इस पर लार्ड लिटन ने देशी समाचार पत्र सम्बन्धी विधान (Vernacular Press Act.) जारी किया, जिसके अनुसार देशी भाषाओं के

सम्पूर्ण पत्रों के सम्पादकों को राजद्रोह की भावना उत्पन्न करने वाले लेख न लिखने के लिए बाधित कर दिया गया । इस प्रकार देशी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में एक प्रकार की ईर्ष्या उत्पन्न करने वाला भेद पड़ गया, क्योंकि अंग्रेजी समाचार पत्रों के लिए ऐसी कोई बाधा नहीं थी ।

८ जनवरी सन १८७७ को लार्ड लिटन ने अलीगढ़ में ओरियण्टल कालेज की नींव रखी । आज कल वही कालेज

सर सय्यद
अहमद और
अलीगढ़ कालेज

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है । इस कालेज को सर सय्यद अहमद खां ने कायम किया था । वह उन्नीसवीं सदी में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता थे । सर सय्यद

अहमद एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेज़ी का जानकार न होते हुए भी अपने सहधर्मियों को पाश्चात्य विचारों से अभिज्ञ होने की सलाह दी। वह बहुत बुद्धिमान और बड़े रोबदाव वाले आदमी थे, अपनी योग्यता और प्रभाव के कारण वह कट्टर विचारों के मुसलमानों के सकुचित दृष्टिकोण में बहुत कुछ परिवर्तन लाने में कामयाब होसके। तब तक प्रायः मुसलमान पाश्चात्य शिक्षा के विरुद्ध थे। सर सैयद की गणना मुसलमानों को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाले बड़े बड़े नेताओं में की जाती है।

अफ़गानिस्तान—जिस समय लार्ड लिटन इंग्लैंड से भारत के लिये रवाना हुआ तो वहाँ की गवर्नमेंटने उसे खास तौर से हिदायत करदी थी कि वह अफ़गानिस्तान के अफ़गानिस्तान की दूसरी लड़ाई अमीर शेरअली के साथ अवश्य सन्धि कर ले। हम देख ही चुके हैं कि वह ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से किस प्रकार निराश हो गया था। उसकी और उसकी प्रजा की धारणा थी कि अंग्रेज़ परले सिरे के स्वार्थी हैं। वह ऐसी सन्धि करना चाहता था जिसके द्वारा अफ़गानिस्तान की गद्दी का स्वामी वह और उसके वंशज ही बने रहें। परन्तु उसकी इस अभिलाषा को लार्ड लिटन के पूर्ववर्ती गवर्नर जनरलो ने पूरा न होने दिया। लार्ड लिटन ने उससे एक अंग्रेज़ो मिशन से भेंट करने का अनुरोध किया, परन्तु उसे इस कार्य से भयंकर परियााम की सम्भावना थी। अतः उसने नन्नता के साथ इस मिशन से भेंट करने से इन्कार कर दिया। लार्ड लिटन ने इन् बात को ब्रिटिश

दितों की 'धृष्ट्या व्यंजक उपेक्षा समझा और अमोर को सावधान कर दिया कि इस अस्वीकृति की कीमत शायद शेरअली ने उसे महंगे दामों में अदा करनी पड़ेगी । पर शेर-ब्रिटिश राजदूत अला बरावर इन्कार करता रहा । इन्हीं दिनों ब्रिटिश गेट करनेसे सरकार ने क्वेटा पर अधिकार कर लिया, जिससे इन्कार का दिया अमीर के छक्के छूट गए । इस स्थान के परे बोलान का दर्रा शुरू होता है, जो अफ़गानिस्तान को जाने का एक मार्ग है । अब अमीर को आशंका हुई कि अंग्रेज़ उसके देश पर धावा करना चाहते हैं । इसके बाद ही एक और बात हुई जिससे अमीर की आशंका और भी बढ़ गई । अंग्रेज़ों ने गिलगित में एक अंग्रेज़ी सेना स्थापित कर दी ।

इधर अमीर को सन् १८७८ में अपनी इच्छा के विरुद्ध रूसी दूत से भेंट करनी पड़ी । इस बात ने बहुत संगीन रूप धारण कर लिया । उस समय उसकी अवस्था लार्ड लिटन के शब्दों में 'लोहे के दो खम्भों के बीच में एक मिट्टी के वर्तन जैसी थी ।' वह यह जानता था कि अंग्रेज़ों से उसे तब तक सहायता नहीं मिल सकती, जब तक वह उनकी शर्तों को पूरी तरह मान न लेगा; परन्तु इन शर्तों को पूरा करना उसके लिए लगभग असम्भव-सा था । इसलिए बाधित हो कर उसने रूस के साथ भी बिगाड़ करना उचित नहीं समझा, बल्कि शीघ्र ही उसने रूस के साथ मैत्री और युद्ध घोषणा-स्थापित करली । इधर लार्ड लिटन ने एक

मिशन उससे भेंट करने को भेजा, जिसे उसने नम्रता के साथ खैबर के दर्रे से ही वापस लौट जाने को बाधित किया। इस पर वायसराय ने यह कह कर कि मिशन को अफ़गानिस्तान से बलपूर्वक खदेड़ दिया गया है, लड़ाई की घोषणा कर दी।

काबुल की ओर तीन रास्तोंसे तीन सेनाएँ खाना की गईं। अफ़गान सेना ने कोई रुकावट नहीं की और शेर अली को अपने देश से भागना पड़ा। इसके बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अमेज़ो ने उसके सबसे बड़े लडके याकूब खां को गद्दी पर बैठाना स्वीकृत कर लिया और मई सन १८७६ मे उससे एक सन्धि कर ली, जिसके अनुसार याकूब खां काबुल मे ब्रिटिश रेज़ीडेण्ट रखने पर राज़ी हो गया और उसने ब्रिटिश सरकार को दर्रे के कुछ ज़िले भी दिए।

पर ब्रिटिश विजय को स्थायी रूप न मिल सका और सन १८७६ मे विदेशियों की अधोनता मे रहने के विरुद्ध अफ़गानो मे तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होने क्रोध मे आकर रेज़ि-

डेण्ट और उसके संगी साधियों को मार डाला। इस कारण एक नई लड़ाई छिड गई। जनरल रौबर्ट्स ने काबुल पर धावा करके उस पर अधिकार

कर लिया। शहर मे मार्शल ला जारी कर दिया गया और बहुत से विद्रोहियों को फासी पर चढ़ा दिया गया। याकूबखां को गद्दी से उतार दिया गया और उसे पिछले हत्याकांड में भाग लेने के

सन्देश पर शाही कैदी की हैसियत से कलकत्ते भेज दिया गया। इसी समय इंग्लैण्ड में मन्त्रि-मण्डल के बदले जाने के कारण लिटन ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह अफ़गानिस्तान से शान्तिपूर्वक समझौता करने के लिए लार्ड रिपन को भेजा गया।

लार्ड रिपन (१८८ - १८८४)—इस समय तक सारे

अफ़गानिस्तान में विद्रोह की आग लग चुकी थी। याकूब खा का

भाई अयूबखा हिरात का शासक बन बैठा था
मायवंड की
दुर्घटना

आर उसने मायवड में एक ब्रिटिश सेना को भारी
शिकस्त दे कर अब कन्धार पर धावा बोल दिया

था। जनरल रायट्स काबुल और कंधार की रक्षा के लिए खाना

हुआ और उसने ३०० मील से अधिक का पार्वतीय मार्ग तीन

सप्ताह में तय कर लिया। उसने अयूब की सेना को हरा कर बुरी

तरह नष्ट कर डाला और इस प्रकार मायवड की दुर्घटना का

वदला ले लिया। इसके बाद ब्रिटिश सेना काबुल और कन्धार

से वापिस चली आई और अयूबखा ने हिरात पर एक बार पुनः

धावा करके कन्धार पर कब्ज़ा कर लिया।

जनरल रायट्स पर उसे शेर अली के भतीजे अब्दुर्रहमान के

की युद्ध विजय हाथों हार खानी पड़ी। इस विजयी को ब्रिटिश

सरकार ने काबुल का शासक स्वीकार कर लिया और भविष्य

में किसी विदेशी हमले से अफ़गानिस्तान की रक्षा करने को उत्तर-

दायित्व अपने ऊपर ले लिया।

भारत में जागृति—अफ़गानिस्तान का भगड़ा निपट

जाने के बाद लार्ड रिपन ने भारत की ओर अपना ध्यान दिया। अपने विचारों में वह—“ग्लैडस्टन के जमाने का लिबरल था; अतः उसने भारत के शासन में कुछ उदारता से काम लेना और शासक और शासित के भेद को, जहां तक हो सके, दूर करना अपना लक्ष्य बना लिया। वास्तव में भारत की जागृति का आरम्भ उसी के शासन-काल से होता है; उसी के शासन-काल में भारतीयों के हृदयों में वह विकलता और भावनाएँ उत्पन्न होने लगी थीं, जो किसी पराधीन देश में आत्म-विश्वास उत्पन्न करने का आवश्यक पूर्वाभास होती हैं।” पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और फलतः पाश्चात्य संस्कृति के प्रचार ने लोगों पर काफ़ी प्रभाव डालना आरम्भ कर

दिया था। इन भावनाओं के साथ लार्ड रिपन

भारत के साथ

की हार्दिक सहानुभूति थी और वह उनके लिए

सहानुभूति

यथाशक्ति अधिक से अधिक सुविधाएं भी

प्रदान करना चाहता था। वह इन भावनाओं का ऐसे ढङ्ग से उपयोग करना चाहता था, जिससे देश के अत्यन्त प्रभावशाली और सुयोग्य व्यक्ति अपने स्थानीय शासन प्रबन्ध में प्रमुख भाग ले सकें।

स्थानीय स्वराज्य (लोकल सेल्फ गवर्नमेंट)—इस

वायसराय का नाम उन अनेक विधानों के सम्बन्ध में विशेष तौर से याद किया जाता है, जिनके द्वारा भारत में स्थानीय स्वराज्य की नींव पड़ सकी। यह सच है कि प्रेज़ीडेन्सी शहरों (कलकत्ता,

बम्बई और मद्रास) में म्यूनिसिपल संस्थाओं की स्थापना इससे पहले ही हो चुकी थी, परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य शहरों में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ था । इन विधानों के द्वारा

डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्ड कायम किए गए और उन्हें सफ़ाई का प्रबन्ध करना, प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सड़कों को अच्छी

दशा में रखना और इसी प्रकार के अन्य कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई । गवर्नर जनरल की इच्छा थी कि इन संस्थाओं के सदस्यों में गैरसरकारी सदस्यों की संख्या अधिक हो और जहाँ कहीं सम्भव हो सका, उसने चुनाव की प्रथा को जारी भी किया ।

इन बोर्डों को अपना सभापति स्वयं चुनने का अधिकार दिया गया । हां, खास खास सूरतों में सरकार किसी नामज़द मेम्बर को

भी प्रधान बना सकती थी । गवर्नर जनरल को

राजनीतिक आशा थी कि इस तरीके से लोगों को राजनीतिक

शिक्षण शिक्षा मिलेगी, जिससे वे राजनीतिक कार्यों

को अधिक विस्तृत रूप से और अधिक व्यवस्थित ढङ्ग से पूरा

कर सकेंगे । पर बोर्डों के कर्मचारी उसकी उच्च आशाओं के

अनुरूप सिद्ध न हुए, तथापि ऐसी संस्थाओं की स्थापना

करना देश की कोई साधारण सेवा न थी । व्यावहारिक रूप में

अधिकारीवर्ग का प्रभुत्व पहले ही जैसा बना रहा और गैरसरकारी

सदस्य आगे बढ़नेमें कुछ संकोच से काम लेते रहे । मांटेगू चेम्स-

फोर्ड सुधारों तक उक्त स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आया था ।

लार्ड रिपन ने अपने शासन काल में जितने काम किए, उन इल्वर्ट विल की बदौलत वह भारतीय जनता का सब से अधिक प्रिय बन सका। यह विल वायसराय की शासन वरतें विल परिपद के कानूनी सदस्य मि० इल्वर्ट ने पेश किया था। इस विल का उद्देश यह था कि गैरसर्कारी अंग्रेज, विशेष कर वाय के वागों के मालिक, पहले की तरह अपने नौकरो के साथ घुरा व्यवहार न कर सके। इस समय तक ये लोग अपने भारतीय मजदूरों के साथ पशुओं का सा व्यवहार करते थे, और अभी कभी तो उन्हें जान से भी मार डालते थे, इस पर भी उन्हें प्रायः कोई दण्ड न मिलता था। यह प्रथा गुलामी की प्रथा से कुछ कम भयकर न थी। इल्वर्ट विल के अनुसार भारत के इतिहास में पहली बार अपराध के मामलों में अंग्रेजों के ऊपर देशी जजों को न्यायनिर्याय का अधिकार दिया गया। इस विल के पास होने से उन लोगों का, जिन्हें इससे हानि पहुँचने की सम्भावना थी, क्रोध भड़क उठा और ऐंग्लो इण्डियन पत्रों में लार्ड रिपन के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो गया। अन्त में इस आन्दोलन से दब कर लार्ड रिपन को एक समझौता करना पड़ा, जिसके अनुसार यूरोपियन अभियुक्त का अपराध निर्याय ऐसी ज्यूरी के हाथ में सौंपा गया, जिसमें कम से कम आधे यूरोपियन अवश्य हों।

लार्ड रिपन ने लार्ड लिटन का देशी पत्र सम्बन्धी विधान रद्द कर दिया और देशी पत्रों को एक बार पुनः अन्य पत्रों की तरह

अन्य हित- कारी कार्य सांख्यिक हितों की चर्चा करने की स्वतन्त्रता होगई। उसने एक शिक्षा समिति भी स्थापित की, जिसके फलस्वरूप प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था में उन्नति करने का प्रयत्न किया गया और शिक्षा के लिए किए जा रहे गैरसरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया गया। उसने एक और उल्लेखनीय कार्य यह भी किया कि राज्यच्युत मैसूर के राजा के—जिसे वेन्टिक ने गद्दी से उतार दिया था—धर्मपुत्र को पुनः मैसूर की गद्दी पर विठा दिया था।

सन १८८४ में रिपन ने इस्तीफा दे दिया। उसके जाने पर भारतीयों ने बड़ा खेद प्रकट किया। वे उसे अपने हितों का सच्चा समर्थक समझते थे। बहुत से भारतीयों की राय है कि उन्नीसवीं सदी के सम्पूर्ण वायसरायों में लार्ड रिपन सर्वश्रेष्ठ थे।

प्रश्न

१. अफ़गानिस्तान की दूसरी लड़ाई के क्या कारण थे? उसकी खास खास घटनाएं बर्णन करो।

२. लार्ड रिपन भारतीयों को इतना प्रिय कैसे हो गया था? उसके द्वारा किए गए किन्हीं दो प्रसिद्ध कार्यों का बर्णन करो।

३. निम्न लिखित पर संक्षिप्त नोट लिखो—

देशी-पत्र सम्बन्धी विधान (वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट), लोहउ संस्कृत गवर्नमेंट, इल्वर्ट विल।

सोलहवां अध्याय

लार्ड डफरिन, लार्ड लैंसडाउन और लार्ड एल्गिन

लार्ड डफरिन(१८८४ से १८८८)—लार्ड रिपन के बाद लार्ड डफरिन भारत का वायसराय नियुक्त हुआ। उन दिनों अफगान सरकार और रूस के साथ रूस-अफगान सरहद के पंजदेह विषय में बातचीत चल रही थी। नए वायसराय का ध्यान सब से पहले उसी की ओर आकर्षित हुआ। पंजदेह में रूसी और अफगानी सेना में मुठभेड़ होगई, पर इस दुर्घटना को भाग्य-वशा, लार्ड डफरिन के बुद्धि कौशल और अपदुर्रहमान के विवेक से कोई भयङ्कर रूप न मिल सका। अपदुर्रहमान अफगानिस्तान को दो बड़ी ताकतों की लड़ाई का मैदान नहीं बनाना चाहता था।

बर्मा के राजा थीवा के राज्य में बहुत अधिक संख्या में संगठित ढाके पड़ते थे, उनके कारण बर्मा ट्रेडिंग कम्पनी और

बर्मा की तीसरी लड़ाई

अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था । थीबा इस अवस्था को दवाने में असमर्थ साबित हुआ । अंग्रेजी सरकार ने उससे इन ब्रिटिश व्यापारियों के नुकसान की पूर्ति करने को कहा, परन्तु उसने इनकार कर दिया । इसके अतिरिक्त उसके

उपरी बर्मा मिला लिया गया

सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि वह फ्रांसीसियों और इटैलियनों के साथ पड़्यन्त्र रच रहा है । अन्त में जब उसने बर्मा ट्रेडिङ्ग कम्पनी पर किसी वजह से भारी जुर्माना कर दिया तो लार्ड डफ़रिन ने भी उसके विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी और एक अंग्रेजी सेना ने इरावदी की ओर कूच कर दिया । मंडाले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और बर्मा के राजा को भारत भेज दिया गया । सन १८८६ की जनवरी में ऊपरी बर्मा (Upper Burma) को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी गई ।

उसी साल ग्वालियर के महाराजा सिंधिया को उसका क़िला वापिस दे दिया गया । यह क़िला गदर के ज़माने से अंग्रेजों के पास था । सन १८८७ में महारानी विक्टोरिया के जुवली शांतिपूर्ण शासनकाल का पचासवां वर्ष आरम्भ हुआ । भारत में इस अवसर पर रायल जुवली बड़े हर्ष और आनन्द से मनाई गई ।

लार्ड डफ़रिन के शासन काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना

हुई। सन् १८८५ में बम्बई में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इस संस्था की स्थापना का श्रेय इण्डियन मि० लूम को है, जो स्वयं भी किसी ज़माने में नेशनल कांग्रेस भारत-सरकार का एक अफसर (सिविल सर्वेंट) रह चुका था। इस संस्था के अन्य उद्देशों में से, बाद के एक प्रेज़ीडेंट के शब्दों में, “राष्ट्रीय एकता को उन भावनाओं को विकसित और प्रकृत रूप देना था, जिसका जन्म लार्ड रिपन के स्मरणीय शासन काल में हुआ था।” कांग्रेस के इस प्रेज़ीडेंट ने कहा था कि हम ब्रिटेन के पूर्ण भक्त हैं, ब्रिटेन ने भारत में शांति स्थापित की है, रेलें बनाई हैं और पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा देश को असीम लाभ पहुँचाया है। परन्तु हम यह चाहते हैं कि भारतीय शासन प्रबन्ध में हम अपने उचित और स्वाभाविक अधिकार प्राप्त करें। लार्ड डफ़रिन इस नवान संस्था का विरोधी नहीं था, अपितु उसने इसे भारतीय दृष्टिकोण से परिचित होने का उत्तम साधन समझा। उस समय से अब तक कांग्रेस ने अनेक बार अपने उद्देशों में परिवर्तन किया है और तदनुसार उसके प्रति सरकार की नीति भी बदलती रही है। धीरे-धीरे यह संस्था देश की राजनीति में बहुत शक्तिशाली बन गई।

सन् १८८४ में आर्य समाज के, जिसे सन् १९११ की जनगणना की रिपोर्ट में गत अर्धशताब्दी का सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन कहा गया है, प्रवर्तक और हिन्दू धर्म के स्वामी दयानन्द महान् सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती का और आर्य समाज देहान्त हुआ। केवल संख्या की दृष्टि से

आर्य समाज का स्थान बहुत ऊंचा नहीं है, परन्तु सर चार्ल्स इलियट के शब्दों में "आर्य समाज अपने संगठन की पूर्णता और चत्कृष्टता के लिये विख्यात है।" इसने अब तक देश में सामाजिक सुधार और शिक्षा सम्बन्धी बहुत से कार्य किए हैं,—विशेष कर पंजाब और संयुक्त प्रांत में।

लार्ड लैसडाउन (१८८८-१८९४)—नए वायसराय, लैन्सडाउन ने अपना अधिक ध्यान सीमान्त प्रदेशों की रक्षा की ओर लगाया। उसने अमीर अब्दुर्रहमान के साथ सीमा प्रांत की रक्षा कुछ बातों के सम्बन्धमें सफाई करने के लिए सर मार्टि-मर ड्यूरेण्ड की अधीनता में काबुल को एक मिशन भेजा। मार्टिमर अपने उद्देश में पूर्ण सफल हुआ और उसने अफ़ग़ानिस्तान की दक्षिणी और पूर्वीय सीमाओं को निश्चित करने का प्रबन्ध किया। अमीर के शुल्क में काफी वृद्धि कर दी गई, जिससे दोनों राज्यों की मित्रता और भी अधिक घनिष्ट होगई।

इस वायसराय के शासन काल में, आसाम की सरहद पर, कछार के पूर्व में अवस्थित मनीपुर नाम की रियासत में कुछ अशान्ति पैदा हुई।

सन् १८६२ में आसाम के चीफ़ कमिश्नर और उसके दल को मनीपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ के राजा को गद्दी से उतार कर अण्डेमान भेज दिया गया। इस विद्रोह में जिन्होंने मुख्य भाग लिया था, उन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद

राजवंश की दूर की रिश्तेदारी का एक लड़का गद्दी पर बैठाया गया और उसके वालिग होने तक रेजिडेण्ट को उसका रक्तक बनाया गया ।

इण्डियन कौन्सिल ऐक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार प्रांतीय कौन्सिलों और इम्पीरियल कौन्सिल में गैर सरकारी

इण्डियन
कौन्सिल ऐक्ट
सन १८९२

सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और यूनिवर्सिटी और अन्य लोकल संस्थाओं को, जिनमें म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी थे, अपने सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया । ये सदस्य लोक-

हित के सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते थे । उन्हें बजट पर वृहत् करने का भी अधिकार दिया गया—परन्तु कुछ प्रतिबन्धों के साथ ।

लार्ड एल्गिन (१८९४ से १८९९)—सन १८६४ में लार्ड लैंसडाउन की जगह पर द्वितीय वायसराय के पुत्र लार्ड एल्गिन को नियुक्त किया गया । उसने भी अपने पूर्ववर्ती शासक की भांति सीमान्त सम्बन्धी समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दिया । एक ओर बर्मा और दूसरी ओर चीन तथा स्याम के बीच की सीमान्त रेखा निश्चित कर दी गई । एक सन्धि के अनुसार ब्रिटिश और रूसी राज्यों की सरहदा को कायम कर दिया गया ।

एक कमोशन द्वारा अफ़गानिस्तान की सीमा भी निश्चित कर दी गई । उत्तर पश्चिम सीमा के उस पार चित्राल में एक सेना भेजी गई । वहां अशान्ति फैल रही थी और उससे उत्तर भारत में भी अशांति उत्पन्न होजाने का भय था ।

इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया । दो वर्ष बाद अफ़रीदियों को दमन करने के लिए सेना भेजी गई । उन्होंने ब्रिटिश सेना

पर हमला कर दिया था और खैबर के दर्रे को टीरा की लड़ाई रोक रक्खा था । इन लोगों को भगा दिया गया, तथापि वे पूरी तरह काबू में नहीं आए । यह लड़ाई टीरा की लड़ाई कहलाती है ।

सन १८६५ में वर्षा कम हुई और सन १८६६ में और भी कम । परिणाम यह हुआ कि पुनः एक भयङ्कर अकाल पड़ा, जिसका प्रभाव मध्य प्रान्त और संयुक्त प्रान्त पर सबसे अधिक

अकाल और
महामारी

था, परन्तु अन्य प्रान्त भी उससे बचे नहीं रहे थे । इस अकाल का सामना करने की बहुत कुछ कोशिश करने पर भी साढ़े सात लाख

भारतीय भूख से तड़प तड़प कर मर गए । अभाग्य से यह विपत्ति अकेली नहीं आई । उसी साल बम्बई में गिल्टी का प्लेग फैल गया । भारत में यह विल्कुल नई बीमारी यूरोप से ही आई थी । सरकार ने लोगों की दृढ़ धारणाओं का विचार न करके प्लेग को दवाने की कुछ ऐसी कोशिशें कीं, जिन्हें लोगों ने शक और अविश्वास की निगाह से देखा और इसके बदले में अनेक अराजकतापूर्ण अपराध—विशेषकर बम्बई प्रेज़ीडेन्सी में—किए गए । सरकारी कर्मचारी बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी, इस संक्रामक रोग को बढ़ने से रोक न सके और उधर जनता इसका दोष अधिकारियों के मत्थे मढ़ती रही । इस प्रकार लार्ड एलिंगन के शासनकाल के अन्तिम भाग में राजनीतिक अशान्ति बहुत रही ।

प्रश्न

१. वर्मा के तीसरे युद्ध का संक्षिप्त विवरण लिखो ।
 २. इण्डियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ ? उसके उद्देश क्या थे ?
 ३. निम्नलिखित विषयों पर नोट लिखो—
 - (अ) पंजदेह का मामला ।
 - (ब) टीरा की लड़ाई ।
 - (द) १८९२ का इण्डियन कौन्सिल ऐक्ट ।
-

सत्रहवां अध्याय

लार्ड कर्ज़न, लार्ड मिन्टो और लार्ड हार्डिंग

लार्ड कर्ज़न (१८९२-१९०५)—लार्ड वैन्टिक के समय से लेकर, लार्ड लारेंस को छोड़ कर जितने गवर्नर जनरल या वायसराय आए, उनमें से एक को भी कार्य भार लेने से पूर्व भारत की अवस्था या एशिया की जातियों और समस्याओं से जानकारी नहीं थी। इस बात में लार्ड एल्गिन के वाद का गवर्नर जनरल अपवाद स्वरूप था। शासन भार ग्रहण करने से पहले दस वर्षों तक वह एशिया के विभिन्न प्रदेशों में घूम फिर कर भारत के निवासियों के रहन सहन, आचार व्यवहार और रीति-

रिवाजों का अध्ययन करता रहा था। इसके

वायसराय पद अतिरिक्त वचपन ही से वायसराय बनने की

पर कर्ज़न उसकी बड़ी आकांक्षा थी और उसने अपनी

की नियुक्ति तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा अपने को पहले ही से इस

कार्य के लिए तैयार कर लिया था। जब उसकी नियुक्ति की घोषणा

निकली तो यह कहने वाले लोगों की कमी नहीं थी कि 'इस

उपाधि दी गई और उसे उस ही भारी पेंशन नियम रूप से वही मिलती रही ।

तिब्बतियों ने भारत के साथ किसी तरह का सम्बन्ध रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और इन दिनों उन्होंने ए

रूसी दूत का लासा में स्वागत किया था । इस कारण तिब्बत का तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए ब्रिटिश सेना भेज

गई, पर उस धावे का परिणाम केवल भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करने और लासा—जो इनने दिनों में अगम्य था—तक पहुँच

पाने के सन्तोष के अतिरिक्त और कुछ न हुआ । ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत के ऊपर चीन का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया । चीन के

प्रजातन्त्र राज्य स्थापित होने के समय से तिब्बत फिर स्वाधीन हो गया है । लार्ड कर्जन ने फारस की खाड़ी में ब्रिटिश हितों की

रक्षा की आयोजना की । इस खाड़ी के किनारे फारस और उसके द्वीपों पर अधिकार करने के लिए अनेक

विदेशी शक्तियाँ प्रयत्न कर रही थीं ।

२२ जनवरी सन १६०१ को रावी विक्टोरिया अपने दीर्घ

और यशस्वी शासन के बाद वृद्धावस्था में परलोक सिधारी । इस पर सब ओर बड़ा

शोक मनाया गया । उनके बाद प्रिंस आफ वेल्स एडवर्ड सप्तम के नाम से गद्दी पर बैठे ।

एडवर्ड का राज्याभिषेक उत्सव दिल्ली के एक विशाल दरबार में सन १६०३ के जनवरी मास में मनाया गया ।

दरबार मे सम्पूर्ण भारतीय नरेश और अन्य सम्मान्य व्यक्ति स्थित हुए थे ।

आन्तरिक शासन प्रबन्ध—आन्तरिक शासन मे भी ई कर्जन ने अनेक योजनाओं को काम मे लाना आरम्भ किया । पुलिस महकमे के कर्मचारियो का वेतन बढ़ाया गया और रगरूटो की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । उसने जितने आर्थिक सुधार किए, उनमे तीन सब से अधिक महत्वपूर्ण सुधार पौड की कीमत पन्द्रह रुपया निश्चित कर देना, माननीय गोखले के कहने पर नमक-
 आर्थिक व्यवस्था कर घटाना और छोटी छोटी आमदनियों को इनकम टैक्स से मुक्त कर देना था । भारत के सानो की दशा मे सुधार करने के लिए उसने कर लगाने पर कर सत्रह में सुविधा करने वाले अनेक नियम बनाए । अने व्यापारिक संघों को प्रोत्साहन दिया, जो आजकल इतने विस्तृत और शक्तिशाली बन गए हैं । साथ ही लगान उसने सिंचाई का विस्तार करने की क्रमवद्ध योजना की । उसने एक काम यह किया कि सन १६०० में पंजाब स्वामित्व विधान (Panjab Land Alienation Act) जारी कर दिया, जिसके द्वारा अनेक काश्तकार जातियों से गैर काश्तकारों को ज़मीन खरीद सकता गैर-
 पंजाब ऐलीए-
 श न ए क ट कानूनी कर दिया गया । इस विधान का उद्देश्य कर्ज के लिए ज़मीन को ज़मानत रखने में बाधा

Act) जारी किया और पुरातत्वान्वेषण विभाग (Archaeological Department) भी कायम किया। इस विभाग ने अब तक प्राचीन इतिहास के चिन्हों की रक्षा करने और सुदाई आदि द्वारा अनुसंधान करने में बहुत कुछ काम किया है।

कर्जन की अवधि सन १९०४ के अप्रैल में समाप्त होती थी, परन्तु उसने अभी कुछ अन्य भी विशेष कार्य करने थे। अतः उसकी अवधि दो वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई।

इस अवधि में उसने जो सब से अधिक उल्लेखनीय काम किया वह वंगभंग था। लार्ड कर्जन का विश्वास था कि इतने बड़े प्रांत का शासन-प्रबन्ध एक प्रान्तीय सरकार के लिए बहुत भारी सिद्ध होता है, इसलिए उसने सन १९०५ के अक्तूबर मास में 'आसाम और बङ्गाल' नामक नया प्रांत बना दिया। इस प्रांत में सारा आसाम और बङ्गाल के पन्द्रह जिले शामिल किए गए और इनका केन्द्र ढाका को रखा गया था। इस पर बङ्गालियों में विरोध भावना ने जोर पकड़ा।

उन्हें विश्वास था कि यह कार्य बङ्गाल के व्यापक आन्दोलन राष्ट्रीय संगठन को तोड़ने के लिए किया गया है। नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन जारी किया, जिसका उद्देश स्वदेशी वस्तुओं द्वारा विदेशी वस्तुओं का प्रचार रोकना था। इस आन्दोलन से देश भर में वैचैनी फैल गई और कहीं कहीं अराजकतापूर्ण अपराध भी किए गए।

इससे भारत में ब्रिटिश शासन नीति के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। नवीन भारतमन्त्री जॉन मारले ने भारतीय शासन व्यवस्था के सुधारों में अपनी पार्टी की उन्नतिशील नीति बरतने का निश्चय कर लिया था। भाग्यवश नवीन वायसराय लार्ड मिण्टो (भारत के सन् १८०७ से १८१३ तक के गवर्नर जनरल मिण्टो के परपोते) को भी, बिल्कुल स्वतन्त्र रूप से यह विश्वास हो चला था कि अब वह समय आ गया है जब कि भारत की शासन व्यवस्था में भारतीयों को भी उत्तरदायित्व के पद प्राप्त करने और राज्य संचालन में सहयोग देने का अवसर दिया जाय।

जिस समय शासन की नागडोर मिण्टो-मारले के हाथों में पहुँची, उस समय भारत में राजनीतिक आंदोलन जोर पकड़ रहा था। बंगभंग के विरुद्ध वायकाट का प्रचार खूब जोरों पर था। रूस के ऊपर जापान की विजय को पूर्व के उत्थानका लक्षण समझा गया और भारतीय लोकमत के नेताओं ने जापान की इस विजय द्वारा लोगों में यह भाव भरने का प्रयत्न किया कि एशिया के लोग यूरोपियन्स के मुकाबले में बिल्कुल गए बीते नहीं हैं। उधर इंग्लैंड में लिबरल पार्टी के अधिकार प्राप्त करने से भारतीयों के हृदयों में बड़ी बड़ी आशाएं जागृत हो उठी थीं। अतः इण्डियन नेशनल कांग्रेस का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जाता था। भारत की राष्ट्रीयता एक

राजनीतिक
अशांति

नया ही रूप धारण करती जा रही थी। अब वह सरकार के लिये क्रमशः अधिकाधिक असहनशील होती जा रही थी। पहले राष्ट्रीय नेता केवल शासन प्रबन्ध में अधिक भारतीय सहयोग ही मांगते थे, परन्तु अब कुछ ऐसे गर्म विचारों वाले लोग (Extremists) भी पैदा हो गए थे, जो केवल

नर्मदल और
गर्मदल

इन छोटी मोटी रियासतों से ही सन्तुष्ट नहीं थे और जो भारत के लिये पूरा स्वराज्य चाहते थे।

उसमें से कुछ तो लक्ष्य प्राप्ति के लिये भौतिक बल का व्यवहार करने के भी पक्ष में थे। यह भौतिक बल प्रयोग करने वाला दल एक ऐसा उत्तेजनात्मक आन्दोलन फैला रहा था, जिसके फलस्वरूप यूरोपियनो पर अनेक घातक आक्रमण किए जाने लगे थे। उस समय के अधिक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, जो माडरेट कहलाते थे और जो उचित तथा वैध उपायों से ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य चाहते थे, इस भौतिक शक्ति के व्यवहार से किसी तरह की सहानुभूति नहीं रखते थे। सन् १९०७ में सूरत की कांग्रेस में गर्म दल ने कांग्रेस में अपना बहुमत बनाने का प्रयत्न किया, परन्तु इसमें उन्हें सफलता न मिली, तब कांग्रेसी लोगों में वाद के कई वर्षों तक भी दो दल बने रहे। इनमें से एक दल गरम और दूसरा 'नरम' कहलाया जाने लगा। परन्तु भारत जन सेवक संघ के संस्थापक गोपालकृष्ण गोखले जैसे त्यागी विद्वान् के प्रभावशाली नेतृत्व में कांग्रेस माडरेट ही बनी रही। परन्तु गर्म दल ने अपना प्रयत्न बन्द नहीं किया और दूसरी ओर क्रांतिकारी लोग अपने हत्या के प्रयत्न भी उसी तरह करते रहे।

इस प्रकार मिण्टो को दो कर्तव्य पूरे करने थे । एक ओर उसे बढ़ती हुई विद्रोह शक्ति को कुचलना था, दूसरी ओर वह भारत सचिव से इस बात में भी सहमत था कि इस अराजकता और विद्रोह की मौजूदगी में भी हमें शासन-सुधार की नीति व्यवहार में लानी ही चाहिए । मिण्टो और मारले दोनों को माडरेटों के सहयोग पर भरोसा था, जो उनके कथन के अनुसार भारत के बुद्धिविवेक के प्रतिनिधि थे । जहां क्रान्तिकारी प्रयत्नों को दबाने के लिए मिण्टो ने कई कानून बनाए, वहां १७ दिसम्बर सन १९०८ को मिण्टो-माले सुधारों की घोषणा की गई और सन १९०८ में उन्हें इण्डियन कौन्सिल्ज़ ऐक्ट के नाम से पास कर दिया गया । इस ऐक्ट के अनुसार इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल और प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौन्सिलों का निर्माण किया गया और प्रांतीय कौंसिलों में गैर सरकारी दल का बहुमत कर दिया गया । जातिगत पृथक् निर्वाचन-प्रथा (Separate Communal Electorate) अमल में लाई गई । कौंसिलों के अधिकारों में वृद्धि की गई । वायसराय की कार्यकारिणी समिति (Executive Council), प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों (Provincial Executive Councils) और इण्डिया आफिस वाली भारतमन्त्री कौन्सिल में भारतीय सदस्य भी भरती किए गए । इन सुधारों ने यद्यपि माडरेटों को सन्तुष्ट कर दिया, परन्तु गर्म दल वालों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके प्रयत्न

दमन और
रियायते

मिण्टो-माले
सुधार

उसी तरह जारी रहे ।

लार्ड हाडिंग (१९१०-१९१३)—लार्ड मिन्टो के बाद लार्ड हाडिंग आया, जो भारत में सिस्त्वों के साथ पहला युद्ध करने वाले गवर्नर जनरल हाडिंग का पोता था । यह अपने देश का बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था और उसने भारतीय भावनाओं के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई ।

सन १९१० का
राज्याभिषेक
दरवार

अब तक किसी ब्रिटिश सम्राट् ने अपने शासनकाल में भारत में पदार्पण नहीं किया था । सन १९११ में सम्राट् जार्ज दिल्ली के एक विशाल राज्याभिषेक दरवार में सम्राज्ञी सहित पधारे, वहां उन्होंने राजाओं और भारतीय जनता से भेटे स्वीकार की । इस देश में सम्राट् और सम्राज्ञी का बड़े उत्साह से स्वागत किया गया । यह विशाल दरवार दिल्ली में १२ दिसम्बर सन १९११ को हुआ था, जिसमें ८०,००० आदमी एकत्रित हुए थे । सजावट और तडक-भड़क उस अपूर्व अवसर के अनुरूप ही थी ।

सम्राट महोदय ने इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं । भारत की राजधानी कलकत्ते से हटाकर दिल्ली लाई गई । बङ्गाल के दोनो भागों को पुनः सम्मिलित कर दिया गया तथा विहार और उड़ीसा नाम का एक नया सूबा बनाया गया । आसाम का भी एक नया सूबा बना । इस प्रकार बगभंग के घावों की पूरी तरह चिकित्सा कर दी गई और वह असन्तोष शान्त हो गया ।

इम्पोरियल सरकार के लिए एक नया शहर बसना

आवश्यक था। आरम्भ में इसके लिए ४०,००,००० पाँड व्यय का अन्दाज़ा किया गया था, परन्तु वास्तविक व्यय नवीन दिल्ली इससे कहीं अधिक हुआ है। नवीन दिल्ली (या रायसीना) का प्रमुख भाग कुछ वर्ष पूर्व ही बन कर समाप्त हुआ है। वायसराय ने नई राजधानी में सन् १६१२ के दिसम्बर में धूम-धाम के साथ प्रवेश किया। जिस समय यह शानदार जलूस चाँदनी चौक में से धीरे धीरे गुज़र रहा था, उस समय वायसराय के हाथी पर एक बम फेका गया। भाग्य से लार्ड हाडिंग के प्राण लेने का प्रयत्न सफल न हुआ। हाँ, वे घायल बहुत बुरी तरह हुए, परन्तु इस घटना से लार्ड हाडिंग के हृदय की विशालता और लेडी हाडिंग की धीरता का सबूत मिल गया। वायसराय ने दमननीति प्रहण करने के बजाय इस आक्रमण के घावों से अच्छा होते ही कौन्सिल में मर्मस्पर्शनी अपील की—“मैं अपने को और लेडी हाडिंग को पुलिस की अपेक्षा लोगों के हाथों में सौंपना अधिक पसन्द करता हूँ।” अपने इस भाषण की बदौलत वह भारत में और भी अधिक प्रसिद्ध हो गए।

दक्षिण अफ्रीका में भारतवासी—सन् १६१३ में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार एशियावासियों से आरेज़ फ्री स्टेट में व्यापार, खेती करने या कोई निजी सम्पत्ति बनाने की अनेक सुविधाएँ हटीं गई थीं। इससे स्वभावतः ही भारत में घोर उत्तेजना फैली। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों ने महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी के नेतृत्व में तोत्र

परन्तु अहिंसात्मक आन्दोलन शुरू किया। लार्ड हाडिङ्ग ने भारत

हाडिङ्ग की
सहायता

के इस आन्दोलन का अपनी प्रसिद्ध वक्तृता द्वारा जोर से समर्थन किया—“भारत की गहरी और प्रज्ज्वलित सहानुभूति, और न सिर्फ भारतीयों

की ही वल्कि मेरे जैसे भारत के हितैषियों की सहानुभूति, दक्षिण अफ्रीका के इस अन्यायपूर्ण और ईर्ष्यामूलक कानून के विरुद्ध प्रयत्न करने वाले देशभक्तों के आन्दोलन के साथ है।”

भारत सरकार के प्रधान व्यक्ति के द्वारा अफ्रीका-सरकार की फार्मवाई के खिलाफ ऐसे सनसनी फैलानेवाले विरोध के प्रकट करने का फल अच्छा सिद्ध हुआ। एक जांच कमेटी के फलस्वरूप वहां इण्डियन रिलीफ ऐक्ट पास किया गया और मित्रता प्रदर्शित करने वाले अन्य आश्वासन भी दिए गए।

महायुद्ध—सन १९१४ में यूरोपियन महायुद्ध छिड़ गया, जिसमें शीघ्र ही इङ्ग्लैंड भी बुरी तरह फँस गया। यद्यपि इस युद्ध के कारण बहुत गहरे थे और यूरोप भर में इस युद्ध की बरसों से तैयारी हो रही थी, तथापि यह आग पहिले पहल सर्बिया में लगे और थोड़े ही दिनों में सारे यूरोप में फैल गई। ११ नवम्बर सन १९१८ को जर्मनों की हार के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई। इङ्ग्लैंड ने भी युद्ध में भाग लिया था। इस महान युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की युद्ध की विजय का श्रेय सब से पहले दो आदमियों को मिलना चाहिए। एक तो लायड जार्ज, जिसने अपनी स्फूर्ति और आशावादिता से ब्रिटिश जनता में जीवन बनाए रखा और

जो उन खतरे के दिनों इंग्लैण्ड के सम्मिलित मन्त्रिमण्डल का मुखिया था। दूसरा व्यक्ति मित्र शक्तियों का कमाण्डर मार्शल फौश है, जिसका प्रत्याक्रमण एक अप्रतिम आघात था। इस विश्वव्यापी युद्ध की घटनाओं का उल्लेख न करके हम यहां पर इस महायुद्ध में भारत ने जो सहयोग दिया, केवल उसी का बहुत संक्षेप में वर्णन करेंगे। संसार के इतिहास में इससे बड़ा और कोई युद्ध नहीं हुआ।

जर्मनों का विश्वास था कि युद्ध छिड़ते ही भारत में विद्रोह और उत्तेजना की आग लग जायगी। परन्तु उनका यह विश्वास शीघ्र ही भ्रम सिद्ध हुआ। इसके विपरीत सम्पूर्ण भारत ने संगठित

होकर अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़े से बड़े बलिदान किए। लाखों वीर भारतीय फ्रान्स का भाग के युद्धक्षेत्रों में वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए।

वास्तव में इस महायुद्ध के छिड़ने से भारतवासियों और देशी राजाओं की राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इस महायुद्ध में २०,००,००० भारतवासियों ने भाग लिया। वे फ्रान्स, फ्लैण्डर्स, मैसीडोनिया, मिथ्र, पैलेस्टाइन और मेसोपोटामिया के मैदानों में अपने ब्रिटिश सहयोगियों के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर शत्रु से लड़े। भारत के विरोधी से विरोधी दल ने भी इस युद्ध में सरकार का पूरा साथ दिया। रुपये पैसे के मामले में देशी राजाओं और जनसाधारण ने बड़ी बड़ी राशियां देने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त भारत ने दो अन्य देशों में

भी अपनी सेनाएँ धावे के लिए भेजों, एक जर्मन ईस्ट अफ्रीका के विरुद्ध और दूसरी मैसोपोटामिया में तुर्कों पर आक्रमण करने के लिए । भारत की व्यवस्थापिका सभा ने सर्वसम्मति से इस अवसर पर इंग्लैण्ड को एक अरब रुपया दान में दिया ।

प्रश्न

१. लार्ड कर्जन के व्यक्तित्व पर एक नोट लिखो ।
२. वग भंग के आन्दोलन का संक्षेप में वर्णन करो ।
३. लार्ड कर्जन के नए कार्य क्या क्या थे ?
४. मिष्टो मारले रिफार्म स्कीम के सम्बन्ध में तुम क्या जानते हो ?
५. लार्ड हार्डिंग भारत में सर्वप्रिय कैसे बने ?
६. निम्नलिखित पर नोट लिखो—

सन १९११ का दरवार, नई दिल्ली, दक्षिण अफ्रीका के भारतीय और यूरोपियन महायुद्ध ।

अठारहवां अध्याय

लार्ड चैम्सफोर्ड, लार्ड शीडिंग और लार्ड इरविन

(सन १९१६ से मई १९३२ तक)

लार्ड चैम्सफोर्ड (१९१६ से १९२१)—यूरोपियन महायुद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था कि लार्ड हाडिंग को अपने शासनकाल की अवधि समाप्त हो जाने के कारण इंग्लैंड लौट जाना पड़ा। नया वायसराय चैम्सफोर्ड भारत में प्रत्यक्षतया यही उद्देश्य लेकर आया था कि वह इस देश से महायुद्ध में मित्र-राष्ट्रों को अधिकतम सहायता दिलाने का प्रयत्न करेगा। अतः उसके आते ही खूब जोरशोर से फौजों की नई भरती की जाने लगी और युद्ध-व्यय के लिए धन एकत्र किया जाने लगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतवर्ष ने युद्ध-व्यय का दस करोड़ पाँड चुकाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। सन १९१७ की इम्पीरियल युद्धपरिषद् और युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद सन

१९१६ की शान्ति परिषद् में भारतीय प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया गया।

इसी बीच भारत के राजनीतिज्ञों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजनीतिक अशांति ने पहले के समान जोर पकड़ लिया था। इन दिनों सुप्रसिद्ध विद्वान और देश-स्वराज्य आंदोलन भक्त लोकमान्य तिलक और मिसेज़ वेसेण्ट के नेतृत्व में होमरूल आन्दोलन शुरू किया गया। इण्डियन नैशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सुधारों की एक संयुक्त योजना तैयार की। क्रमशः आन्दोलन ने बड़ा तीव्र रूप धारण कर लिया।

इसी अशान्त वायुमण्डल में सन १९१७ में भारत सचिव मि० ई० एस० माण्टेग्यू ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो एक नीतिज्ञ क शब्दों में “पार्लियामेंट में वर्क और १९१७ अगस्त की घोषणा पिट के ज़माने के बाद से तब तक की सारी घोषणाओं से सब से अधिक महत्वपूर्ण थी।” इस घोषणा का अभिप्राय था कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीत का उद्देश्य भारतीयों को शासनप्रबन्ध के प्रत्येक विभाग में केवल अधिकाधिक अवसर देना ही नहीं है, वरंच इस देश में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की क्रमशः स्थापना के लिए जनता के मत द्वारा व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की स्थापना करना भी है, जिससे भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उसका एक आवश्यक अंग बन जाए।

मि० माण्टेग्यू नवीन नीति को व्यवहारिक रूप देने के लिये वायसराय के परामर्श से एक रिपोर्ट तैयार करने भारत मे आए। देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं ने माण्टेग्यू चैम्स- उनको सहयोग दिया और उन्होने एक फोर्ड रिपोर्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की, जो सन् १९१८ मे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी गई।

उधर युद्ध के बाद भारत के शासन मे कोई बड़ा [परिवर्तन न आते देख कर स्वतन्त्रता प्रेमी भारतीय बड़े उद्विग्न हो रहे थे और अनेक नवयुवक मार्गभ्रष्ट होकर हत्या के तरीकों पर भी उतर आए थे। परियाम यह हुआ कि इन हिंसात्मक आक्रमणों के सम्बन्ध मे विचार करने के लिये भारत सरकार ने मि० रौलट की अधीनता मे एक विशेष कमेटी वैठाई। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दो ऐक्ट ऐसे पास किए जिनके द्वारा रौलट ऐक्ट सरकार को इन पड्यन्त्रों के विरुद्ध लगभग असीमित शक्ति प्राप्त हो गई। इन मसविदों को भारतीय लोकमत के विरोध करते रहने पर भी पास कर दिया गया। इसलिए भारतीय नेताओं ने उनकी बड़ी कटु आलोचना की। पर रौलट ऐक्ट इस पर भी वापिस नहीं लिया गया।

अब मोहनदास करमचन्द गांधी, जो अपने साधु जीवन के कारण लोगो मे महात्मा के नाम से सिद्ध हो चुके थे, भारत की राजनीति मे महत्वपूर्ण और निश्चयात्मक पार्ट

सत्याग्रह में
म० गांधी
का नेतृत्व

खेलने के लिए आगे बढ़े। उन्होने रौलट ऐक्ट का विरोध करने के लिये शान्तिमय और

अहिंसात्मक सत्याग्रह का आन्दोलन आरम्भ किया। इसके लिए उन्होंने सन् १९१६ की ६ अप्रैल को देश भर में सत्याग्रह दिवस मनाने की घोषणा कर दी। उस दिन देश भर में पूर्ण हलताल होनी थी। महात्मा गांधी के स्पष्ट आदेश के विरुद्ध भी दिल्ली, अहमदाबाद और बम्बई में दंगे हो गए। पंजाब और विशेष कर अमृतसर में भी उत्तेजना की लहर फैल गई। अमृतसर में क्रुद्ध जनता ने पब्लिक भवनों को जला डाला, पांच अंग्रेजों को मार दिया और एक अंग्रेज महिला का अपमान किया। पंजाब के अन्य भी अनेक स्थानों पर रेलवे लाइन और तार नष्ट कर दिए गए।

पंजाब के कुछ जिलों में मार्शल ला की घोषणा कर दी गई। इसके बाद ही जलियानवाला बाग की दुर्घटना हुई। सर वैलन्टाइन शिरोल कहता है—“एक अशुभ दिन उसने नार्शल ला (जनरल डायर ने) एक ऐसे जन-समुदाय पर बिना किसी भी चेतावनी के गोली की बौछार करना उचित समझा, जो उसके आदेश की अवज्ञा करके जलियानवाला बाग में एकत्र हुआ था। यह शासकों और शासितों के बीच में ऐसी वृणित खाई खोदना था कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में उस कलकपूर्ण दिन की कहानी की उपेक्षा नहीं की जा सकती।” अभाग्यवश इस भयंकर गोली कांड के बाद ही अमृतसर की गलियों में लोगों को पैदल रेंगने को बाधित किया गया। इन अदृशपूर्ण कार्यों की स्मृति भारतीय लोगों के दिमाग से कभी नहीं दूर

हो सकी। इन सब बातों से इस देश में जातिगत विरोध प्रज्ज्वलित हो गया। जब ड्यूक आफ कनाट सन १६२१ में भारत में पधारे तो उन्होंने भी कहा था—“अमृतसर की छाया सारे भारत पर फैल गई है।”

सन १६१६ के अन्त में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, माण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर “गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट” पास किया। इस ऐक्ट के द्वारा भारतवासियों को स्वराज्य की ओर एक और कदम बढ़ाने का अवसर दिया गया और प्रांतीय शासन में उन्हें कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। इन सुधारों का अधिक विस्तृत विवरण अगले परिच्छेद में किया जायगा।

विश्वज्यापी युद्ध के बाद शांति कायम करना सदैव बड़ा कठिन होता है। टर्की के साथ अंग्रेजों ने जिन शर्तों पर सन्धि की थी, उससे भारत के मुसलमानों के अप्रसर दल में घोर असहयोग विरोध की भावना का जन्म हो गया था। महात्मा गांधी ने पंजाब के अत्याचारों के साथ खिलाफत के सवाल को भी शामिल कर लिया और वहिष्कार की नीति अपनाकर ब्रिटिश शक्ति को अशक्त करने के लिए असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस वहिष्कार की चार मुख्य धाराएं थीं—

ई कौन्सिलों में भाग लेने के लिए कोई उम्मेदवार या निर्वाचक तैयार न हो। सब भारतीय हाथ के कते और बुने कपड़े ही पहने

कुछ लोगों ने अमीर के पास भारतीय जनता की अशांति और बेचैनी का अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण लिख कर सलाह दी कि यदि वह एक बार सीमा पर हमला कर दे, तो चारों ओर विद्रोह की आग लग जायगी। सन १६१६ की मई में अमीर की सेना ने भारतीय सीमा पार करके ब्रिटिश राज्य पर धावा बोल दिया। उनका सामना करने के लिए ब्रिटिश सेना ने खैबर पर धावा कर दिया और डफ़ा पर अधिकार कर लिया। जलालाबाद और काबुल पर बम गिराए गए। उत्तर की ओर अफ़गानों को बात की बात में हरा दिया गया। दक्षिण की ओर लड़ाई कुछ देर तक जारी रही, परन्तु यहाँ भी अफ़गानों को मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने स्वयं ही शांति के लिए प्रार्थना की।

— अगस्त सन १६१६ को, रावलपिण्डी में दोनों ओर से एक सन्धिपत्र लिखा गया। इस सन्धि के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने अमीर से वे सुविधाएँ वापिस ले लीं, जिनके द्वारा वह ब्रिटिश भारत के रास्ते अख़्त शख़्त मंगाना था। पैन्शन की पिछली रकम भी रद्द कर दी गई और भविष्य के लिए पैन्शन बन्द कर दी गई। इन सब के बदले में अफ़गानिस्तान को सब से बड़ी चीज़ यह मिली कि उसका अन्य देशों के साथ स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार मान लिया गया।

लार्ड रीडिंग (१९२१-१९२६)—सन १६२१ में लार्ड रीडिंग भारत का वायसराय नियुक्त हुआ। भारत में आने से पहले ही वह अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका

-या । इन अशांति के दिनों उसका अनुभव बड़ा काम आया । उसने अत्यन्त नाजुक और खतरनाक स्थिति को बड़ी योग्यता और सफलता के साथ बरा में कर लिया । उसका शासनकाल दृढ़ और प्रबल शासन का समय था ।

इधर असहयोग ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया था । अब तक महात्मा गांधी का जन साधारण पर बड़ा गहरा

प्रभाव स्थापित हो चुका था । प्रिंस आफ वेल्स के

असहयोग
वापिस ले
लिया गया ।

आगमन पर उन्होंने हड़ताल को घोषणा की । वह गुजरात के एक ज़िले वारदोली में सभी तरह के

कर देना अस्वीकार करके सत्याग्रह आरम्भ करने

के विषय में अपनी योजनाएं बना रहे थे । परन्तु कांग्रेस के कुछ

अनुयायी उचित रूप से अहिंसा व्रत का पालन न कर सके । चौरा-

चौरी नामक एक पुलिस के थाने पर क्रोध में आई हुई एक भीड़

ने धावा बोल दिया और पुलिस वालों को बुरी तरह मार डाला ।

इसके बाद और कई स्थानों पर भी कुछ दुर्घटनाएं हुईं । तब उस

महान् नेता ने शोक और पश्चात्ताप से अभिभूत होकर सत्याग्रह

के लिए देश की असमर्थता स्वीकार कर ली और कहा कि लोग

पूर्णांतः अहिंसा-व्रत का पालन नहीं कर सके, अतः सत्याग्रह अनि-

श्चित समय के लिए स्थगित किया जाता है ।

इस मौके पर सरकार ने भी दमन से काम लेना शुरू किया ।

अधिकांश राष्ट्रीय नेता, जिनमें महात्मा गांधी भी थे, गिरफ्तार

कर लिए । बहुत से स्वयंसेवकों को भी जेल में भेज दिया

गया। उधर टर्की के साथ संतोषजनक सन्धि हो जाने से मुसलमानों की उत्तेजना भी शांत हो गई।

इन्हीं दिनों देश में हिन्दू और मुसलमानों के भगड़े शुरू हो गए। कई स्थानों पर भयकर मारकाट हुई। कुछ समय के बाद कांग्रेस के अनेक नेता जेल से छूट कर बाहर आए। तब पंचमोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन का विचार काफ़ी समय तक के लिए स्थगित करके कौन्सिल में जाकर स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ने का निश्चय किया। सन १९२५ के फ़रवरी मास में महात्मा गांधी को भी सरकार ने छोड़ दिया।

लार्ड इरविन (१९२६-१९३१)—सन १९२६ के अप्रैल मास में लार्ड इरविन भारत के वायसराय बन कर आए। जिन दिनों वह बम्बई में उतरे, उन्हीं दिनों और मुस्लिम दंगा दिनों में कलकत्ता शहर के हिन्दू मुसलमानों में बड़ा भयकर दंगा हो गया। इसके बाद दंगों ने और भी भीषण रूप पकड़ा।

सन १९२७ के दिसम्बर में किसी धर्मान्ध मुसलमान ने दिल्ली में स्वामी अद्भुतानन्द को कत्ल कर दिया। इससे हिन्दू-मुस्लिम दंगों की ज्वाला और भी भभक उठी। लार्ड इरविन ने दोनों जातियों में सद्भाव बनाने के लिए बड़ा गम्भीर प्रयत्न किया।

इरविन अपने देश का एक कृषि-विशारद समझा जाता रहा है। भारत में आकर उसने यहाँ भी कृषि की उन्नति के लिए

एक शाही कमिशन नियुक्त करवाया ।

सन १९२८ में इंग्लैण्ड की सरकार ने भारत के शासन-विधान

की जाच पड़ताल करने के लिए सर जान साइमन

सा इ म न
कमीशन

की अध्यक्षता में एक शाही कमिशन नियुक्त किया ।

इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था ।

इस कारण इस देश के सम्पूर्ण राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार

किया । सन १९२६ के अन्त में इंग्लैण्ड में पुनः मजदूर सरकार

कायम हो गई और श्री रैम्से मैकडानल्ड के प्रधान-
वैजवुडवैन मन्त्रित्व में सर वैजवुड वैन भारत-सचिव नियुक्त हुए ।

इस भारत मन्त्री को भारतीय लोकमत के साथ गहरी सहानुभूति

थी । उधर लार्ड इरविन के हृदय में भी भारत और इंग्लैण्ड में

परस्पर मैत्री के भाव बनाए रखने की प्रबल आकांक्षा थी ।

उधर भारतीय नेताओं की ओर से भारत में शान्ति स्थापन

करने और राजनीतिक आन्दोलन के लिए परस्पर समझौता

करने का प्रयत्न जारी था । इसके लिए,

सर्वदल सम्मेलन और
कलकत्ता कांग्रेस

कांग्रेस के प्रयत्न पर अनेक राजनीतिक

दलों की तरफ से एक नेहरू कमेटी नियुक्त

की गई । इस कमेटी की रिपोर्ट में देश ने बड़ी दिलचस्पी ली ।

इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य को भारत का ध्येय मान

कर सब जातियों का एक पैकट बनाने का प्रयत्न किया गया था ।

सन १९२६ के दिसम्बर मास में कलकत्ता कांग्रेस ने नेहरू

रिपोर्ट के आधार पर अपना ध्येय, एक वर्ष के लिए, औपनिवेशिक

स्वराज्य कर लिया। परन्तु इस नेहरू रिपोर्ट से भी हिन्दू मुस्लिम सवाल हल न हो सका, तथापि इसके द्वारा इस सवाल को हल करने में मदद अवश्य मिली।

सन १९३० के सितम्बर मास में लार्ड इरविन इङ्ग्लैण्ड गए और लौट कर १७ नवम्बर १९३० के दिन उन्होंने एक घोषणा की, जिसका अंग्रेजी भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस घोषणा में यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत

मे अंग्रेजी शासन का उद्देश्य इस देश में पूर्ण
राउण्ड टेबल औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status)
कान्फरेंस कायम करना है। इस कार्य के लिए शीघ्र ही

इङ्ग्लैण्ड में एक राउण्डटेबल कान्फरेंस होने की घोषणा भी वायसराय ने की। इस कान्फरेंस में भारत के सम्पूर्ण दलों और हिन्दुओं के प्रतिनिधि तथा इङ्ग्लैंड की सरकार तथा अन्य दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होने थे। २४ दिसम्बर के दिन वायसराय ने भारत के चार महान नेताओं—महात्मा गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू और मुहम्मद अली जिन्हा—को इसी प्रश्न पर विचार करने के लिये दिल्ली में आमन्त्रित किया। इस बातचीत का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने राउण्ड टेबल कान्फरेंस में भाग लेने से इन्कार कर दिया, परन्तु देश के अन्य सम्पूर्ण दलों तथा संगठनों ने वायसराय की घोषणा का खुब स्वागत किया। वायसराय के साथ नेताओं की इस कान्फरेंस में सिर्फ एक दिन पहले

से विदेशी माल को दूकानों, विशेषकर अंग्रेजी कपड़े की दूकानों पर कांग्रेस के स्वयंसेवक पिकेटिंग करने लगे। वायसराय ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके पिकेटिंग आदि के खिलाफ क्रमशः १२ आर्डिनान्स जारी किए। परन्तु यह आन्दोलन मरने पर न आया। इससे देश के व्यापार तथा आयात निर्यात पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। सरकार ने कांग्रेस की वर्किंग कमिटी को गैर कानूनी करार दे दिया और बहुत से स्थानों की कांग्रेस कमेटियाँ तथा अन्य अनेक संघ गैर कानूनी बना दिए गए। सन १९३० के सम्पूर्ण वर्ष में यह आन्दोलन बहुत ज़ोरों पर रहा। कोई ६० हजार कांग्रेसी जेलों में भेजे गए। अनेक स्थानों पर पोलिस से जनता की मुठभेड़ भी हुई और पेशावर, शोलापुर आदि स्थानों पर तो हत्याकाण्ड भी हो गए। साथ ही कान्तिकारी लोगो ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं।

उधर इंग्लैण्ड में राउण्ड टेबल कान्फरेंस की पहली बैठक जारी थी, इसमें भारतवर्ष से कांग्रेस और व्यापार-राउण्डटेबल मण्डल को छोड़ कर बाकी सभी दलों के सरकार द्वारा नामजद प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस कान्फरेंस के द्वारा दोनों देशों को एक दूसरे के मनोभावों को समझने का बड़ा अच्छा अवसर मिला। भारतीय राजाओं ने भी इस कार्य में बड़ा प्रशस्तनीय सहयोग दिया और यह निश्चय किया गया कि निरूट भविष्य में ही एक भारत-संघ (Federation of Indian Empire) की शानदार स्थापना की जाय। परन्तु

भारत की अशान्ति के कारण कान्फरेंस का वायुमण्डल कुछ उदास-सा ही बना रहा ।

लार्ड इरविन और भारतसचिव वैजवुड वैन की यह हार्दिक इच्छा थी कि कांग्रेस भी देश के शासन-निर्माण में सहयोग दे । कर्नल वैजवुड वैन के अपने शब्दों में कांग्रेस 'हिन्दोस्तान की सब से बड़ी और सुसङ्गठित संस्था थी और भारतीय जनता पर तो कांग्रेस का ही सब से अधिक प्रभाव था ।' अतः सन १९३१ के फरवरी मास में सरकार ने सम्पूर्ण नेताओं को जेलों से छोड़ दिया और कांग्रेस वर्द्धि कमेटी पर से वन्दिश उठा ली । इधर ६

फरवरी के दिन पं० मोतीलाल नेहरू का देहान्त होजाने से देश भर में शोक के बादल छा गए । थोड़े दिनों बाद महात्मा गांधी दिल्ली में गए और

वायसराय से अनेक बार मिलजुल कर उन्होंने सरकार से समझौता कर लिया जो गांधी इरविन समझौता (Pact) के नाम से मशहूर है । इसके अनुसार कांग्रेस ने सत्याग्रह संग्राम वापिस ले लिया और

राउण्ड टेबल कान्फरेंस में सहयोग देने का वचन दिया । अपने इस्तेमाल के लिए नमक बनाने की इजाजत दे दी तथा सब आर्डिनान्स वापिस ले लिए । स्वदेशी प्रचार के उद्देश्य से शान्तिमय पिकेटिंग करने की भी अनुमति मिल गई ।

प्रश्न

१९११ में भारत के सहयोग पर नोट लिखो ?

१९२१ का असहयोग आन्दोलन किसने और क्यों की उन्नति का संक्षेप में वर्णन करो और लिखो कि किस प्रकार हुआ ?

दूसरे अफगान युद्ध का वृत्तान्त लिखो ।

१९३० का असहयोग आन्दोलन क्यों शुरू हुआ ? घटनाएँ लिखो ।

१५ अगस्त के दिन के बारे में तुम क्या जानते हो ?

उपडेटेवल कान्फरेंस की पहली बैठक के सम्बन्ध में तुम जो भी उल्लेख लिखो ।

सम्बन्धित पर नोट लिखो—

१९४७ का, जंगल का कानून, लाहौर कांग्रेस और सर्वदल सम्मेलन ।



उन्नीसवां अध्याय

लार्ड विलिंगडन और लार्ड लिन्लिथगो

(१९३१ से वर्तमान) लार्ड विलिंगडन १९३१-३६

सन १९३१ के एप्रिल मास में लार्ड इरविन का शासनकाल समाप्त हो गया। लार्ड इरविन अपने भारत प्रेम तथा उदारता के कारण इस देश में बहुत सर्वप्रिय हो गए थे। अतः वह जब इस देश से गए तो भारत में इस बात से बड़ा दुःख अनुभव किया गया। उन के बाद लार्ड विलिंगडन भारत के वायसराय बन कर आए। यह दो बार बम्बई और मद्रास प्रांत के गवर्नर रह चुके थे।

मार्च १९३१ के अन्त में करांची कांग्रेस ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया और राउण्ड टेबल कान्फरेंस के लिए

महात्मा गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया। सन १९३१ के सितम्बर मास में

महात्मा गांधी इंग्लैण्ड के लिए रवाना होगए।

महात्मा गांधी
इंग्लैण्ड गए

वहां उनका बड़ा आतिथ्य किया गया। परन्तु राउएड टेबल कान्फरेंस में महात्मा गांधी हिन्दू-मुस्लिम समझौता न करवा सके। शासन-विधान के सम्बन्ध में भी कांग्रेस और सरकार एकमत न हो सके।

इधर भारतवर्ष में भी अशान्ति के वादल पुनः दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस और सरकार दोनों को एक दूसरे के व्यवहार से सन्तोष न था। दोनों का कथन था कि दूसरा पक्ष समझौते का पालन नहीं कर रहा। इन्हीं दिनों पं० जवाहरलाल नेहरू ने यू०

पी० में लगान न देने का आन्दोलन जारी किया, महात्मा गांधी उधर सीमा प्रांत में अब्दुल गफ़ार खा का लालकुर्ती पुनः गिरफ्तार

आन्दोलन जारी था। परिणाम यह हुआ कि सरकार ने कांग्रेस के इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उधर महात्मा गांधी लण्डन से छुट्टी मिलते ही हिन्दोस्तान में पहुँचे, परन्तु तब तक यहाँ की स्थिति कावृ से बाहर हो चुकी थी। भारत में आते ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सलाह से पुनः असहयोग आन्दोलन जारी कर देने की घोषणा कर दी और अगले ही दिन, ५ जनवरी सन १९३२ की रात को वह गिरफ्तार कर लिए

गए। सरकार ने असहयोग आन्दोलन को दवाने आर्डिनान्सों की सब स्कीमे पहले ही बना रखी थीं। उसके अनुसार एक ही साथ चार आर्डिनान्स जारी

किए गए और भारतवर्ष भर की कांग्रेस कमेटियां गैर कानूनी करार दे दी गईं। कांग्रेस के अनुयाइयों ने इन आर्डिनान्सों को तोड़ना

शुरू किया। विदेशी माल के बहिष्कार के लिए पुनः पिकेटिंग आदि की जाने लगी। इस तरफ सत्याग्रह आन्दोलन फिर से जारी हो गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार करीब ६० हजार कामेसी इस आन्दोलन में जेलों में गए और १००० से ऊपर संस्थाएं गैरकानूनी करार दी गईं। कामेस के सैकड़ों मकान और लाखों रुपया जप्त किया गया।

इन्ही दिनों हिंसावादी क्रान्तिकारी प्रयत्नों ने भी जोर पकड़ लिया। विशेषतः बंगाल में ऐसे प्रयत्न बहुत होते रहे। वहां इन प्रयत्नों को रोकने के लिए सरकार ने एक आर्डिनान्स भी जारी किया और उसके नीचे हजारों गिरफ्तारियां हुईं।

असहयोग की समाप्ति—महात्मा गांधी कट्टर अहिंसावादी हैं। उनका विश्वास है। कि हिंसा से भारतवर्ष आजाद नहीं हो सकता और जब तक भारतवासियों में हिंसा के भाव रहेंगे, असहयोग आन्दोलन सफल न होगा। अतः देश में हिंसात्मक अनुयाइयों की बढ़ती को देख कर उन्होंने ने असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया।

बिहार का भूकम्प—जनवरी १९३४ ईसवी में बिहार में एक भयंकर भूकम्प आया, जिसमें हजारों आदमी मारे गए; लाखों मकान टूट गए और करोड़ों रुपयों का नुकसान

हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस और सरकार ने एक दूसरे के सहयोग से पीड़ित लोगों को बड़ी सहायता पहुँचाई।

क्वेटा का भूकम्प—बिहार भूकम्प की याद अभी ताज़ी ही थी कि सन् १९३५ के मई महीने के आखिर में भारतवर्ष पर एक और महाभयंकर विपत्ति आई। आधी रात के समय एक बहुत ही ज़बरदस्त भूकम्प ने सम्पूर्णा क्वेटा नगर को तबाह कर दिया। यह भूकम्प क्या था, खंड प्रलय था। दो मिनटों में सम्पूर्णा क्वेटा खडरातों का ढेर बन गया और करीब ५० हजार आदमी जान से मारे गए। इस अवसर पर सरकार तथा कोयटा की सेना ने भूकम्प पीड़ितों की बड़ी सहायता की। हिन्दोस्तान के सभी सूबों के लोगों ने कोयटा फण्ड में काफ़ी धन दान दिया।

सम्राट् पंचम जार्ज की सिल्वर जुवली और मृत्यु—सन् १९३५ में सम्राट् पंचम जार्ज की सिल्वर जुवली सम्पूर्णा अग्नेज़ी साम्राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। परन्तु उसके कुछ ही महीनों के बाद, २६ जनवरी १९३६ के दिन सम्राट् पंचम जार्ज का देहान्त हो गया। इस मौत से सारे साम्राज्य में शोक छा गया। सम्राट् पंचम जार्ज अपनी सम्पूर्णा अज्ञात में बहुत लोकप्रिय थे।

सम्राट् अष्टम एडवर्ड—पंचम जार्ज के बाद उनके बड़े

सिन्ध, उड़ीसा और ब्रह्मा—नए शासन सुधारों के अनुसार सिन्ध को बम्बई से और उड़ीसा को बिहार से जुदा कर दिया गया है। ये दोनों प्रान्त अब गवर्नरों के प्रान्त बन गए हैं। सन् १९३७ से बर्मा को भारतवर्ष से पृथक कर दिया गया है और अब बर्मा में भारतवासियों को विदेशी समझा जाने लगा है। सन् १९३८ में वहाँ बर्मियों और भारतवासियों में अनेक दंगे भी हुए।

नए सुधार—प्रथम एप्रिल १९३७ से भारतवर्ष में नए सुधारों का प्रारम्भ किया गया। इन सुधारों के अनुसार अब इस देश के ११ प्रान्तों में एक तरह का प्रान्तीय-स्वराज्य कायम होगया है और प्रत्येक प्रान्त की लैजिस्लेटिव असेम्बली के बहु-मत का नेता 'प्रधान मन्त्री' के नाम से अपने प्रान्त का शासन कर रहा है। गवर्नर उसके कामों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करता। कांग्रेस भी, इस नए शासन में पूरा सहयोग दे रही है और देश में पूर्ण शान्ति तथा व्यवस्था कायम है। सम्भवतः १९४० तक केन्द्रीय सरकार में भी सुधार जारी हो जायगे। यहाँ सघ-प्रणाली (फिडरेशन) जारी होगी।

पुत्र अष्टम एडवर्ड के नाम से बादशाह बने। अष्टम एडवर्ड को उनकी प्रजा शुरू ही से बहुत चाहने लगी थी, परन्तु श्रीमती सिम्पसन नाम की एक महिला से विवाह करने की इच्छा से उन्होंने १० दिसम्बर १६३६ को राजसिंहासन छोड़ दिया। अब उन्हें 'ड्यूक आफ विण्डसर' कहा जाता है।

लार्ड लिन्लिथगो—एप्रिल सन् १६३६ में लार्ड विलिंगडन का शासन-काल समाप्त हुआ और उनके बाद लार्ड लिन्लिथगो भारतवर्ष के वायसराय बन कर आए। भारतवर्ष का नया शासन-विधान बनाने के लिए जो पार्लियामैण्टरी कमेटी बनी थी, उसके प्रधान लार्ड लिन्लिथगो थे। वह भारतीय कृषि पर नियुक्त किए गए रायल कमीशन के भी प्रधान थे और इसी सिलसिले में वह भारतवर्ष में आए भी थे। इससे उन्हें भारतीय परिस्थिति से अच्छा परिचय है। लार्ड लिन्लिथगो भारत की गाँवों की दशा सुधारने तथा इस देश की खेती-वाड़ी उन्नत करने में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कई अच्छे बैल गाँवों को दान में दिये हैं। लार्ड लिन्लिथगो इस मुल्क में हरदिल अज़ीज़ बन गए हैं।

सम्राट् जार्ज छठे—अष्टम एडवर्ड के राजत्याग के बाद उनके छोटे भाई जार्ज षष्ठ के नाम से सम्राट् बने और १८ मई १६३७ को बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। सम्राट् जार्ज छठे भी अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय बनते जा रहे हैं।

सिन्ध, उड़ीसा और ब्रह्मा—नए शासन सुधारों के अनुसार सिन्ध को बम्बई से और उड़ीसा को बिहार से जुदा दिया गया है। ये दोनों प्रान्त अब गवर्नरो के प्रान्त बन हैं। सन् १९३७ से बर्मा को भारतवर्ष से पृथक कर दिया है और अब बर्मा में भारतवासियों को विदेशी समझा जाने है। सन् १९३८ में वहाँ बर्णियों और भारतवासियों में अनेक भी हुए।

नए सुधार—प्रथम एप्रिल १९३७ से भारतवर्ष में नए सुधारों का प्रारम्भ किया गया। इन सुधारों के अनुसार अब देश के ११ प्रान्तों में एक तरह का प्रान्तीय-स्वराज्य कायम किया है और प्रत्येक प्रान्त को लैजिस्लेटिव असेम्बली के बहु-सदस्यीय का नेता 'प्रधान मन्त्री' के नाम से अपने प्रान्त का शासन चला रहा है। गवर्नर उसके कामों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करता। प्रत्येक प्रान्त में एक सभ्यता-संरक्षण समिति है और देश में शांति तथा व्यवस्था कायम है। सम्भवतः १९४० तक केंद्रीय सरकार में भी सुधार जारी हो जायेंगे। यहां संघ-प्रणाली (फेडरेशन) जारी होगी।

तीसवां अध्याय

भारत की शासन-व्यवस्था

भारतवर्ष के अर्वाचीन इतिहास के अन्त में ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का खाका खींचना भी आवश्यक प्रतीत होता है। विशेषकर आजकल के दिनों में जब कि शासन-विधान में परिवर्तन करने का प्रयत्न हो रहा है, शासन-व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ गया है।

भारत से ब्रिटिश सम्पर्क सन १६०० से आरम्भ हुआ। जब एलिज़ाबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को व्यापारिक सुविधाओं का अनुमतिपत्र प्रदान किया था। इन अधिकार-पत्रों में समय समय पर परिवर्तन परिवर्द्धन होते रहे हैं। सन १७६५ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापार-प्रधान संस्था रही है।

सन १७६६ में दीवानी का अधिकार मिल जाने पर कम्पनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासिका बन बैठी। उस समय

१८५८ तक कम्पनी अनेक प्रदेशों की शासक रही और अपना व्यवसाय और सुविधाएं छोड़ती चली गई।
 नी का भारत सरकार के कार्य में पार्लियामेंट ने सबसे पहले
 त्व सन् १७३ में हस्तक्षेप किया और सन् १७८४ में
 सन-परिषद् कायम की गई। सन् १७६३ के बाद प्रति
 ३ वर्षों के अन्तर से भारत के सम्बन्ध में पार्लियामेंट के
 ष्ट पास होते रहे। सन् १७९३ में भारत में व्यापार करने का
 पनी का एकाधिकार रद्द कर दिया गया और इस देश में व्या-
 र करने की सब को अनुमति हो गई। सन् १८५३ से सिविल
 षिस के लिये उम्मेदवार भरती किये जाने आरम्भ हुए और
 १८५७ के गद्दर के बाद से भारत का शासन कम्पनी के
 यो से ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया।

सन् १८५८ में सम्राज्ञी के घोषणापत्र के अनुसार इस देश
 शासन के लिए सम्राज्ञी के नाम पर एक भारत मन्त्री और
 १५ सदस्यों की एक कौंसिल नियत की गई।
 षरत सम्राट सन् १८६१ के दो कानूनों द्वारा गवर्नर जनरल
 ष शासन में की प्रबन्ध कारिणी समिति में हेरफेर किया गया,
 षान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिलों को पुनः सङ्गठित किया गया और
 र्ईकोर्ट स्थापित करने की व्यवस्था की गई। उस समय से बीसवीं
 षताब्दी तक भारत का पार्लियामेंटी व्यवस्थापन पेंचल छोटी
 षेटी बातों तक ही परिमित था। सन् १८६२ में लेजिस्लेटिव
 षौंसिलो का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया और उनके कुछ सदस्यों का

चुनाव भी होने लगा ।

इन सुधारों का मुख्य उद्देश भारत की व्यवस्थापिका सभाओं (Indian Legislative Councils) को अधिक प्रतिनिधि-

सत्तात्मक रूप देना था—जो अन्य उपायों के

मिण्टोमारले

अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाने, नामजद्गी

सुधार

के स्थान पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने

और वाद विवाद में सदस्यों को काफ़ी स्वतन्त्रता देने के रूप में व्यवहार में लाया गया । परन्तु क़ौसिलें इस समय तक भी केवल परामर्श ही दे सकती थीं । इस विषय में कोई उन्नति नहीं हुई थी ।

उत्तरदायित्वपूर्ण शासन—भारत की शासन व्यवस्था के विकास का दूसरा भाग उत्तरदायित्वपूर्ण अथवा पार्लियामेंटरी सरकार के साथ सम्बन्ध रखता है । उत्तरदायित्वपूर्ण शासन से हमारा अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसकी प्रबन्ध-कारिणी समिति जनसाधारण द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की इच्छा का पालन करे । मिण्टोमारले सुधार स्कीम ने ब्रिटिश सरकार के शासन प्रबन्ध के ढांचे को हाथ नहीं लगाया था । लार्ड मारले और लार्ड मिण्टो दोनों ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की ओर किसी तरह का क़दम उठाने में साफ़ तौर से अपनी अस्वीकृति जाहिर कर दी थी । उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के विचारमात्र का भारतमन्त्री ने क्रोध के साथ खण्डन किया और इसके विषय में घोषणा की थी—“यदि मेरे अस्तित्व की अवधि सरकारों या शारीरिक रूप से बीस गुणा कर दी जाय तो भी यह मेरा लक्ष्य

एक क्षण के लिए भी न होगा।”

पर सुधारकों की अपेक्षा घटनाएँ अधिक प्रबल थीं। महा-
युद्ध ने भारत के विषय में अंग्रेजों के दृष्टिकोण
मौलिक-फोर्ड में परिवर्तन कर दिया था। जिस लक्ष्य का सन
सुधार १९०८ में जोरो के साथ खण्डन किया गया था उसी
कीसन की १९१७ में सरकारी तौर से घोषणा की गई।

प्रांतीय शासन-प्रबन्ध में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की
आवश्यकता मान ली गई। सरकार के अधिकारों और उत्तरदा-
यित्वों को प्रांतीय और केन्द्रित सरकारों में विभा-
द्वैधशासन जित किया गया और उनका नाम “केन्द्रित-विषय”
और “प्रांतीय विषय” रखा गया। “प्रांतीय विषयों” के भी
दो भाग किए गए हस्तान्तरित (ट्रांसफर्ड) और सुरक्षित (रिज़र्व्ड)
विषय। रिज़र्व्ड विषयों में सिंचाई, जङ्गलात, पुलिस आदि शामिल
हैं और उनका सम्बन्ध सीधे गवर्नर की प्रबन्धकारिणी समिति
से होता है। शिक्षा, लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट, कृषि, स्वास्थ्य आदि
“ट्रांसफर्ड विषयों” में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन अमल में लाया
गया। ये विषय गवर्नर के शासन में रहेंगे और गवर्नर प्रांतीय
कौन्सिलों द्वारा चुने हुए उत्तरदायी मन्त्रियों के परामर्श से उन पर
शासन करेगा। यही प्रसिद्ध द्वैधशासन है जो सन १९१६ के ऐक्ट
द्वारा स्थापित किया गया था।

प्रांतीय कौन्सिलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई।
चुने हुए सदस्य कम से कम सत्तर फी सदी और सरकारी सदस्य

अधिक से अधिक वीस फ़ी सदी रक्खे गए । एक कौंसिल का जीवन तीन वर्ष तक के लिए रक्खा गया । प्रारम्भिक तीन वर्षों के बाद से कौंसिलों को अपना प्रोज़िडेण्ट स्वयं चुनने का अवसर दिया गया । कार्य और विधान में भी हम पार्लियामेण्टी शासन की ओर बहुत कुछ प्रवृत्ति पाते हैं । पर कौंसिलों के रहने पर भी कौंसिलों की दोषपूर्ण कार्यवाही को रोकने, आवश्यकता व्यय को मंजूर करने, और आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकार गवर्नर को सौंपा गया ।

केन्द्रित शासन प्रबन्ध में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन के लिए कुछ नहीं दिया गया । केन्द्रित व्यवस्थापिका सभाओं के दो विभाग बनाये गये । कौंसिल आफ़ स्टेट में ६० में केन्द्रीय शासन से ४० निर्वाचित सदस्य हैं । बड़ी व्यवस्थापिका सभा के १४० सदस्यों में से १०० निर्वाचित सदस्य होते हैं । बड़ी व्यवस्थापिका सभा अपना सभापति स्वयं निर्वाचित करती है । कौंसिल आफ़ स्टेट की साधारण अवधि पांच वर्ष है और बड़ी व्यवस्थापिका सभा की तीन वर्ष ।

इस महत्वपूर्ण ऐक्ट के अनेक संविधानों में भारतमन्त्री की कौंसिल में सुधार करना, इङ्गलैण्ड में भारत के एजेण्ट की हैसियत से काम करने के लिए हाई कमिश्नर की अन्य विधान नियुक्ति, सिविल सर्विस के विषय में विधान, भारत में पब्लिक सर्विस की भर्ती और संयमन के लिए पब्लिक सर्विस कमिशन (Public Service Commission) की

नियुक्ति उल्लेखनीय है।

मोंट-फोर्ट सुधारों की स्थापना—जिस समय भारत असद्व्योग के विषय और समुद्र में निम्न था, उसी समय नवीन शासन विधान की स्थापना हुई और सन् १६२१की फरवरी में ड्यूक आफ कनाट ने देहली में विधिपूर्वक लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली, कॉंसिल आफ स्टेट और चैम्बर आफ प्रिसेज को खोला। इस अवसर पर शाही सन्देश इन सार्वक शब्दों में अपनी परामर्श को प्राप्त हुआ—“कई वर्षों से, और सम्भवतः कई पुस्तों से देशभक्त और राजभक्त भारतवासी अपनी मातृ-भूमि के लिए स्वराज्य का स्वप्न देख रहे हैं। आज मेरे साम्राज्य के अन्दर तुम्हारे स्वराज्य और अन्य उपनिवेशों द्वारा उपभोग की जाने वाली स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक अनेक सुविधाओं और अत्यन्त विस्तीर्ण कार्यक्षेत्र का आरम्भ होता है।”

राउण्ड-टेबल कान्फ्रेंस—एक्ट में यह सविधान किया गया था कि हर दस वर्ष बाद एक शाही कमीशन, भारत में प्रचलित सुधारों की जांच करने और उत्तरदायित्व पूर्ण शासन के परिमाण को विस्तृत करने, सुधारने या रोक रखने के लिए नियुक्त किया जाय। फलतः एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके प्रधान सर जान साइमन थे।

इस कमीशन की रिपोर्ट तैयार होने के बाद इंग्लैण्ड में भारत के सम्पूर्ण दलों तथा हितों के प्रतिनिधियों को बुला कर एक गोलमेज कान्फ्रेंस की गई थी, इस कान्फ्रेंस की दो बैठकें

